

उत्तर प्रदेश

की

आर्थिक समीक्षा

1981-82



अर्थ एवं संख्या प्रभाग,
राज्य नियोजन संस्थान,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

विषय सूची

<u>अध्याय</u>	<u>पृष्ठ संख्या</u>
1—सामान्य आर्थिक स्थिति	1-11
2—कृषि एवं सम्बन्धीय व्यवसाय	12-16
3—उद्योग, खनिज एवं विद्युत	17-24
4—सड़क, परिवहन एवं संचार	25-30
5—सामाजिक सेवार्ये	31-34
6—धन शक्ति एवं सेवायोजन	35-38
7—प्रदेश की आर्थिक प्रत्याशार्ये	39
परिशिष्ट 1 "उत्तर प्रदेश के आर्थिक क्षेत्र"	40

NIEPA DC



D00990

- 542
352,1252
UTT- U

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sushant Park, Mayapuri, New Delhi-110016
DOC. No. D-990
Date.....22/2/84

अध्याय-1

सामान्य आर्थिक स्थिति

1.0—उत्तर प्रदेश की अर्थ व्यवस्था मुख्यतः कृषि जन्य है। राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद में आधे से अधिक अंश कृषि एवं सम्बन्धी खण्ड का है। वर्ष 1979-80 में पड़े भीषण सूखे के कारण प्रदेश की अर्थ व्यवस्था पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा किन्तु वर्ष 1980-81 में इसमें कुछ सुधार हुआ। राष्ट्र की कुल जनसंख्या में प्रदेश के लगभग 16 प्रतिशत अंश की तुलना में राष्ट्रीय आय में इसका योगदान केवल लगभग 11 प्रतिशत ही है। जनसंख्या की दृष्टि से यह प्रदेश राष्ट्र का सबसे बृहद् प्रदेश है किन्तु आर्थिक विकास के दृष्टि से यह पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आता है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय, औद्योगिक विकास, अवस्थापन सुविधाओं जैसे विभिन्न मानकों के आधार पर यह प्रदेश राष्ट्रीय स्तर से काफी पीछे है। आगामी अनुच्छेदों एवं परिच्छेदों में प्रदेश की सामान्य स्थिति एवं आर्थिक विकास संबंधी कार्य-कलापों का उल्लेख किया गया है।

1.1—प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल 294 हजार वर्ग कि० मी० भारत के सम्पूर्ण क्षेत्रफल का लगभग 9 प्रतिशत है। केवल मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं महाराष्ट्र राज्यों का भौगोलिक क्षेत्रफल ही इस प्रदेश से अधिक है। जनगणना 1971 के अनुसार इस प्रदेश की कुल जनसंख्या 883 लाख थी, जो वर्ष 1981 में बढ़कर 1109 लाख (अनन्तिम) हो गई। प्रदेश की कुल जनसंख्या में 53.0 प्रतिशत (588 लाख) पुरुष तथा 47.0 प्रतिशत (521 लाख) स्त्रियां थीं। इस सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि 1971-81 की अवधि में प्रदेश की जनसंख्या में 25.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो अखिल भारतीय स्तर पर हुई 24.8 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में प्रथम बार (1931 से) अधिक रही। इसके फलस्वरूप भारत की कुल जनसंख्या में प्रदेश की जनसंख्या का शतांश वर्ष 1971 में 16.1 से बढ़कर वर्ष 1981 में 16.2 हो गया और प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व 377 व्यक्ति प्रति वर्ग कि० मी०, वर्ष 1971 (300 व्यक्ति प्रति वर्ग कि० मी०) की तुलना में लगभग 25.7 प्रतिशत तथा वर्ष 1981 के राष्ट्रीय औसत घनत्व (221 व्यक्ति प्रति वर्ग कि० मी०) की तुलना में 70.6 प्रतिशत अधिक रहा। जनसंख्या के घनत्व की दृष्टि से केरल (654), पश्चिमी बंगाल (614) तथा बिहार (402) के पश्चात इस प्रदेश का चौथा स्थान रहा जब कि 1971 की जनगणनानुसार इसका पांचवा स्थान था क्योंकि उस समय उक्त राज्यों के अतिरिक्त तामिलनाडु में भी जनसंख्या का घनत्व प्रदेश के घनत्व से अधिक था।

1.2—उत्तर प्रदेश की आर्थिक क्षेत्रवार जनान्किकी संबंधी आंकड़े नीचे तालिका 1.1 में दर्शाये गये हैं।

तालिका 1.1

उत्तर प्रदेश के आर्थिक क्षेत्रों की जनसंख्या एवं घनत्व

क्रम संख्या	आर्थिक क्षेत्र	जनसंख्या ('000)		घनत्व (व्यक्ति प्रति वर्ग कि० मी०)	
		1971	1981	1971	1981
1	2	3	4	5	6
1	पर्वतीय क्षेत्र	3822	4815	75	94
2	पश्चिमी क्षेत्र	31314	39357	381	479
3	केन्द्रीय क्षेत्र	15743	19703	343	430
4	पूर्वी क्षेत्र	33171	41574	387	484
5	बुन्देलखण्ड क्षेत्र	4291	5437	146	185
	उत्तर प्रदेश	88341	110886	300	377

स्रोत :— भारतीय जनगणना 1971 व 1981 (अस्थाई आंकड़े)।

उक्त आंकड़ों से ज्ञात होता है कि 1971-81 की अवधि में बुन्देलखण्ड एवं पर्वतीय क्षेत्र की जनसंख्या में क्रमशः 26.7 प्रतिशत व 26.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, जो राज्य में हुई 25.5 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में काफी अधिक रही। केन्द्रीय क्षेत्र की जनसंख्या में यह वृद्धि अन्य आर्थिक क्षेत्रों की तुलना में सबसे कम (25.2 प्रतिशत)

हुई। सघनतम बसे पूर्वी क्षेत्र की जनसंख्या में 1971-81 के दशक में हुई 25.3 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में पश्चिमी क्षेत्र की जनसंख्या में 25.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रदेश की कुल जनसंख्या में पूर्वी क्षेत्र की जनसंख्या का अंश वर्ष 1971 के 37.6 प्रतिशत से घटकर वर्ष 1981 में 37.5 प्रतिशत तथा पश्चिमी क्षेत्र की जनसंख्या का अंश वर्ष 1971 के 35.4 प्रतिशत से बढ़कर 35.5 प्रतिशत हो गया। जब कि बुन्देलखंड, पर्वतीय तथा केन्द्रीय क्षेत्र की जनसंख्या का अंश प्रदेश की कुल जनसंख्या में वर्ष 1971 के अंश के अनुरूप ही रहा जो वर्ष 1981 में क्रमशः 4.9 प्रतिशत, 4.3 प्रतिशत तथा 17.8 प्रतिशत था।

1.3—वर्ष 1971-81 की अवधि में प्रदेश की जनसंख्या के घनत्व में 77 व्यक्ति प्रति वर्ग कि०मी० की वृद्धि हुई। इसके समक्ष पर्वतीय एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में यह वृद्धि केवल क्रमशः 19 तथा 39 हुई थी और इस प्रकार वर्ष 1981 में इन क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व क्रमशः 94 तथा 185 व्यक्ति हो गया। सघनतर बसे पूर्वी व पश्चिमी क्षेत्र की जनसंख्या के घनत्व में क्रमशः 97 व 98 व्यक्तियों की लगभग समान वृद्धि हुई जब कि केन्द्रीय क्षेत्र के घनत्व में 87 व्यक्तियों की वृद्धि हुई। इस प्रकार राज्य स्तर पर हुई वृद्धि की तुलना में इन तीनों आर्थिक क्षेत्रों की जनसंख्या के घनत्व में अधिक वृद्धि रही। परिणामतः वर्ष 1981 में पूर्वी, पश्चिमी व केन्द्रीय क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व क्रमशः 484, 479, 430 रहा और घनत्व की दृष्टि से ये क्षेत्र 1981 में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहे। इनके अतिरिक्त बुन्देलखण्ड क्षेत्र चतुर्थ व पर्वतीय क्षेत्र पांचवें स्थान पर रहे।

1.4—उत्तर प्रदेश के जनपदों का घनत्व के अनुसार आर्थिक क्षेत्रवार वितरण तालिका 1.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.2

उत्तर प्रदेश के जनपदों का घनत्व के अनुसार आर्थिक क्षेत्रवार वितरण

आर्थिक क्षेत्र	राज्य के औसत घनत्व से अधिक घनत्व वाले जनपद	राज्य के औसत घनत्व से कम घनत्व वाले जनपद
1	2	3
1—पर्वतीय	..	8
2—पश्चिमी	..	2
3—केन्द्रीय	..	1
4—पूर्वी	..	2
5—बुन्देलखण्ड	..	5
उत्तर प्रदेश	..	18

स्रोत—भारतीय जनगणना 1981 (अस्थायी आंकड़े)।

उपर्युक्त तालिका से विदित होता है वर्ष 1981 में प्रदेश के लगभग 67.9 प्रतिशत जनपदों में जनसंख्या का घनत्व प्रदेश के औसत घनत्व (377 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि०मी०) से अधिक रहा। पश्चिमी, केन्द्रीय एवं पूर्वी क्षेत्रों में ऐसे जनपद क्रमशः 44.7 प्रतिशत, 21.1 प्रतिशत व 34.2 प्रतिशत पाये गये। पर्वतीय एवं बुन्देलखंड क्षेत्र के सभी जनपदों में जनसंख्या का घनत्व प्रदेश के औसत घनत्व से कम पाया गया। इस क्रम में यह भी उल्लेखनीय है कि लखनऊ जनपद का घनत्व 798 प्रदेश के औसत घनत्व के दूने से भी अधिक लगभग 111.7 प्रतिशत अधिक रहा।

1.5—वर्ष 1971 तथा 1981 की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के अंश का आर्थिक क्षेत्रवार वितरण नीचे तालिका 1.3 में दिया गया है।

तालिका 1.3

उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत

क्रम संख्या	आर्थिक क्षेत्र	कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत		1971-81 में वृद्धि
		1971	1981	
1	पर्वतीय क्षेत्र	14.7	18.4	3.7
2	पश्चिमी क्षेत्र	18.3	23.8	5.5
3	केन्द्रीय क्षेत्र	17.4	21.4	4.0
4	पूर्वी क्षेत्र	8.2	10.7	2.5
5	बुन्देलखंड क्षेत्र	14.7	19.9	5.2
	उत्तर प्रदेश	14.0	18.0	4.0

स्रोत—भारतीय जनगणना 1971 व 1981 (अस्थायी आंकड़े)।

उक्त तालिका के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अंश वर्ष 1971 के 14.0 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1981 में 18.0 प्रतिशत हो गया। 1971-81 दशक में कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के शतांश की दृष्टि से पश्चिमी क्षेत्र, जो 1971 में सभी क्षेत्रों से आगे था, की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के शतांश में 5.5 की सर्वाधिक वृद्धि होने के कारण प्रथम स्थान पर तथा पूर्वी क्षेत्र, जो 1971 में सभी आर्थिक क्षेत्रों का अनुगामी था, के इस शतांश में न्यूनतम 2.5 की वृद्धि होने के कारण वर्ष 1981 में भी पांचवें स्थान पर यथावत् बना रहा। कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अंश पर्वतीय एवं बुन्देलखंड क्षेत्रों में वर्ष 1971 में 14.7 प्रतिशत के समान स्तर पर था, किन्तु वर्ष 1981 में बुन्देलखंड क्षेत्र की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का शतांश 19.9 तथा पर्वतीय क्षेत्र में मात्र 18.4 हो जाने के कारण बुन्देलखंड क्षेत्र तृतीय तथा पर्वतीय क्षेत्र चतुर्थ स्थान पर आ गया। केन्द्रीय क्षेत्र वर्ष 1971 के समान 1981 में भी द्वितीय स्थान पर बना रहा जहाँ नगरीय जनसंख्या वर्ष 1971 में 17.4 प्रतिशत तथा वर्ष 1981 में 21.4 प्रतिशत थी।

1.6 प्रदेश के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में साक्षरता का स्तर नीचे तालिका 1.4 में दिया गया है।

तालिका 1.4

1971-81 में उत्तर प्रदेश के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के साक्षरता प्रतिशत में वृद्धि

क्रम संख्या	आर्थिक क्षेत्र	साक्षरता प्रतिशत		1971-81 में साक्षरता प्रतिशत में वृद्धि
		1971	1981	
1	पर्वतीय क्षेत्र	31.0	39.4	8.4
2	पश्चिमी क्षेत्र	22.3	28.2	5.9
3	केन्द्रीय क्षेत्र	22.9	28.5	5.6
4	पूर्वी क्षेत्र	19.4	24.6	5.2
5	बुन्देलखंड क्षेत्र	22.5	28.7	6.2
	उत्तर प्रदेश	21.7	27.4	5.7

स्रोत—भारतीय जनगणना 1971, 1981 (अस्थायी आंकड़े)।

उक्त आंकड़ों से ज्ञात होता है कि प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत वर्ष 1971 के 21.7 से बढ़कर 1981 में 27.4 हो गया फिर भी यह अखिल भारतीय औसत 36.2 प्रतिशत की तुलना में काफी कम रहा। साक्षरता

की दृष्टि से पर्वतीय क्षेत्र का प्रथम स्थान रहा जहाँ वर्ष 1981 में साक्षरता प्रतिशत 39.4 था। केन्द्रीय, बुन्देलखण्ड, पश्चिमी क्षेत्रों में साक्षरता लगभग समान ही रही और पूर्वी क्षेत्र में साक्षरता का स्तर 24.6 प्रतिशत राज्य के स्तर 27.4 प्रतिशत से कम था। 1971-81 की अवधि में पर्वतीय क्षेत्र में ही साक्षरता स्तर में सबसे अधिक वृद्धि (8.4 प्रतिशत) हुई और सबसे कम वृद्धि पूर्वी क्षेत्र में हुई जो केवल 5.2 प्रतिशत थी जब कि राज्य स्तर पर साक्षरता में 5.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

1.7--1981 की जनगणना के अन्तर्गत संदर्भित वर्ष में 6 मास से अधिक अवधि में आर्थिक कार्यों में लगे व्यक्तियों को मुख्य कर्मकर, 6 मास से कम अवधि में आर्थिक कार्यों में लगे व्यक्तियों को सीमान्त कर्मकर तथा शेष व्यक्तियों को गैर कर्मकर की श्रेणी में रखा गया है। 1981 जनगणना के अस्थाई आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 323.03 लाख व्यक्ति मुख्य कर्मकर तथा 29.65 लाख व्यक्ति सीमान्त कर्मकर की श्रेणी में पाये गये, जो प्रदेश की कुल जनसंख्या के क्रमशः 29.1 प्रतिशत तथा 2.7 प्रतिशत थे। दूसरे शब्दों में वर्ष 1981 की कुल जनसंख्या के लगभग 31.8 प्रतिशत कर्मकर वर्ष 1971 के 30.9 प्रतिशत कर्मकरों से कुछ अधिक रहे। प्रदेश की कुल जनसंख्या में मुख्य कर्मकारों का शतांश पुरुष वर्ग में 49.6, स्त्री वर्ग में 6.0, ग्रामीण क्षेत्र में 29.6, तथा नगरीय क्षेत्र में 27.2 रहा। इसी प्रकार जनसंख्या के, इन्हीं वर्गों में सीमान्त कर्मकरों का शतांश क्रमशः 1.9, 3.5, 3.0 एवं 1.1 रहा।

1.8--वर्ष 1981 की कुल जनसंख्या में मुख्य कर्मकारों के आर्थिक क्षेत्रवार प्रतिशत अंश का विवरण नीचे तालिका 1.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.5

1981 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में मुख्य कर्मकरों का आर्थिक क्षेत्रवार प्रतिशत

क्रम संख्या	आर्थिक क्षेत्र	जनसंख्या में कर्मकरों का प्रतिशत अंश				
		पुरुष	स्त्री	कुल	ग्रामीण	नगरीय
1	2	3	4	5	6	7
1	पर्वतीय क्षेत्र	46.4	24.2	35.4	36.3	31.2
2	पश्चिमी क्षेत्र	50.1	1.6	28.0	28.4	26.9
3	केन्द्रीय क्षेत्र	52.4	4.8	30.4	31.3	27.1
4	पूर्वी क्षेत्र	48.0	8.1	28.6	28.8	27.0
5	बुन्देलखण्ड	50.2	8.0	30.7	31.8	26.4
	उत्तर प्रदेश	49.6	6.0	29.1	29.6	27.2

स्रोत :--भारतीय जनगणना 1981 (अस्थाई आंकड़े)।

तालिकागत आंकड़ों के अनुसार प्रदेश की कुल पुरुष जनसंख्या में 49.6 प्रतिशत पुरुष कर्मकर रहे जब कि केन्द्रीय क्षेत्र में इनका अंश 52.4 प्रतिशत अन्य सभी क्षेत्रों की तुलना में अधिक रहा। पर्वतीय एवं पूर्वी क्षेत्रों में कुल पुरुषों के क्रमशः 46.4 प्रतिशत व 48.0 प्रतिशत पुरुष कर्मकर सम्पूर्ण प्रदेश के औसत (49.6 प्रतिशत) से कम रहे। परन्तु कुल स्त्री जनसंख्या में स्त्री कर्मकरों के अंश का आर्थिक क्षेत्रवार अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि पर्वतीय क्षेत्र में कुल स्त्रियों की 24.2 प्रतिशत स्त्री कर्मकर थी जो अन्य क्षेत्रों में सबसे अधिक तथा सम्पूर्ण राज्य में 6.0 प्रतिशत स्त्री कर्मकरों की तुलना में चार गुने से भी अधिक रही। परिणाम स्वरूप पर्वतीय क्षेत्र की पुरुष जनसंख्या में पुरुष कर्मकरों के न्यूनतम अंश होने के उपरान्त भी इस क्षेत्र की कुल जनसंख्या में 35.4 प्रतिशत कर्मकर थे, जो राज्य स्तर के साथ-साथ सभी आर्थिक क्षेत्रों से अधिक रहे। प्रदेश के सभी आर्थिक क्षेत्रों की ग्रामीण जनसंख्या में कर्मकरों का प्रतिशत अंश नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या में कर्मकरों के अंश की अपेक्षा अधिक रहा।

1.9--वर्ष 1981 के अनुसार मुख्य कर्मकरों का उद्योगानुसार प्रतिशत वितरण तालिका 1.6 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.6

जनगणना 1981 के अनुसार मुख्य कर्मकरों का उद्योगानुसार आर्थिक क्षेत्रवार प्रतिशत वितरण

क्रम सं०	आर्थिक क्षेत्र	कृषक	कृषि में			अन्य	समस्त
			कृषि श्रमिक	लगे कुल कर्मकर	घरेलू उद्योग		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पर्वतीय क्षेत्र	64.9	5.7	70.6	2.2	27.2	100.0
2	पश्चिमी क्षेत्र	53.7	15.4	69.1	4.3	26.6	100.0

1	2	3	4	5	6	7	8
3	केन्द्रीय क्षेत्र	63.0	11.8	74.8	3.7	21.5	100.0
4	पूर्वी क्षेत्र	58.6	20.3	78.9	5.3	15.8	100.0
5	बुन्देलखंड क्षेत्र	57.4	21.1	78.5	3.5	18.0	100.0
उत्तर प्रदेश		58.0	16.3	74.3	4.4	21.3	100.0

स्रोत:—भारतीय जनगणना 1981 (अस्थाई आंकड़े) ।

उक्त आंकड़ों से ज्ञात होता है कि प्रदेश में कुल मुख्य कर्मकरों के 58.0 प्रतिशत कृषक तथा 16.3 प्रतिशत कृषि-श्रमिक थे। इस प्रकार वर्ष 1981 में प्रदेश में कुल कर्मकरों के 74.3 प्रतिशत कर्मकर प्रत्यक्ष रूप से कृषि में लगे पाये गये। पूर्वी, बुन्देलखंड तथा केन्द्रीय क्षेत्र में कुल कर्मकरों के क्रमशः 78.9 प्रतिशत, 78.5 प्रतिशत व 74.8 प्रतिशत कृषक एवं कृषि श्रमिक थे जो इस बात का द्योतक है कि इन आर्थिक क्षेत्रों में कृषि पर निर्भरता अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक रही। यह भी देखा गया कि 4.4 प्रतिशत कर्मकर घरलू उद्योगों में लगे पाये गये। पूर्वी क्षेत्र में इनका प्रतिशत अन्य सभी क्षेत्रों में सर्वाधिक (5.3 प्रतिशत) रहा तथा अन्य सभी आर्थिक क्षेत्रों के कुल कर्मकरों में घरलू उद्योगों में लगे कर्मकरों का अंश राज्य के औसत (4.4 प्रतिशत) से कम रहा।

1.10—स्थायी भाव पर राज्य आय अनुमान प्रदेश की अर्थ व्यवस्था में हुई प्रगति को मापने का उपयुक्त माप दण्ड है। अतः प्रदेश की अर्थ व्यवस्था के आंकलन हेतु निम्न तालिका 1.7 में 1970-71 के भाव पर राज्य आय अनुमान प्रदर्शित किये गये हैं।

तालिका 1.7

उत्तर प्रदेश तथा भारत की कुल आय के अनुमान
(1970-71 के भावों पर)

वर्ष	उत्तर प्रदेश		भारत		राष्ट्रीय आय में राज्य आय का शतांश
	कुल आय (करोड़ रु०)	सूचकांक (1970-71 = 100.0)	(कुल आय करोड़ रु०)	सूचकांक (1970-71 = 100.0)	
1	2	3	4	5	6
1970-71	4256	100.0	34235	100.0	12.4
1973-74	4059	95.4	35967	105.1	11.3
1978-79 (अ)	5372	126.2	46306	135.3	11.6
1979-80 (अ)	4498	105.7	43822	128.0	10.3
1980-81 (त्व)	5523	129.8	47211	137.9	11.7

अ=अनन्तिम अनुमान

त्व=त्विरित अनुमान

स्रोत—अर्थ एवं संख्या प्रभाग एवं केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन भारत सरकार।

उक्त तालिका के अनुसार प्रदेश की कुल राज्य आय (1970-71 के भाव पर) जो कि वर्ष 1970-71 में 4256 करोड़ रुपये थी, चौथी योजना के अन्तिम वर्ष में 4.6 प्रतिशत घटकर 4059 करोड़ रुपये रह गयी। जबकि इसी अवधि में राष्ट्रीय आय में 5.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, परिणामतः 1973-74 में राष्ट्रीय आय में प्रदेश का योगदान वर्ष 1970-71 के 12.4 प्रतिशत से घटकर 11.3 प्रतिशत रह गया। पांचवीं योजनावधि में प्रदेश के आर्थिक विकास की गति राष्ट्रीय औसत की तुलना में कुछ अधिक रही जिस कारण पांचवीं योजना के अन्तिम वर्ष (1978-79) में भारत की कुल आय में राज्य आय का योगदान वर्ष 1973-74 के 11.3 प्रतिशत से बढ़कर 11.6 प्रतिशत हो गया। यद्यपि वर्ष 1979-80 में सम्पूर्ण भारत में सूखे का दुःप्रभाव पड़ा किन्तु सम्पूर्ण देश की अपेक्षा प्रदेश में सूखे का अधिक प्रभाव पड़ा। इसके फलस्वरूप वर्ष 1979-80 में गत वर्ष की अपेक्षा जहां राष्ट्रीय आय में केवल लगभग 5.4 प्रतिशत की गिरावट आई वहीं राज्य आय में 16.3 प्रतिशत की गिरावट आई और वर्ष 1979-80 की कुल राष्ट्रीय आय में राज्य आय का अंश 11.6 प्रतिशत से घटकर 10.3 प्रतिशत रह गया। वर्ष 1980-81 के लिये उपलब्ध त्विरित अनुमानों के अनुसार प्रदेश की कुल राज्य आय 5523 करोड़ रुपये पूर्वगामी वर्ष की अपेक्षा लगभग 22.8 प्रतिशत तथा वर्ष 1978-79 की कुल राज्य आय की तुलना में 2.8 प्रतिशत अधिक रहीं, जबकि राष्ट्रीय आय में सम्वादी अवधि में वृद्धि क्रमशः 7.7 प्रतिशत तथा 2.0 प्रतिशत ही रही।

1.11—देश/प्रदेश के वास्तविक आर्थिक विकास का बोध कुछ हद तक स्थायी भावों पर प्रति व्यक्ति राज्य आय अनुमान से हो सकता है। तालिका 1.8 में 1970-71 के भावों पर उत्तर प्रदेश एवं भारत की प्रति व्यक्ति आय दर्शायी गयी है।

तालिका 1.8

उत्तर प्रदेश एवं भारत की प्रति व्यक्ति आय
(1970-71 के भावों पर)

वर्ष	उत्तर प्रदेश		भारत		भारत की अपेक्षा प्रदेश की प्रति-व्यक्ति आय में न्यूनता (प्रतिशत)
	प्रति व्यक्ति आय (₹0)	सूचकांक (1970-71=100.0)	प्रति व्यक्ति आय (₹0)	सूचकांक (1970-71=100.0)	
1	2	3	4	5	6
1970-71	486	100.0	633	100.0	23.2
1973-74	439	90.3	621	98.1	29.3
1978-79 (अ)	530	109.1	715	113.0	25.9
1979-80 (अ)	436	89.7	661	104.4	34.0
1980-81 (त्व)	526	108.2	696	110.0	24.4

अ-अनन्तिम अनुमान

त्व-त्वरित अनुमान

स्रोत—अर्थ एवं संख्या प्रभाग एवं केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन भारत सरकार।

उपरोक्त तालिका से विदित है कि वर्ष 1970-71 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय (486 ₹0) उस वर्ष राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय (633 ₹0) की अपेक्षा 23.2 प्रतिशत कम थी। चौथी योजना के अन्तिम वर्ष (1973-74) में 1970-71 की तुलना में प्रति व्यक्ति राज्य आय में 9.7 प्रतिशत की गिरावट के समक्ष प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में मात्र 1.9 प्रतिशत की गिरावट रही परिणामतः वर्ष 1973-74 में प्रति व्यक्ति राज्य आय (439 ₹0) प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय की तुलना में 29.3 प्रतिशत कम हो गई। पांचवी योजनावधि में राज्य की अर्थव्यवस्था में अपेक्षाकृत अधिक प्रगति के फलस्वरूप वर्ष 1978-79 की प्रति व्यक्ति राज्य आय (530 ₹0) जो वर्ष 1973-74 में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय की अपेक्षा 29.3 प्रतिशत कम थी वह वर्ष 1978-79 में 25.9 प्रतिशत कम रही। वर्ष 1979-80 में अभूतपूर्व सूखे के कारण प्रदेश की अर्थ व्यवस्था पर काफी विपरीत प्रभाव पड़ा और इस वर्ष प्रति व्यक्ति राज्य आय घटकर 436 ₹0 के निम्नतम स्तर पर पहुंच गई, जो वर्ष 1978-79 की तुलना में 17.7 प्रतिशत कम रही जबकि सन्वादी अवधि में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में केवल 7.6 प्रतिशत की गिरावट आई परिणामतः वर्ष 1979-80 में प्रति व्यक्ति राज्य आय प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय की अपेक्षा 34.0 प्रतिशत हो गई। वर्ष 1980-81 में परिस्थितियों के कुछ अनुकूल होने के कारण प्रति व्यक्ति अनुमानित राज्य आय (526 ₹0) गत वर्ष की अपेक्षा 20.6 प्रतिशत अधिक रही किन्तु 1978-79 की तुलना में 0.8 प्रतिशत कम रही। इसके विपरीत राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय वर्ष 1980-81 में 696 ₹0 रही जो वर्ष 1979-80 की तुलना में 5.3 प्रतिशत अधिक रही परन्तु वर्ष 1978-79 की तुलना में 2.7 प्रतिशत कम रही।

1.12—राजकीय अर्थ व्यवस्था के विभिन्न खण्डों में हुई प्रगति तथा सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था में उनके योगदान के अभिज्ञान हेतु तालिका 1.9 में 1970-71 के स्थायी भावों पर कुल राज्य आय का खण्ड वार प्रतिशत वितरण दर्शाया गया है।

तालिका 1.9

उत्तर प्रदेश की राज्य आय (1970-71 के भावों पर) का खण्डवार प्रतिशत वितरण

क्रम-संख्या	खण्ड	1978-79	1979-80	1980-81
		(अ)	(अ)	(त्व)
1	2	3	4	5
1	कृषि एवं पशुपालन	55.6	49.2	55.6
2	वन एवं लट्ठे बनाना	1.0	1.2	1.0
3	मछली उद्योग	0.2	0.2	0.1

1	2	3	4	5
4	उत्खनन एवं पत्थर निकालना	0.1	0.2	0.1
	(i) प्राथमिक खण्ड	56.9	50.8	56.8
1	विनिर्माण	10.7	11.3	10.2
2	निर्माण	5.8	7.6	6.3
3	विद्युत गैस-एवं जल सम्पत्ति	0.8	0.9	0.8
	(ii) माध्यमिक खण्ड	17.3	19.8	17.3
	(iii) परिवहन, संचार एवं व्यापार	14.0	15.0	14.0
	(iv) वित्त एवं स्थावर सम्पदा	4.5	5.5	4.6
	(v) सामुदायिक एवं निजी सेवायें	7.3	8.9	7.3
	समस्त	100.0	100.0	100.0

अ—अनन्तिम अनुमान त्व-त्वरित अनुमान
 स्रोत—अर्थ एवं संख्या प्रभाग उत्तर प्रदेश ।

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि प्रदेश की सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था में 'कृषि एवं पशुपालन खंड' का विशिष्ट स्थान है। यों तो कुल राज्य आय में इस खंड का योगदान आधे से भी अधिक रहता है किन्तु वर्ष 1979-80 में सूखे के कारण इस खण्ड से अर्जित आय में पूर्व वर्ष की अपेक्षा 25.9 प्रतिशत की गिरावट आने के उपरान्त भी वर्ष 1979-80 की कुल राज्य आय में इस खंड का योगदान लगभग आधा (49.2 प्रतिशत) रहा। वर्ष 1980-81 की कुल राज्य आय में विनिर्माण खंड का योगदान 10.2 प्रतिशत वर्ष 1978-79 के 10.7 प्रतिशत से कम रहा किन्तु वर्ष 1980-81 की कुल राज्य आय में माध्यमिक खंड का 17.3 प्रतिशत अंश वर्ष 1978-79 के समान रहा। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 1973-74 में राज्य की सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था में माध्यमिक खंड का योगदान 16.5 प्रतिशत था, जो कि बढ़कर वर्ष 1980-81 में 17.3 प्रतिशत हो गया। यह तथ्य इस बात का द्योतक है कि राज्य की अर्थ व्यवस्था कृषि से अकृषीय क्षेत्र की ओर शर्नः शर्नः अग्रसर होती जा रही है।

1.13—देश/प्रदेश स्तर पर विभिन्न योजनावधि में आर्थिक विकास में हुई वृद्धि दर का बोध निम्नतालिका-1.10 से हो-सकता है।

तालिका-1 10

विभिन्न योजनावधियों में भारत एवं उत्तर प्रदेश की आर्थिक वृद्धि दर

योजनावधि	सम्पूर्ण राष्ट्रीय/राज्य आय प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय/राज्य आय			
	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश
1	2	3	4	5
प्रथम योजना	3.4	1.9	1.6	0.5
द्वितीय योजना	4.0	1.8	1.8	0.2
तृतीय योजना	2.2	1.6	0.0 (+)	0.2
वार्षिक योजनायें	4.0	0.3	1.8 (-)	1.5
चतुर्थ योजना	3.3	2.3	1.1	0.4
पांचवीं योजना	5.2	5.8	2.8	3.9
1978-79 से 1980-81	1.0	1.4	(-) 1.3	(-) 0.4

स्रोत—अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश ।

उपरोक्त तालिका 1.10 के अनुसार चतुर्थ योजनाकाल तक प्रदेश की आर्थिक विकास दर सम्पूर्ण भारत की विकास दर से कम रही और प्रथम, तीन पंचवर्षीय योजनाकाल में तो स्थिति बहुत ही खराब रही थी। यद्यपि चौथी योजनावधि में भी प्रदेश की विकास दर भारतीय विकास दर की अनुगामी रही किन्तु फिर भी प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और पांचवीं योजनाकाल में कुल राज्य आय में 5.8 प्रतिशत की दर से तथा प्रति व्यक्ति राज्य आय में 3.9 प्रतिशत की दर से हुई वृद्धि भारतीय स्तर पर हुई क्रमशः 5.2 प्रतिशत तथा 2.8 प्रतिशत की वृद्धि दर से

अधिक रही। वर्ष 1979-80 में पड़े आशातीत सूखे के कारण ह्वस्त प्रदेशीय अर्थव्यवस्था में यद्यपि वर्ष 1980-81 में पर्याप्त सुधार हुआ और 1978-79 से 1980-81 की अवधि में कुल राज्य आय में 1.4 प्रतिशत की वृद्धि दर सम्भव हुई जबकि राष्ट्र स्तर पर कुल आय में वृद्धि दर केवल 1.0 रही। जनसंख्या में वृद्धि के कारण इस अवधि में यद्यपि प्रति व्यक्ति राज्य आय में 0.4 प्रतिशत का ह्रास, दृष्टिगोचर हुआ परन्तु यह ह्रास भारत स्तर पर हुए 1.3 प्रतिशत वार्षिक ह्रास की तुलना में कम रहा।

1.14—पांचवी योजना काल के अनुगामी वर्षों में भी मुद्रा स्फीति का दबाव बना रहा और इसके कारण सम्पूर्ण देश की भांति प्रदेश में भी मूल्य वृद्धि को नियंत्रित नहीं किया जा सका। इसके साथ ही प्रदेश में वर्ष 1979-80 की अनावृष्टि भी काफी हद तक भाव वृद्धि में सहायक सिद्ध हुई। चूंकि किसी भी क्षत्र की अर्थव्यवस्था पर उस क्षेत्र की वस्तुओं के भावों का व्यापक प्रभाव पड़ता है। अतः प्रदेश की आर्थिक समीक्षा के सन्दर्भ में भावों की प्रवृत्ति का अध्ययन करना सामयिक होगा। तालिका 1.11 में उत्तर प्रदेश में व्यापक थोक भाव सूचकांक (1970-71=100) तथा कुछ मुख्य वर्ग/उप-वर्ग सूचकांक सम्बन्धी आंकड़े दर्शाये गये हैं। इन आंकड़ों से विदित होता है कि प्रदेश में वर्ष 1978-79 का व्यापक सूचकांक 184.5 था जो 37.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 1980-81 में 253.0 के स्तर पर पहुंच गया। इस अवधि में सर्वाधिक वृद्धि (48.1 प्रतिशत) विनिर्मित उत्पाद्य वर्ग सूचकांक में हुई जबकि ईंधन, शक्ति, प्रकाश व स्नेहक वर्ग सूचकांक और प्राथमिक वस्तु वर्ग सूचकांक में क्रमशः 33.2 प्रतिशत और 26.1 प्रतिशत की वृद्धि रही। गत वर्ष की अपेक्षा वर्ष 1980-81 के व्यापक थोक भाव सूचकांक में 21.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विनिर्मित उत्पाद्य वर्ग सूचकांक, ईंधन, शक्ति, प्रकाश व स्नेहक वर्ग सूचकांक और प्राथमिक वस्तु वर्ग सूचकांक में क्रमशः 21.7 प्रतिशत, 19.8 प्रतिशत और 21.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उक्त तालिका से यह भी ज्ञात होता है कि वर्ष 1980-81 में विनिर्मित उत्पाद्य वर्ग के अन्तर्गत खाद्य उत्पाद्य उपवर्ग सूचकांक (319.2) में गत वर्ष की अपेक्षा 51.9 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इसके पश्चात् इसी अवधि में प्राथमिक वस्तु वर्ग के अन्तर्गत अखाद्य वस्तु उपवर्ग के सूचकांक में 24.4 प्रतिशत की वृद्धि रही, अपवाद स्वरूप वर्ष 1980-81 में गत वर्ष अपेक्षा कपड़े के थोक भावों में कुछ गिरावट आई, जिसके फलस्वरूप कपड़ा उपवर्ग के सूचकांक में 0.7 प्रतिशत कमी हुई। वर्ष 1981-82 के प्रथम त्रैमास में थोक भावों की बढ़ती गति कुछ शिथिल हुई जिसके फलस्वरूप जून 1981 में व्यापक थोक भाव सूचकांक मार्च 1981 (260.7) की अपेक्षा 3.1 प्रतिशत से बढ़कर 268.9 हो गया। यद्यपि मुख्य वर्ग सूचकांक तथा प्राथमिक वस्तु वर्ग, ईंधन, शक्ति, प्रकाश व स्नेहक वर्ग और विनिर्मित उत्पाद्य वर्ग सूचकांकों में मार्च 1981 की अपेक्षा जून 1981 में क्रमशः 1.0 प्रतिशत, 7.3 प्रतिशत और 4.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई किन्तु गत वर्ष की सम्बाद्धी अवधि में हुई वृद्धि क्रमशः 6.1 प्रतिशत, 7.6 प्रतिशत और 6.3 प्रतिशत की तुलना में अपेक्षाकृत कम रही। उक्त तालिका से यह तथ्य भी स्पष्ट होता है कि वर्ष 1979-80, 1980-81 तथा वर्ष 1981-82 के प्रथम त्रैमास में विनिर्मित उत्पाद्य के थोक भाव प्राथमिक वस्तुओं के थोक भावों से अपेक्षाकृत अधिक गति से बढ़े।

तालिका 1.11.

उत्तर प्रदेश में थोक भावों की प्रवृत्ति

मद	थोक भाव सूचकांक (1970-71- =100)				वर्ष 1980-81 में प्रतिशत वृद्धि		मार्च 1981 की तुलना में जून 1981 में प्रति- शत वृद्धि		
	1978- 79	1979- 80	1980- 81	मार्च, 1981	जून 1981	1978- 79 की तुलना में	1979- 80 की तुलना में	9	
1—प्राथमिक वस्तु (43.7)	185.7	193.1	234.2	236.4	238.7	26.1	21.3	1.0	
(क) खाद्य वस्तु (22.9)	187.4	192.1	227.0	238.2	230.8	21.4	18.5	3.1	
(ख) अखाद्य वस्तु (20.7)	183.4	193.8	241.1	233.9	247.0	31.5	24.4	5.6	
(ग) खनिज पदार्थ (0.1)	342.2	342.6	361.6	417.9	417.9	5.7	5.5	0.0	
2—ईंधन, शक्ति, प्रकाश व स्नेहक (7.3)	..	222.6	247.4	296.4	327.4	351.2	33.2	19.8	7.3
3—विनिर्मित उत्पाद्य (49.0)	177.8	216.4	263.4	272.4	283.7	48.1	21.7	4.1	
(क) खाद्य उत्पाद्य (14.8)	155.9	210.1	319.2	317.1	334.4	104.7	51.9	5.4	
(ख) कपड़ा (14.7)	..	185.2	208.5	207.1	209.4	214.4	11.8	(-) 0.7	2.4
(ग) रसायन व रसायन उत्पाद्य (3.7)	..	186.3	217.1	259.8	288.8	297.1	39.4	19.7	2.9
(घ) अधात्विक खनिज उत्पाद्य (3.4)	..	201.0	261.8	291.0	302.4	324.1	44.8	11.2	7.2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(ख) मूल व मिश्रित धातु एवं धातु उत्पाद्य (5.8) ..	178.7	222.1	269.2	306.7	311.4	50.6	21.2	1.5	
(च) मशीनरी एवं यातायात उपकरण (3.1) ..	193.4	222.4	253.1	261.5	279.0	30.9	13.8	6.7	
समस्त वर्ग (100.0)]	184.5	208.5	253.0	260.7	268.9	37.1	21.3	3.1	

टिप्पणी:—भार (एक दशमलव अंक तक सही) मर्दों के साथ कोष्ठ में दिये हुये है।

1.15—थोक भावों में वृद्धि का प्रभाव नगरीय एवं ग्रामीण फुटकर भाव पर पड़ना स्वाभाविक है। इसकी पुष्टि नीचे तालिका 1.12 में प्रदर्शित नगरीय तथा ग्रामीण उपभोक्ता भाव सूचकांकों से भी होती है।

तालिका 1.12

उत्तर प्रदेश में उपभोक्ता भाव सूचकांक

(अ) नगरीय मध्यवर्गीय उपभोक्ता भाव सूचकांक (1948=100)

मद	वर्ष			वर्ष 1980-81 प्रतिशत वृद्धि में प्रतिशत वृद्धि			
	1978-79	1979-80	1980-81	1978	1979	मार्च 80	मार्च 81
				की अपेक्षा	की अपेक्षा	में जून 80 में	तुलना में जून 81 में
1	2	3	4	5	6	7	8
1—खाद्य ..	353.9	375.2	436.9	23.4	16.4	4.4	4.8
2—खाद्यान्न ..	317.2	335.6	391.5	23.4	16.7(-)	4.0 (-)	16.6
3—धान्य ..	264.9	284.6	343.8	29.8	20.8(-)	6.0 (-)	11.7
4—दालें ..	725.7	734.2	763.5	5.2	4.0	2.8	(-)1.8
5—चीनी ..	274.5	342.5	661.9	141.1	93.3	7.8	8.4
6—सरसों का तेल ..	538.5	583.0	714.8	32.7	22.6(-)	2.6	0.9
व्यापक सूचकांक ..	334.4	362.2	418.5	25.1	15.5	2.9	3.2

(ब) ग्रामीण उपभोक्ता भाव सूचकांक (कृषि वर्ष 1957-58=100)

मद	वर्ष			वर्ष 1980-81 प्रतिशत वृद्धि में प्रतिशत वृद्धि			
	1978-79	1979-80	1980-81	1978	1979	जैमास	जैमास
				की अपेक्षा	की अपेक्षा	में जून 80 में	में जून 81 में
1	2	3	4	5	6	7	8
1—खाद्य ..	375.4	404.5	464.2	23.7	14.8	1.8	1.8
2—खाद्यान्न ..	356.2	379.9	422.1	18.5	11.1(-)	1.4(-)	1.3
3—धान्य ..	320.5	346.8	393.0	22.6	13.3(-)	1.8(-)	2.3
4—दालें ..	644.8	647.2	657.2	1.9	1.5	0.3	3.4
5—चीनी ..	267.4	354.7	650.4	143.2	83.4	21.0	6.6
6—सरसों का तेल ..	406.2	436.1	527.2	29.8	20.9	(-)0.2(-)	3.4
व्यापक सूचकांक ..	376.5	410.4	469.2	24.6	14.3	1.1	1.8

स्रोत:—अर्थ एवं संख्या प्रभाग।

उक्त तालिका 1.12 (अ) से विदित है कि प्रदेश में नगरीय मध्यवर्गीय उपभोक्ता भाव सूचकांक (1948=100), जो वर्ष 1978-79 में 334.4 था, बढ़कर वर्ष 1979-80 में 362.2 तथा वर्ष 1980-81 में 418.5 के स्तर पर पहुंच गया, इस प्रकार वर्ष 1980-81 के सूचकांक में वर्ष 1978-79 तथा गत वर्ष 1979-80 की अपेक्षा क्रमशः 25.1 प्रतिशत और 15.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी प्रकार तालिका 1.12 (ब) के अनुसार ग्रामीण, फुटकर भावों में सम्वादी वृद्धि क्रमशः 24.6 प्रतिशत और 14.3 प्रतिशत रही। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि नगरीय क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता भावों में वृद्धि अपेक्षाकृत कुछ कम रही। वर्ष 1978-79 तथा वर्ष 1979-80 की अपेक्षा वर्ष 1980-81 में चीनी के भावों में सर्वाधिक वृद्धि नगरीय एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में हुई। यह तुलनात्मक वृद्धि नगरीय क्षेत्र में क्रमशः 141.1 प्रतिशत तथा 93.3 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र में क्रमशः 143.2 प्रतिशत तथा 83.4 प्रतिशत रही। वर्ष 1981-82 के प्रथम त्रैमास में गत वर्ष (मार्च 1981) की तुलना में नगरीय मध्य वर्गीय सूचकांक में 3.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, यह वृद्धि यद्यपि गत वर्ष के सम्वादी त्रैमास में हुई वृद्धि (2.9 प्रतिशत) से अधिक रही, किन्तु वर्ष 1981-82 के प्रथम तीन माहों में खाद्यान्न, धान्य एवं दालों के भावों में क्रमशः 16.6 प्रतिशत, 11.7 प्रतिशत और 1.8 प्रतिशत की गिरावट भी आई। इसी अवधि में प्रदेश के ग्रामीण उपभोक्ता भाव सूचकांक (कृषि वर्ष 1957-58=100) में केवल 1.8 प्रतिशत की वृद्धि दृष्टिगोचर हुई, जो गत वर्ष की सम्वादी अवधि में हुई वृद्धि (1.1 प्रतिशत) से यद्यपि अधिक थी परन्तु इस अवधि में खाद्यान्न, धान्य और सरसों के तेल के भाव प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमशः 1.3 प्रतिशत, 2.3 प्रतिशत और 3.4 प्रतिशत कम रहे।

1.16—विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु, कार्य प्रकृति आदि को विचार में रखते हुये देश में न्यूनतम, पीष्टिक आहार के मापदण्ड के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी तथा नगरीय क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2100 कैलोरी की आवश्यकता आंकी गई है। इस आधार पर वर्ष 1979-80 में प्रदेश की 47.2 प्रतिशत (47.8 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र तथा 43.5 प्रतिशत नगरीय क्षेत्र) जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रही थी। इस समुदाय के व्यक्तियों के आर्थिक उत्थान हेतु विशेष योजना कार्यक्रमों के माध्यम से प्रयास किये जा रहे हैं। इनमें से ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्योदय कार्यक्रम उल्लेखनीय है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक ग्राम से ऐसे पांच निर्धन परिवारों का चयन किया गया, जिनकी सभी छोटों से वार्षिक आय 2,000 रु० से कम थी। इन परिवारों को स्वावलम्बी एवं आर्थिक रूप से सक्षम बनाने हेतु अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान सीमा के साथ 4 प्रतिशत ब्याज दर पर 5,000 रु० तक ऋण दिये जाने की व्यवस्था की गई। वर्ष 1980-81 में ऐसे समस्त चयनित परिवारों में से 1.62 लाख परिवारों को विभिन्न आर्थिक कार्यक्रमों हेतु 34.58 करोड़ रुपये ऋण, जिसका लगभग एक तिहाई अंश अनुदान के रूप में था, सुलभ कराकर लाभांशित किया गया।

1.17—1971 की जनगणनानुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या का 21.2 प्रतिशत अंश अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों का था। यद्यपि नियोजित विकास द्वारा सभी प्रदेशवासियों के जीवन स्तर के समुदायिकरण के निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं फिर भी इस समुदाय के व्यक्तियों के जीवन स्तर पर नियोजित विकास का विशेष प्रभाव परिलक्षित नहीं हो पा रहा है। अतः इस समुदाय के लोगों को विकास योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ सुलभ कराने हेतु सभी विकास विभागों से स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत, उन्नत विभाज्य परिव्यय में से इनकी जनसंख्या के अनुपात में परिव्यय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित करने हेतु निदिष्ट किया गया जिससे इनके लिये रोजगार के अपेक्षाकृत अधिक अवसर उपलब्ध हो सकें और इनकी आय के स्थायी स्रोत सुनिश्चित हो सकें इसके साथ-साथ आवास, पेयजल, स्वास्थ्य की देखभाल जैसी न्यूनतम प्रारम्भिक आवश्यकताओं की सम्पत्ति की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा सके। उक्त कार्य क्रमों के माध्यम से वर्ष 1979-80 में 23.34 करोड़ रुपये इन जातियों के कल्याण हेतु व्यय किया गया। वर्ष 1980-81 एवं 1981-82 में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान हेतु निदिष्ट क्रमशः 119 करोड़ रुपये, तथा 164 करोड़ रुपये का परिव्यय वर्ष 1979-80 के व्यय का क्रमशः लगभग पांच गुना व सात गुना रहा।

1.18—सूखा, बाढ़ एवं जल प्लावन जैसी विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से यह प्रदेश प्रायः प्रभावित होता रहा है, परिणामतः इसके आर्थिक विकास में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। यद्यपि इन आपदाओं से उत्पन्न विषम परिस्थितियों से निपटने हेतु केन्द्र सरकार से सहायक अनुदान एवं ऋणस्वरूप वित्तीय सहायता प्राप्त होती है फिर भी राज्य सरकार को अपने वित्तीय संसाधनों का एक पर्याप्त अंश इन आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त अर्थ व्यवस्था के जीर्णोद्धार पर व्यय करना पड़ता है। वर्ष 1981-82 में बाढ़ एवं जल प्लावन के परिणामस्वरूप क्षतिग्रस्त फसलों, मवेशियों तथा मकानों के रूप में 4.75 करोड़ रुपये की व्यक्तिगत तथा मुख्य रूप से सड़कों एवं पुल के टूटने तथा क्षतिग्रस्त होने से 55.58 करोड़ रुपये की सार्वजनिक सम्पत्ति को अनुमानित हानि हुई। प्रभावित जन समुदाय को राहत पहुंचाने तथा सार्वजनिक क्षतिग्रस्त सम्पत्ति को सुधार हेतु विभिन्न विभागों द्वारा 182 करोड़ रुपये की आवश्यकता प्रस्तुत की गई है। वर्ष 1981-82 में (दिनांक 11-8-81 तक) 3.63 करोड़ रुपये का अनुदान, 2.27 करोड़ रुपये गृह अनुदान तथा 1.49 करोड़ रुपये विशेष अनुदान तथा लगभग एक करोड़ रुपये तकावी हेतु आवंटित किये गये।

1.19—योजना आयोग द्वारा प्रदेश की छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) हेतु 6200 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। वर्ष 1981 की जनगणनानुसार प्रदेश के 1109 लाख व्यक्तियों पर उपर्युक्त स्वीकृत परिव्यय औसतन 559 रु० प्रति व्यक्ति है, जो पांचवी योजना के 322 रु० की तुलना में 73.6 प्रतिशत अधिक है। छठी योजना में प्रदेश के कृषिगत एवं औद्योगिक विकास में जल तथा विद्युत के महत्व को दृष्टिगत रखते हुये उपर्युक्त सम्पूर्ण परिव्यय को सर्वाधिक भाग (53.8 प्रतिशत) "जल एवं विद्युत" मद के लिये निर्धारित किया गया है। इसके समक्ष वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 में इस मद हेतु क्रमशः 52.7 प्रतिशत तथा 50.9 प्रतिशत भाग सुनिश्चित किया गया। इसके उपरान्त "कृषि एवं सम्बन्धीय मद हेतु निर्धारित 16.6 प्रतिशत अंश के विपरीत वर्ष 1981-82 के कुल स्वीकृत परिव्यय में कृषि एवं सम्बन्धीय मद का अंश 16.5 प्रतिशत रहा। वर्ष 1981-82 के स्वीकृत कुल योजना परि-

ख्य का 15.2 प्रतिशत भाग सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं हेतु निर्धारित किया गया, जो उक्त कार्यक्रमों पर छठी योजना के कुल परिव्यय के 14.1 प्रतिशत अंश तथा वर्ष 1980-81 के योजना परिव्यय के 14.5 प्रतिशत अंश से कुछ अधिक ही रहा। इसी प्रकार छठी योजना के कुल परिव्यय का उद्योग एवं खनिकर्म हेतु आवंटित 5.4 प्रतिशत भाग के समक्ष वर्ष 1981-82 के योजना परिव्यय में 5.8 प्रतिशत अंश, निर्धारित किया गया है, प्रदेश में स्वीकृत योजना परिव्यय के मदवार प्रतिशत वितरण के आंकड़े नीचे तालिका 1.13 में दर्शाये गये हैं।

तालिका 1.13

उत्तर प्रदेश में स्वीकृत योजना परिव्यय का मदवार प्रतिशत वितरण

क्रम- संख्या	मद	छठी योजना (1980-85)		
		1980-81	1981-82	
1	2	3	4	5
1	कृषि एवं सम्बन्धीय	16.6	15.6	16.5
2	सहकारिता	0.9	1.0	1.0
3	जल एवं विद्युत	53.8	52.7	50.9
4	उद्योग एवं खनिकर्म	5.4	5.4	5.8
5	परिवहन एवं संचार	8.9	10.5	10.0
6	सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएँ	14.1	14.5	15.2
7	अन्य	0.3	0.3	0.6
समस्त		100.0 (6200.00)	100.0 (933.83)	100.0 ¹ (1085.00)

नोट—कोष्ठ में दी गई सूचना करोड़ रुपये में है।

स्रोत—नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश।

अध्याय 2

कृषि एवं सम्बर्गीय व्यवसाय

2.0—वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की लगभग 82 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है तथा कृषि ही इनकी जीविकोपार्जन का मुख्य साधन है। जनगणना पर आधरित आंकड़ों से यह भी विदित होता है कि प्रदेश में कुल 323.03 लाख मुख्य कर्मकरों के 74.3 प्रतिशत कर्मकर कृषक एवं कृषि श्रमिकों की श्रेणी में हैं। इसके अतिरिक्त कुल राज्य आय में “कृषि एवं पशुपालन” खंड से अर्जित होने वाली आय का अंशदान 50 प्रतिशत से अधिक है। स्थायी भावों (1970-71) पर कुल राज्य आय में इस खंड का योगदान वर्ष 1978-79 में 55.6 प्रतिशत था जो वर्ष 1979-80 में सूखे के कारण 49.2 प्रतिशत रहा। स्पष्टतः राज्य की अर्थ व्यवस्था कृषि गत कार्यकलापों पर व्यापक रूप से आधरित है। अतः प्रदेश में कृषि कार्यक्रमों का प्रचार एवं प्रसार योजनाबद्ध ढंग से किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। प्रदेश की छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) हेतु 6200 करोड़ रुपये के स्वीकृत परिव्यय में से लगभग 16.6 प्रतिशत धनराशि कृषि एवं सम्बर्गीय कार्यक्रम हेतु प्रत्यक्ष रूप में प्राविधानित है वर्ष 1981-82 की वार्षिक योजना में भी इन कार्यक्रमों के लिये राज्य के कुल परिव्यय का 16.5 प्रतिशत परिव्यय आवंटित किया गया है।

2.1—प्रदेश के वर्ष 1973-74 में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल (298.26 लाख हेक्टेयर) का 57.6 प्रतिशत अंश वास्तविक बोये गये क्षेत्रफल का था, जो बढ़ते हुये वर्ष 1978-79 में 58.6 प्रतिशत हो गया। वर्ष 1978-79 में वास्तविक बोया गया क्षेत्रफल 174.82 लाख हेक्टेयर वर्ष 1973-74 की तुलना में लगभग 1.8 प्रतिशत तथा वर्ष 1977-78 की तुलना में 0.4 प्रतिशत अधिक रहा, किन्तु सूखे के कारण वर्ष 1979-80 का वास्तविक बोया गया क्षेत्रफल 169.97 लाख हेक्टेयर गत वर्ष की तुलना में 2.8 प्रतिशत कम रहा। चूंकि भूमि एक सीमित साधन है, वास्तविक बोये गये क्षेत्रफल में कोई विशेष वृद्धि सम्भव नहीं है। अतः छठी योजना अवधि में कृषि उत्पादन में 5.5 प्रतिशत की प्रस्तावित वार्षिक विकास दर को प्राप्त करने हेतु प्रति हेक्टर उत्पादकता में वृद्धि ही एकमात्र विकल्प है। इस हेतु फसल सघनता में वृद्धि, सिंचाई सुविधाओं का प्रसार, प्रति हेक्टेयर उर्वरकों के प्रयोग में वृद्धि, अधिक उपज देने वाली प्रजातियों के अन्तर्गत क्षेत्र का विस्तार करने आदि के प्रयास जारी हैं।

2.2—वर्ष 1973-74 में प्रदेश में फसल सघनता 134.0 प्रतिशत थी जो वर्ष 1978-79 में बढ़कर 139.0 प्रतिशत हो गयी। वर्ष 1978-79 में फसल सघनता की दृष्टि से पर्वतीय क्षेत्र (160.1 प्रतिशत), पश्चिमी क्षेत्र (146.9 प्रतिशत) तथा पूर्वी क्षेत्र (140.9 प्रतिशत) क्रमशः प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर रहे और इस प्रकार इन क्षेत्रों में फसल सघनता राज्य के औसत से अधिक रही। केन्द्रीय क्षेत्र में फसल सघनता 131.5 प्रतिशत प्रदेश के औसत से कुछ ही कम रही किन्तु बुन्देलखंड क्षेत्र में फसल की सघनता केवल (111.6 प्रतिशत) ही रही। वर्ष 1979-80 में राज्य में फसल सघनता 139.1 प्रतिशत थी, जो गत वर्ष की फसल सघनता के लगभग समान ही रही। प्रदेश में फसल सघनता को अधिक से अधिक बढ़ाकर वर्ष 1981-82 तक 141.6 प्रतिशत के स्तर तक पहुंचाने का हर सम्भव प्रयास जारी है। इसके उपरांत भी यह प्रदेश पंजाब व हरियाणा जहां फसल सघनता वर्ष 1978-79 में ही क्रमशः 157 प्रतिशत और 151 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच चुकी है, राज्यों से काफी पीछे रहेगा। प्रदेश में फसल सघनता पांचवीं योजना अवधि में 134 से 139 प्रतिशत पर पहुंची जबकि कृषि की दृष्टि से उन्नत पंजाब तथा हरियाणा राज्यों में फसल सघनता का स्तर बढ़कर क्रमशः 146 से 157 तथा 144 से 151 प्रतिशत हो गया।

2.3—फसल सघनता तथा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग मुख्यतः सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर है। प्रदेश में राजकीय तथा निजी सिंचाई साधनों द्वारा अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित करने के निरन्तर प्रयास जारी हैं। निजी सिंचाई साधनों से समय पर सुनिश्चित सिंचाई की सुविधा सुलभ होने के कारण इनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन अधिक बढ़ती जा रही है। लघु सिंचाई विभाग के अनुसार वर्ष 1980-81 में सिंचाई हेतु उपलब्ध 1101 हजार निजी कुयें, 472 हजार निजी रहट, 611 हजार निजी पम्पिंग सेट तथा लगभग 808 हजार निजी नलकूप गत वर्ष की तुलना में क्रमशः 1.3 प्रतिशत, 1.5 प्रतिशत, 21.5 प्रतिशत तथा 8.3 प्रतिशत अधिक रहे। वर्ष 1981-82 में जून 1981 तक निजी सिंचाई साधनों के प्रसार हेतु 5.83 करोड़ रुपये भूमि विकास बैंक द्वारा तथा 2.56 करोड़ रुपये व्यवसायिक बैंकों द्वारा ऋण स्वरूप सुलभ कराये गये। इसकी सहायता से 10486 निजी नलकूप, 14919 पम्पिंग सेट्स, 478 रहट तथा 1826 कुयों का निर्माण किया गया। इस प्रकार वर्ष 1981-82 में निजी लघु सिंचाई साधनों द्वारा 9.16 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजन के प्रस्तावित लक्ष्य के समक्ष जून, 1981 तक 1.32 लाख हेक्टेयर (लक्ष्य का 14.5 प्रतिशत) की सिंचन क्षमता का सृजन किया गया।

2.4—वर्ष 1979-80 में इस प्रदेश में विभिन्न स्रोतों द्वारा उपलब्ध 151.82 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचन क्षमता वर्ष 1973-74 (97.96 लाख हेक्टेयर) एवं वर्ष 1978-79 (140.33 लाख हेक्टेयर) में उपलब्ध सिंचन क्षमता की तुलना में क्रमशः 55.0 प्रतिशत तथा 8.2 प्रतिशत अधिक रही। सिंचन क्षमता में होने वाली

वृद्धि के साथ ही सिंचित क्षेत्रफल में भी वृद्धि स्वाभाविक है। प्रदेश में विभिन्न सिंचाई साधनों द्वारा वास्तविक सिंचित क्षेत्रफल के आंकड़े तालिका 2.1 में दर्शाये गये हैं :—

तालिका 2.1

विभिन्न स्रोतों द्वारा सिंचा गया वास्तविक क्षेत्रफल

[(हजार हे०)]

क्रम-सं०	सिंचाई स्रोत	1973-74	1978-79	1979-80
1	2	3	4	5
1	नहर	2466 (34.1)	3117 (35.1)	2804 (31.5)
2	नलकूप	2607 (36.0)	4207 (47.3)	4828 (54.2)
3	अन्य	2168 (29.9)	1568 (17.6)	1280 (14.3)
	योग	7241 (100.0)	8892 (100.0)	8912 (100.0)

नोट:—कोष्ठक में दिये गये आंकड़े कुल सिंचित क्षेत्र से छोटानुसार प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत:—सिंचाई विभाग एवं कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास विभाग।

तालिकागत आंकड़ों से ज्ञात होता है कि वर्ष 1979-80 में 89.12 लाख हेक्टेयर शुद्ध सिंचित क्षेत्र वर्ष 1973-74 के शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल (72.41 लाख हे०) तथा वर्ष 1978-79 के शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल (88.92 लाख हे०) की तुलना में क्रमशः 23.1 प्रतिशत और 0.2 प्रतिशत अधिक रहा। उक्त आंकड़ों से यह भी प्रतीत होता है कि सिंचित क्षेत्रफल में वृद्धि सिंचन क्षमता में वृद्धि के अनुरूप नहीं हो सकी। अतः सृजित सिंचन क्षमता का उपयोग अपेक्षित गति से नहीं बढ़ रहा है। कुल बोये गये क्षेत्रफल का वर्ष 1973-74 में 42.2 प्रतिशत क्षेत्रफल सिंचाई के अन्तर्गत रहा जो वर्ष 1978-79 में बढ़कर 50.9 प्रतिशत व 1979-80 में 52.4 प्रतिशत हो गया। सिंचाई सघनता जो वर्ष 1973-74 में 117.3 प्रतिशत थी, पांचवीं योजना के अन्तिम वर्ष (1978-79) में शनैः शनैः बढ़ते हुए 118.9 प्रतिशत तथा वर्ष 1979-80 में यह 124.0 प्रतिशत हो गई इसके उपरान्त भी सिंचाई सघनता की दृष्टि से यह प्रदेश अखिल भारतीय औसत 125.2 प्रतिशत से पीछे है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा उड़ीसा जहां कि वर्ष 1977-78 में ही सिंचाई सघनता क्रमशः 172.2 प्रतिशत, 158.1 प्रतिशत, 148.1 प्रतिशत तथा 135.3 प्रतिशत थी, से तो इस प्रदेश में सिंचाई सघनता काको कम है। यह भी देखा गया है कि प्रदेश के शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल में कुये, तालाब आदि अन्य परम्परागत सिंचाई साधनों का योगदान वर्ष 1973-74 के 29.9 प्रतिशत से घटते हुये वर्ष 1979-80 में 14.3 प्रतिशत रह गया है। वर्ष 1973-74 में नहरों का योगदान 34.1 प्रतिशत से बढ़कर पांचवीं योजना के अन्तिम वर्ष 1978-79 में 35.1 प्रतिशत हो गया, किन्तु भयंकर सूखे के प्रभाव स्वरूप वर्ष 1979-80 में गिरकर 31.5 प्रतिशत ही रह गया। दूसरी ओर नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्र का अंश वर्ष 1973-74 के 36.0 प्रतिशत से बढ़ते हुये वर्ष 1978-79 और वर्ष 1979-80 में क्रमशः 47.3 प्रतिशत और 54.2 प्रतिशत के स्तर तक पहुंच गया। इससे यह संकेत मिलता है कि सिंचाई कार्यों में नलकूपों की महत्ता बढ़ती जा ही है।

2.5—सिंचाई की सुविधाओं के प्रसार से रसायनिक उर्वरकों के उपयोग में भी वृद्धि हुई। वर्ष 1978-79 में वितरित 1058 हजार मी० टन रसायनिक उर्वरक वर्ष 1973-74 की तुलना में 128.3 प्रतिशत अधिक था। परिणामतः वर्ष 1973-74 में प्रति हेक्टेयर क्षेत्र पर प्रयुक्त लगभग 20 कि० ग्रा० रसायनिक उर्वरक का उपयोग वर्ष 1978-79 में दो गुने से भी अधिक (43.6 कि० ग्रा० प्रति हेक्टेयर) हो गया। वर्ष 1979-80 में भीषण सूखे के कारण रसायनिक उर्वरकों का कुल प्रयोग गत वर्ष की तुलना में लगभग 4.7 प्रतिशत घटकर 1008 हजार मी० टन रहा। फलस्वरूप वर्ष 1979-80 में प्रति हेक्टेयर क्षेत्र पर प्रयुक्त 42.7 कि० ग्रा० रसायनिक उर्वरक गत वर्ष में प्रयुक्त 43.6 कि० ग्रा० की तुलना में 2.1 प्रतिशत कम रहा। वर्ष 1980-81 में कुल उर्वरक वितरण 1151 हजार मी० टन गत वर्ष की तुलना में 14.2 प्रतिशत अधिक रहा। सरुज बोये गये क्षेत्र पर प्रयुक्त प्रति हेक्टेयर रसायनिक उर्वरक का आर्थिक क्षेत्रवार विवरण तालिका 2.2 में दिया गया है।

तालिका 2.2

प्रति हेक्टेयर सकल बोये गये क्षेत्र पर प्रयुक्त रसायनिक उर्वरक]

(टि० न०)

क्रम- संख्या	आर्थिक क्षेत्र	1978-79	1979-80
1	2	3	4
1	पर्वतीय क्षेत्र	27.7	30.0
2	पश्चिमी क्षेत्र	52.5	52.4
3	केन्द्रीय क्षेत्र	35.0	35.1
4	पूर्वी क्षेत्र	48.3	46.3
5	बुन्देलखण्ड क्षेत्र	11.5	8.4
उत्तर प्रदेश		43.6	42.7

स्रोत—कृषि निदेशालय, उ० प्र०।

उपरोक्त तालिका से यह ज्ञात होता है कि वर्ष 1979-80 में प्रति हेक्टेयर उर्वरक प्रयोग में गत वर्ष की तुलना में राज्य स्तर पर हुई 2.1 प्रतिशत की कमी की तुलना में पूर्वी तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्रों में क्रमशः 4.1 प्रतिशत व 27.0 प्रतिशत की गिरावट आई, पश्चिमी व केन्द्रीय क्षेत्रों में रसायनिक उर्वरक का प्रयोग वर्ष 1979-80 में गत वर्ष के समान ही रहा। जब कि पर्वतीय क्षेत्र में इसमें पर्याप्त वृद्धि हुई। तालिकागत आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1978-79 की ही भांति वर्ष 1979-80 में भी पश्चिमी एवं पूर्वी क्षेत्रों में प्रति हेक्टेयर प्रयुक्त रसायनिक उर्वरक प्रदेश के औसत से अधिक रहा।

2.6—अधिक उपज देने वाली प्रजातियों के अन्तर्गत आच्छादित क्षेत्र पांचवीं योजनावधि में लगभग 55 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 1978-79 में 8239 हजार हेक्टेयर हो गया था किन्तु सूखे के कारण वर्ष 1979-80 में, यह घटकर 7417 हजार हेक्टेयर रहा। वर्ष 1980-81 में अधिक उपज देने वाली प्रजातियों के अन्तर्गत 8823 हजार हेक्टेयर आच्छादित क्षेत्र होने की आशा है, जिसमें 28.9 प्रतिशत क्षेत्र धान, 70.1 प्रतिशत क्षेत्र गेहूँ तथा शेष क्षेत्र मक्का आदि अन्य फसलों के अन्तर्गत होने का अनुमान है।

2.7—उन्नत कृषि विधियों के प्रयोग तथा सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के फलस्वरूप प्रदेश में कुल खाद्यान्न उत्पादन, जो वर्ष 1973-74 में 155.63 लाख मी० टन था, लगभग 48.5 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 1978-79 में 231.08 लाख मी० टन के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया था किन्तु वर्ष 1979-80 में भीषण सूखे के कारण इसमें लगभग 28.9 प्रतिशत की कमी हो गयी तथा वर्ष 1979-80 में खाद्यान्न उत्पादन का स्तर घटकर मात्र 164.39 लाख मी० टन पर पहुँच गया था। खरीफ़ खाद्यान्न उत्पादन 42.91 लाख मी० टन गत वर्ष के उत्पादन का मात्र 51.6 प्रतिशत रहा और रबी ऋतु में ईरिगेशन उपज, शुष्क खेतों एवं मिश्रित खेतों आदि के विविध उपायों के उपरान्त भी रबी खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 18 प्रतिशत की कमी हो गयी। परन्तु वर्ष 1980-81 में अनुकूल वर्षा होने के कारण स्थिति में काफी सुधार हुआ और वर्ष 1980-81 में कुल खाद्यान्न उत्पादन (249.46 लाख मी० टन) गत वर्ष की तुलना में 51.7 प्रतिशत तथा वर्ष 1978-79 के उत्पादन की तुलना में लगभग 8.0 प्रतिशत अधिक रहा। स्पष्ट है कि प्रदेश में कृषि उद्यम अभी भी काफी हद तक प्राकृतिक परिस्थितियों पर निर्भर है। वर्ष 1978-79 में गेहूँ का कुल उत्पादन 114.58 लाख मी० टन था, जो घटकर वर्ष 1979-80 में 98.95 लाख मी० टन रहा था परन्तु वर्ष 1980-81 में गेहूँ उत्पादन 133.85 लाख मी० टन हो गया जो गत वर्ष की तुलना में 35.3 प्रतिशत व वर्ष 1978-79 के उत्पादन से 16.8 प्रतिशत अधिक रहा। इसी प्रकार वर्ष 1980-81 में उत्पादित 224.21 लाख मी० टन धान्य उत्पादन वर्ष 1979-80 व 1978-79 की तुलना में क्रमशः लगभग 50.6 प्रतिशत व 8.1 प्रतिशत अधिक रहा। अरहर का उत्पादन वर्ष 1979-80 में 5.39 लाख मी० टन था जो 1978-79 की तुलना में 16.6 प्रतिशत कम था किन्तु वर्ष 1980-81 में यह पुनः बढ़कर 7.56 लाख मी० टन के स्तर पर पहुँच गया।

2.8—वर्ष 1979-80 में सूखे के कारण कृषिगत वस्तुओं की प्रति हेक्टेयर औसत उपज पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा किन्तु वर्ष 1980-81 में अनुकूल परिस्थितियों के कारण सामान्यतः सभी कृषि वस्तुओं की प्रति हेक्टेयर औसत उपज में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। वर्ष 1980-81 में गेहूँ की प्रति हे० औसत उपज (16.50 कुन्तल) वर्ष 1978-79 की तुलना में 6.4 प्रतिशत अधिक रही। वर्ष 1980-81 में जौ, चना एवं बाजरा की भी क्रमशः 13.25 कुन्तल, 8.61 कुन्तल व 7.37 कुन्तल प्रति हेक्टेयर औसत उपज थी जो वर्ष 1978-79 की तुलना में क्रमशः 15.0 प्रतिशत, 15.1 प्रतिशत व 17.9 प्रतिशत अधिक रही परन्तु वर्ष 1980-81 में चावल की प्रति हेक्टेयर औसत उपज 10.53 कुन्तल वर्ष 1978-79 की 11.59 कुन्तल की अपेक्षा 9.1 प्रतिशत कम रही। दालों के

अन्तर्गत वर्ष 1973-79 को अनेजा अरहर को उत्पादकता वर्ष 1980-81 में 12.2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 14.48 कुन्तल प्रति हेक्टेयर हो गई और कुल दालों को औसत उपज भी जो वर्ष 1978-79 में 7.62 कुन्तल प्रति हेक्टेयर थी, वर्ष 1980-81 में बढ़कर 8.84 कुन्तल प्रति हेक्टेयर हो गई।

2.9—वर्ष 1979-80 में सुख का दुष्प्रभाव गन्ना, तिलहन एवं आलू जैसी वाणिज्यिक फसलों पर भी पड़ा और उक्त वर्ष में इन वस्तुओं का उत्पादन वर्ष 1978-79 की तुलना में क्रमशः 17.8 प्रतिशत, 36.4 प्रतिशत तथा 26.4 प्रतिशत गिरकर 512.28 लाख मी० टन, 9.64 लाख मी० टन तथा 31.63 लाख मी० टन रह गया। परन्तु वर्ष 1980-81 में अनुकूल प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण गन्ना के उत्पादन में वर्ष 1979-80 से 25.3 प्रतिशत का वृद्धि हुई तथा कुल उत्पादन 642.05 लाख मी० टन हुआ जो वर्ष 1978-79 की तुलना में भी 3.0 प्रतिशत अधिक रहा। वर्ष 1979-80 की तुलना में वर्ष 1980-81 में यद्यपि आलू का उत्पादन बढ़कर 41.65 लाख मी० टन हो गया और तिलहन का उत्पादन भी 15.64 लाख मी० टन रहा किन्तु वर्ष 1980-81 में आलू के उत्पादन का स्तर वर्ष 1978-79 से कम रहा।

2.10—अनुकूल कृषि परिस्थितियों के कारण वर्ष 1980-81 में यद्यपि प्रति हेक्टेयर गन्ने को औसत उपज (470.90 कुन्तल) वर्ष 1978-79 की तुलना में 23.4 प्रतिशत अधिक रही किन्तु आलू को प्रति हेक्टेयर औसत उपज (156.66 कुन्तल) तथा तिलहन का प्रति हेक्टेयर औसत उपज (4.11 कुन्तल) वर्ष 1978-79 के लगभग समान रहा।

2.11—पशुपालन कृषि उद्योग का अनुपूरक उद्यम है। इसके द्वारा कृषि पर निर्भर परिवारों को पूरक रोजगार के अवसर सुलभ होते हैं तथा उनका आय में वृद्धि होती है। अतः प्रदेश में उपलब्ध पशु सम्पदा के अनुरक्षण एवं संवर्धन द्वारा पशुपालन व्यवसाय को अधिक लाभदायक बनाने हेतु प्रदेश की छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में 2000 लाख रुपए का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। इस परिव्यय के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 में 293 लाख रुपयों का व्यय किया गया। वर्ष 1981-82 में पशुपालन कार्यक्रमों पर होने वाला 337 लाख रुपयों का संभावित व्यय गत वर्ष के वास्तविक व्यय से 15 प्रतिशत अधिक रहेगा। वर्ष 1978 की पशुगणना के अनुसार प्रदेश में उपलब्ध 523.45 लाख पशु वर्ष 1972 की तुलना में 6.4 प्रतिशत अधिक रहे। वर्ष 1972 की अपेक्षा वर्ष 1978 में कुल गाजातीय एवं कुल गायों की संख्या में क्रमशः 1.8 प्रतिशत व 1.5 प्रतिशत की कमी हुई जबकि दुधारू गायों की संख्या में 5.1 प्रतिशत का वृद्धि हुई। कुल माँहें जातीय एवं कुल भैंसों की संख्या में क्रमशः 10.9 प्रतिशत व 10.4 प्रतिशत वृद्धि के साथ ही दुधारू भैंसों की संख्या में भी 15.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त 1972 की तुलना में 1978 में भड़, बकरे-बकरी सुअर आदि की संख्या में भी पर्याप्त वृद्धि हुई और वर्ष 1978 में उपलब्ध 54.98 लाख कुल कुक्कुट भा वर्ष 1972 की तुलना में 40.3 प्रतिशत अधिक रहे। प्रदेश में उपलब्ध इस विपुल पशु-सम्पदा के अनुरक्षण हेतु वर्ष 1980-81 में 1196 पशु चिकित्सालय वर्ष 1978-79 की तुलना में 3.0 प्रतिशत तथा गत वर्ष की तुलना में 2.6 प्रतिशत अधिक रहे। इनके अतिरिक्त ग्रामीण जनता को निकटस्थ दूरी पर पशुओं की चिकित्सा एवं देखभाल का सुविधा सुलभ कराने के उद्देश्य से पशु विकास केन्द्र स्थापित किये गये हैं। प्रदेश में वर्ष 1980-81 में पशुओं के 170.11 लाख सुरक्षात्मक टाके लगाये गये, जो कि वर्ष 1978-79 व 1979-80 की तुलना में क्रमशः 20.0 प्रतिशत व 2.3 प्रतिशत अधिक रहे। पशुओं का नेस्ल सुधार हेतु कृत्रिम गर्भाधान की सुविधायें सुलभ कराने के उद्देश्य से वर्ष 1978-79 से 743 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र कार्यरत रहे। कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों के अतिरिक्त वर्ष 1980-81 में कार्यरत 1915 कृत्रिम गर्भाधान उप-केन्द्र गत वर्ष के समान किन्तु वर्ष 1978-79 की तुलना में 1.3 प्रतिशत अधिक रहे। इनके अलावा वर्ष 1980-81 में 33 बोर्य संग्रह केन्द्र तथा 2 डीप फ्रीज केन्द्र कार्यरत रहे। वर्ष 1980-81 में 9.77 लाख गायों तथा 7.33 लाख भैंसों को कृत्रिम गर्भाधान सुविधा से लाभान्वित कराया गया, जो कि गत वर्ष लाभान्वित पशुओं की तुलना में क्रमशः 4.9 प्रतिशत तथा 9.2 प्रतिशत अधिक रहे। पशुओं का लैप पोस्टेड चारे की व्यवस्था हेतु वर्ष 1979-80 में 27.4 हजार हेक्टेयर भूमि पर चारा उगाने वाले कालेय कृषकों का चारा बोज एवं चारा पोष उपलब्ध कराई गई। पशुपालन विकास हेतु निरन्तर विभिन्न प्रयासों के परिणामस्वरूप प्रति दुधारू गाय एवं प्रति दुधारू भैंस का दैनिक दुग्ध उत्पादन वर्ष 1979-80 में क्रमशः 1.52 लि० ग्रा० तथा 2.88 कि० ग्रा० गत वर्ष का अपेक्षा क्रमशः 4.3 प्रतिशत तथा 0.7 प्रतिशत अधिक रहा। वर्ष 1979-80 में प्रति मुर्गा प्रति वर्ष 115 अण्डे का उत्पादन गत वर्ष की तुलना में 4.5 प्रतिशत अधिक रहा परन्तु प्रति भेड़ उन उत्पादन में 8.7 प्रतिशत की कमी रही।

2.12—मत्स्य पालन उद्योग प्रदेश वासियों को अनुपूरक रोजगार के अवसर सुलभ कराने के साथ-साथ कुपोषण से पीड़ित जन सन्दाय के लिये प्रोटोन युक्त भोजन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमि का भूदा करता है। छठी योजनावधि (1980-85) में मत्स्य कार्यक्रमों पर 670 लाख रुपयों के स्वीकृत परिव्यय में से वर्ष 1981-82 में 60.00 लाख रुपयों का परिव्यय आवंटित किया गया। सन मत्स्य पालन कार्यक्रमों द्वारा मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करने के प्रयास जारी हैं। वर्ष 1980-81 में मत्स्य विभाग द्वारा उत्पादित 6.54 करोड़, मत्स्य बोज तथा वितरित 4.90 करोड़ मत्स्य बाज पूव वर्ष की तुलना में क्रमशः 37.1 प्रतिशत तथा 49.8 प्रतिशत अधिक रहे। परिणामतः वर्ष 1980-81 में कुल 33.2 हजार मी० टन मत्स्य उत्पादन गत वर्ष की तुलना में 4.4 प्रतिशत अधिक रहा। मत्स्या उत्पादन को और अधिक बढ़ाने हेतु 17 जनपदों में विश्व बैंक पारयोजना के अन्तर्गत ग्राम सभा के तालाबों को पट्टे पर दिलाने, मत्स्य पालन के अल्पकालीन प्रशिक्षण, तालाबों के सुधार, अंगुलिकाओं का आपूर्ति तथा अन्य निवेशों की आपूर्ति हेतु बैंकों के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था कराने के प्रयास किये जा रहे हैं। प्रदेश के अन्य 29 जनपदों में उपर्युक्त कार्यक्रमों हेतु राज्य सरकार द्वारा अभिकरणों की स्थापना भी की जा रही है।

2. 13—वर्ष 1979-80 में प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 17.4 प्रतिशत (5119 हजार हेक्टेयर) क्षेत्र वन के अन्तर्गत था, जो राष्ट्रीय वन नीति के मानक (33.3 प्रतिशत) से बहुत कम है। रक्षित वन प्राकृतिक संसाधन के स्रोतों में से प्रमुख हैं तथा पयोवरण संतुलन बनाये रखने के साथ-साथ जल एवं भू संरक्षण में भी अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। फिर भी भूमि की सीमित उपलब्धता के साथ-साथ जनता की प्रकाष्ठ संबंधित मांगों की आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए वनों के वैज्ञानिक प्रबन्ध, सघन बनीकरण, शीघ्र एवं औद्योगिक महत्व की प्रजातियों के वृक्षारोपण द्वारा वनोपज का यथा सम्भव बढ़ाने के प्रयास जारी हैं। स्थानीय जनता की ईर्ष्य, वन उपज व चारापत्ती की आवश्यकता पूर्ति हेतु वर्ष 1979-80 से वन विभाग द्वारा प्रदेश के 41 मैदानी जनपदों में सामाजिक वानिकी योजना कार्यान्वित की जा रही है, इसके अन्तर्गत बहुउद्देशीय वृक्ष प्रजातियों का वृक्षारोपण किया जा रहा है। यथासम्भव उपलब्ध भूमि का उपयोग वृक्षान्तर्गत लाने के साथ ही सड़कों को अधिक शोभनाय बनाने तथा राहगीरों को छाया प्रदान करने के उद्देश्य से वन विभाग द्वारा सड़कों के किनारे वृक्षारोपण करने का कार्यक्रम भी अपनाया जा रहा है। छठी योजना में "वन" संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों के लिये 8000 लाख रुपये के स्वीकृत परिव्यय में से वर्ष 1980-81 में 1168 लाख रुपये व्यय किये गये तथा 1981-82 में 1648 लाख रुपये व्यय किये जाने की संभावना है। वर्ष 1979-80 में उत्पादित 23.59 लाख घन मी० जलाने की लकड़ी, 162.52 लाख बांस एवं रिंगल तथा 1.42 लाख कुन्तल लीसा पांचवीं योजना के अंतिम वर्ष की तुलना में क्रमशः 0.17 प्रतिशत, 21.0 प्रतिशत तथा 9.2 प्रतिशत अधिक रहा। किन्तु वर्ष 1979-80 में उत्पादित 6.83 लाख घन मीटर इमारती लकड़ी गत वर्ष की अपेक्षा लगभग 18 प्रतिशत कम रही। प्रदेश में उपलब्ध संपूर्ण वनोपज का एक बड़ा अंश पर्वतीय जनपदों में उत्पादित होता है। इसी कारण पर्वतीय क्षेत्र के कुल जिला शुद्ध घरेलू उत्पादन में "वन" का योगदान अन्य-क्षेत्रों की अपेक्षा काफी अधिक रहा। वर्ष 1978-79 (1970-71 के भावों पर) के कुल शुद्ध जिला घरेलू उत्पाद में "वन" खण्ड का योगदान जहाँ पश्चिमी, केन्द्रीय, पूर्वी तथा बृन्देलखण्ड क्षेत्रों में क्रमशः 0.4 प्रतिशत, 0.3 प्रतिशत, 0.9 प्रतिशत तथा 1.1 प्रतिशत था वहीं पर्वतीय क्षेत्र के कुल जिला घरेलू उत्पाद में पाया गया 16.2 प्रतिशत अंश प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में तो कई गुना अधिक रहा ही राज्य स्तर पर पाये गये 1.5 प्रतिशत अंश के भी 10 गुने से अधिक रहा। वर्ष 1979-80 में वनों से प्राप्त 45.18 करोड़ रुपये के राजस्व पांचवीं योजना के अंतिम वर्ष (1978-79) के 42.26 करोड़ रुपये की अपेक्षा 6.9 प्रतिशत अधिक रहे।

2. 14—वर्ष 1970-71 के स्थायी भावों पर वर्ष 1978-79 में प्रदेश में कृषि एवं पशुपालन, वन उद्योग एवं लकड़ी बनाना तथा मत्स्य उद्योग से अर्जित 3050.52 करोड़ रुपये की शुद्ध आय इस वर्ष की कुल राज्य आय की 56.8 प्रतिशत रही। वर्ष 1979-80 में कृषि के लिये प्रतिकूल परिस्थितिया होने के कारण—विशेष रूप से कृषि एवं पशुपालन खण्ड से अर्जित (2214.27 करोड़ रुपये) आय में वर्ष 1978-79 की अपेक्षा 25.9 प्रतिशत की गिरावट आ गई। परिणामतः वर्ष 1979-80 की (1970-71 के स्थायी भावों पर) कुल आय में उपर्युक्त स्रोतों से अर्जित आय का योगदान वर्ष 1978-79 के 56.8 प्रतिशत से गिरकर लगभग 50.6 प्रतिशत रह गया। वर्ष 1980-81 में अनुकूल मौसम होने के कारण कृषि गत उत्पादन में गत वर्ष की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई। वर्ष 1980-81 में विशेष रूप से कृषि एवं पशुपालन खण्ड से अर्जित 3069.11 करोड़ रुपये की आय गत वर्ष की तुलना में 38.8 प्रतिशत अधिक रही। परिणामतः वर्ष 1980-81 की कुल राज्य आय में उपर्युक्त स्रोतों का योगदान वर्ष 1979-80 के 50.6 प्रतिशत से पुनः बढ़कर 56.7 प्रतिशत हो गया जबकि राष्ट्रीय आय में उपर्युक्त स्रोतों का योगदान वर्ष 1979-80 के 39.8 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1980-81 में 41.5 प्रतिशत हुआ।

अध्याय 3

उद्योग, खनिज एवं विद्युत

3. 0—किसी भी क्षेत्र की अर्थ व्यवस्था में उद्योग एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि उद्योगों के विकास से अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ आधार प्रदान किया जा सका है। प्रदेश में नियोजित आर्थिक विकास की प्रक्रिया के अन्तर्गत उद्योगों के विकास हेतु भी निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। प्रदेश में “उद्योग एवं खनिज” विकास कार्यक्रमों पर प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि में वार्षिक औसत व्यय 127.40 लाख रुपये, (कुल वार्षिक औसत व्यय का 4.2 प्रतिशत) था, जो बढ़कर पांचवीं पंच वर्षीय योजनाकाल (1974-79) के कुल वार्षिक औसत व्यय का 6.2 प्रतिशत (3643.20 लाख रुपये) हो गया। प्रदेश की छठी योजना (1980-85) में इन कार्यक्रमों के विकास हेतु औसत वार्षिक परिव्यय 6622 लाख रुपये निर्धारित किया गया है, जो कुल औसत वार्षिक परिव्यय का 5.3 प्रतिशत तथा पांचवीं योजना के वार्षिक औसत व्यय से 81.8 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 1981-82 में उक्त कार्यक्रमों पर वार्षिक औसत परिव्यय कुल परिव्यय का 5.8 प्रतिशत रखा गया है।

3. 1—औद्योगिक विकास की गति की तीव्रता में “उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम” एवं “उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम” का योगदान उल्लेखनीय है। वर्ष 1978-79 में उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा विभिन्न उद्यमियों को 10.89 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई जो क्रमशः 53.2 प्रतिशत और 129.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 1979-80 और वर्ष 1980-81 में क्रमशः 16.68 करोड़ रुपये और 24.99 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुँच गयी। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा वर्ष 1980-81 में प्रदत्त लगभग 2.71 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता वर्ष 1978-79 की 1.30 करोड़ रुपये और वर्ष 1979-80 की 1.46 करोड़ रुपये की तुलना में क्रमशः 108.5 प्रतिशत और 85.6 प्रतिशत अधिक रही।

3. 2—प्रदेश में लघु उद्योगों के विकास एवं प्रसार हेतु विभिन्न अनुसूचित व्यवसायिक बैंकों द्वारा भी लघु औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता ऋण स्वरूप उपलब्ध कराई जा रही है। विभिन्न अनुसूचित व्यवसायिक बैंकों द्वारा प्रदेश में लघु उद्योगों को प्रदत्त ऋणा विशेष संबंधी सूचना नीचे तालिका 3.1 में प्रदर्शित की गई है।

तालिका 3.1

उत्तर प्रदेश में लघु स्तरीय उद्योगों को अनुसूचित व्यवसायिक बैंकों द्वारा प्रदत्त प्रत्यक्ष ऋणावशेष
(अंतिम शुक्रवार की स्थिति)

वर्ष	इकाइयों की संख्या कुल अवशेष ऋण (लाख रु०)	
1	2	3
1974	24064	7014.7
1975	28603	8115.4
1976	45453	10781.4
1977	54616	13714.4
1978(सं)	61858	17925.2
1979(अ)	77547	22868.1

सं०—संशोधित

अ—अनन्तिम

स्रोत :—स्टैटिस्टिकल टेबिलस रिलेटिंग टू बैंस इन इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक।

उक्त तालिका से ज्ञात होता है कि वर्ष 1979 में विभिन्न अनुसूचित व्यवसायिक बैंकों द्वारा लाभान्वित की गई लघु औद्योगिक इकाइयों की संख्या 77547 थी जो वर्ष 1974 और वर्ष 1978 की अपेक्षा क्रमशः लगभग 222 प्रतिशत और 25 प्रतिशत अधिक रही। वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली औद्योगिक इकाइयों के साथ-साथ उन्हें प्राप्त होने वाली वास्तविक धनराशि में भी वृद्धि परिलक्षित हुई। वर्ष 1979 के अन्त में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों पर अवशिष्ट कुल 22868.1 लाख रुपये वर्ष 1974 की तुलना में तीन गुने से भी अधिक (226 प्रतिशत अधिक) तथा गत वर्ष की अपेक्षा लगभग 27.8 प्रतिशत अधिक रहे। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा व्यवसायिक बैंकों की सहायता से भी प्रदेश के औद्योगिक ढांचे को सुदृढ़ करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

3. 3—प्रदेश में उद्योगों के सर्वोन्मुखी विकास हेतु सार्वजनिक, संयुक्त, सहकारी एवं निजी सभी क्षेत्रों में अधिकाधिक औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करने के प्रयास जारी हैं। प्रदेश में वर्तमान स्थिति के अनुसार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में 24 परियोजनाएँ तथा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र में 25 परियोजनाएँ कार्यरत हैं जिनमें क्रमशः 82.9 हजार व्यक्ति तथा 18.2 हजार व्यक्ति रोजगार में लगे हैं। इनके अतिरिक्त केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत 150 करोड़ रुपये के अनुमानित विनियोग की (तेल परिशोधन परियोजना) ग्रायल रिफाइनरी प्रोजेक्ट की स्थापना का कार्य प्रगति पर रहा। संयुक्त क्षेत्र के अन्तर्गत भी 50 करोड़ रुपये लागत की 20 परियोजनाएँ स्थापित की गई हैं, जिनमें से 3.82 करोड़ रुपये के विनियोग द्वारा 700 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने वाली अल्मोडा मैग्नेसाइट लि० तथा 7.70 करोड़ रुपये के विनियोग से 500 व्यक्तियों को रोजगार सलभ कराने वाली यूपी० टवोगा-फाइबर ग्लास लि० उल्लेखनीय रही। संयुक्त क्षेत्र के अन्तर्गत ही उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लि० द्वारा भारत सरकार से 25 परियोजनाओं के लिये प्राप्त आशय/अनुज्ञा पत्रों का कार्यान्वयन भी प्रगति पर रहा। सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत मुख्य रूप से कताई मिलें एवं चीनी मिलें स्थापित की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम द्वारा पच्चीस-पच्चीस हजार तकियों वाली 4 कताई मिलें नगीना, मगहर, डटावा तथा बलन्दशहर तथा 21 चीनी मिलें स्थापित की गई हैं। इसके अतिरिक्त सहकारी क्षेत्र में ही फलपुर इलाहाबाद में 168 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किया जाने वाला रसायनिक उर्वरक कारखाना तथा दलपतपुर में कार्यरत इनफैन्ट फूड बनाने का कारखाना भी उल्लेखनीय उपलब्धि है। निजी क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 1978-79 व 1979-80 में 8.36 करोड़ रुपये विनियोग की 5 परियोजनाओं में उत्पादन प्रारम्भ हुआ।

3. 4—बृहत एवं मध्यम उद्योगों के प्रसार हेतु उद्यमियों को वित्तीय सहायता के साथ-साथ प्राविधिक परामर्श तथा अन्य सहायता प्रदान कर नये उद्योग स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिये वर्ष 1972 में दि. प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त प्रदेश के परम्परागत चीनी तथा वस्त्रोद्योग के बहुमुखी विकास हेतु उ० प्र० राज्य चीनी निगम तथा उ० प्र० राज्य वस्त्र निगम स्थापित किये गये हैं। इलेक्ट्रानिक उद्योग के विकास/प्रसार हेतु यूपी० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन तथा खनिजों पर आधारित उद्योगों के विकास हेतु उ० प्र० राज्य खनिज विकास निगम भी कार्यरत है। उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम के अन्तर्गत प्रदेश की 13 रुग्ण चीनी मिल कार्यरत हैं। उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लि० की सार्वजनिक क्षेत्र में 25000 तकिये प्रतिमिल की क्षमता वाली 8 कताई मिलें, जिनमें 7500 व्यक्तियों की रोजगार प्राप्त था, उत्पादन रत रहीं। यूपी० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन ने संयुक्त क्षेत्र में इलेक्ट्रानिक सम्बन्धित 7 कंपनियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र में 4 कंपनियाँ स्थापित की। उ० प्र० राज्य सीमेंट कारपोरेशन लि० के स्वामित्व में गवर्नमेंट सीमेंट फैक्टरी चर्क तथा गवर्नमेंट सीमेंट फैक्टरी डाला द्वारा सीमेंट का उत्पादन किया जा रहा है। इसी निगम की कजराहट सीमेंट फैक्ट्री, जिसकी उत्पादन क्षमता 1680 हजार टन है, ने भी आलोच्य वर्ष (1981-82) के उत्तरार्ध में उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है। उ० प्र० राज्य खनिज विकास निगम लि० द्वारा संचालित 5 कारखानों में लाइम स्टोन, डोलोमाइट तथा वाक्साइट का उत्पादन हो रहा है।

3. 5—उपर्युक्त बृहत निगमों के अतिरिक्त प्रदेश में उ० प्र० लघु उद्योग विकास निगम लि०, प्रदेश के निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु उ० प्र० निर्यात निगम लि०, कृटीर उद्योग क्षेत्र में जता उत्पादन एवं उनके विक्रय संचालन हेतु यूपी० स्टेट लैडर डेवलपमेंट एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन लि०, ब्रासवेयर उद्योग को अधिक सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित आधार पर चलाने हेतु उ० प्र० राज्य ब्रास वेयर निगम लि० की भी स्थापना की गई।

3. 6—प्रदेश के संगठित क्षेत्र में हुये औद्योगिक विकास का अनुमान वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के आंकड़ों द्वारा लगाया जा सकता है। इस सर्वेक्षण में श्वित सहित न्यूनतम 10 तथा बिना श्वित न्यूनतम 20 श्रमिक वाले कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत कारखानों के सभी पहलुओं की सूचना एकत्र की जाती है। प्रदेश के संगठित क्षेत्र में हुये औद्योगिक विकास सम्बन्धी आंकड़े तालिका 3. 2 में दर्शाये गये हैं।

तालिका 3.2
उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास (संगठित क्षेत्र)

वर्ष	कार्यरत कारखाने जिनसे रिटर्न प्राप्त हुये								
	पंजीकृत कारखाने (संख्या)	कारखाने निवेशित श्रमिक (संख्या)	कारखाने निवेशित श्रमिक (संख्या)	उत्पादन प्रति श्रमिक (हजार रुपये)	उत्पादन प्रति श्रमिक (हजार रुपये)	उत्पादन प्रति श्रमिक (हजार रुपये)	उत्पादन प्रति श्रमिक (हजार रुपये)	उत्पादन प्रति श्रमिक (हजार रुपये)	
1973-74	4450	4303	4174	1823	357	1400	8545
1974-75	5438	4425	4330	2156	406	1764	9129
1975-76	5010	4534	4470	2538	487	1984	7915
1976-77	5602	4719	4648	2724	491	2109	9098
1977-78	5958	5081	5048	3120	534	2421	9846
1978-79 (अ)	6582	5324	5280	3578	538	2761	11023

अ—अनन्तम

@—कारखाना अधिनियम 1948

†—रेलवे एवं प्रतिरक्षा सम्बन्धित कारखानों के अतिरिक्त

स्रोत—वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (अर्थ एवं संख्या प्रभाग)।

तालिकागत आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1978-79 में प्रदेश में 6582 पंजीकृत कारखाने वर्ष 1973-74 के 4450 पंजीकृत कारखानों तथा गत वर्ष 1977-78 के 5958 पंजीकृत कारखानों की अपेक्षा क्रमशः 47.9 प्रतिशत व 10.5 प्रतिशत अधिक रहे। यद्यपि रेलवे एवं प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों के अधीन कारखानों की विस्तृत सूचना उपलब्ध नहीं है फिर भी रेलवे एवं प्रतिरक्षा से सम्बन्धित कारखानों के अतिरिक्त वर्ष 1978-79 में 5324 कार्यरत कारखाने इस वर्ष के कुल पंजीकृत कारखानों के लगभग 81 प्रतिशत थे जो वर्ष 1973-74 के कार्यरत कारखानों की अपेक्षा लगभग 23.7 प्रतिशत अधिक रहे। प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1978-79 में सभी कारखानों में निवेशित 3578 करोड़ रुपये की पूंजी तथा 2761 करोड़ रुपये का उत्पादन वर्ष 1973-74 की अपेक्षा क्रमशः 96.3 प्रतिशत व 97.2 प्रतिशत व गत वर्ष की तुलना में क्रमशः 14.7 प्रतिशत व 14.0 प्रतिशत अधिक रहा। निवेशित पूंजी एवं उत्पादन के अनुरूप इन कारखानों में लगे श्रमिकों की औसत दैनिक संख्या में वृद्धि न हो सकी क्योंकि वर्ष 1978-79 में इन कारखानों में कार्यरत 538 हजार औसत दैनिक श्रमिक वर्ष 1973-74 की अपेक्षा केवल 50.7 प्रतिशत तथा गत वर्ष के औसत दैनिक श्रमिकों की तुलना में 0.7 प्रतिशत अधिक रहे। तालिकागत आंकड़ों से यह भी ज्ञात होता है कि प्रति श्रमिक आवर्धित मूल्य वर्ष 1973-74 के 8545 रु० से बढ़कर वर्ष 1978-79 में 11023 रु० हो गया इस प्रकार आवर्धित मूल्य में उक्त अवधि में 29.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। किन्तु यदि इस अवधि में विनिर्मित वस्तुओं के मूल्य में होने वाली वृद्धि को दृष्टिगत रखा जाय तो यह ज्ञात होगा कि प्रति श्रमिक आवर्धित मूल्य में कोई वृद्धि सम्भव न हो सकी।

3.7—उत्तर प्रदेश के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में हुई औद्योगिक प्रगति से सम्बन्धित आंकड़े नीचे तालिका 3.3 में दर्शाये गये हैं।

तालिका 3.3

उत्तर प्रदेश के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में हुई औद्योगिक प्रगति का स्तर (1978-79)

क्षेत्र	प्रति लाख जन संख्या पर			प्रति श्रमिक आवर्धित मूल्य (रु०)
	कारखाने@ (संख्या)	निवेशित पूंजी (लाख रु०)	श्रमिक (संख्या)	
1	2	3	4	5
1—पर्वतीय क्षेत्र ..	4	194	297	8207
2—पश्चिमी क्षेत्र ..	9	260	672	9919
3—केन्द्रीय क्षेत्र ..	6	1167	1020	11099
4—पूर्वी क्षेत्र ..	2	101	227	14349
5—बुन्देलखंड क्षेत्र ..	1	87	154	12523
उत्तर प्रदेश	5	351	527	11023

@—कार्यरत जिनसे रिटर्न प्राप्त हुये।

स्रोत—वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश।

उपरोक्त तालिका के अनुसार वर्ष 1978-79 में प्रतिलाख जन संख्या पर सर्वाधिक कारखाने पश्चिमी क्षेत्र में (9) और न्यूनतम बुन्देलखंड क्षेत्र में (1) थे। इन आंकड़ों से यह भी विदित होता है कि संगठित क्षेत्र के अन्तर्गत पश्चिमी एवं केन्द्रीय क्षेत्रों की तुलना में अन्य क्षेत्रों में कारखानों का विस्तार कम रहा।

प्रदेश में प्रतिलाख-जनसंख्या पर निवेशित पूंजी औसतन 351 लाख रुपये थी। केन्द्रीय क्षेत्र में यह धनराशि सबसे अधिक 1167 लाख रुपये रही। राज्य के औसत की तुलना में यह तीन गुने से भी अधिक थी अन्य सभी आर्थिक क्षेत्रों की प्रतिलाख जनसंख्या पर निवेशित पूंजी राज्य के औसत से कम रही। इस दृष्टि से पश्चिमी (260 लाख रु०), पर्वतीय (194 लाख रु०), पूर्वी (101 लाख रु०) तथा बुन्देलखंड क्षेत्र (87 लाख रु०) क्रमशः द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ व पांचवे स्थान पर रहे।

प्रतिलाख जनसंख्या पर केन्द्रीय क्षेत्र में 1020 श्रमिक राज्य के औसत (527 श्रमिक) के लगभग दूने रहे। पश्चिमी क्षेत्र में भी ऐसे श्रमिकों (672) की संख्या राज्य के औसत से 27.5 प्रतिशत अधिक रही इनके अतिरिक्त पर्वतीय, पूर्वी व बुन्देलखंड क्षेत्रों की प्रतिलाख जनसंख्या पर क्रमशः 297, 227 व 154 श्रमिक थे जो राज्य के औसत से कम रहे।

यद्यपि प्रतिलाख जनसंख्या पर उपलब्ध कारखाने, निवेशित पूंजी तथा श्रमिकों की दृष्टि से पूर्वी क्षेत्र सभी अन्य आर्थिक क्षेत्रों (बुन्देलखंड क्षेत्र को छोड़ कर) से पीछे रहा किन्तु इस क्षेत्र में प्रति श्रमिक आवधिक मूल्य 14349 रु 0 राज्य के औसत (11023 रु 0) से 30 प्रतिशत अधिक होने के साथ-साथ प्रथम स्थान पर रहा। बुन्देलखंड क्षेत्र, जो अन्य दृष्टिकोण से सभी क्षेत्रों से पीछे था, में भी प्रति श्रमिक आवधिक मूल्य 12523 रु 0 राज्य के औसत से 13.6 प्रतिशत अधिक था और यह क्षेत्र द्वितीय स्थान पर रहा। केन्द्रीय क्षेत्र में प्रति श्रमिक आवधिक मूल्य (11099 रु 0) राज्य के औसत के लगभग समान था। इस दृष्टि से पश्चिमी व पर्वतीय क्षेत्रों का स्थान क्रमशः चौथा व पांचवां रहा।

3.8—प्रदेश के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत औद्योगिक इकाइयों से सम्बन्धित पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण असंगठित क्षेत्र में हुई औद्योगिक प्रगति का कुछ अनुमान 1977 एवं 1980 में सम्पादित आर्थिक गणना के आंकड़ों से लगाया जा सकता है। वर्ष 1980 की आर्थिक गणना के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार भाड़े पर कम से कम एक व्यक्ति रखने वाले लगभग 4.67 लाख अकृषीय संस्थान वर्ष 1977 में ऐसे संस्थानों (3.40 लाख) की तुलना में 37.4 प्रतिशत अधिक रहे। प्रदेश के नगरीय क्षेत्र में पाये गये 2.73 लाख अकृषीय संस्थान वर्ष 1977 की तुलना में दूने से भी अधिक (206.8 प्रतिशत) रहे। भाड़े पर श्रमिक रखने वाले अकृषीय संस्थानों में वर्ष 1980 में, प्रति संस्थान औसतन 6 व्यक्ति भाड़े पर थे, जबकि 1977 में ऐसे व्यक्तियों की संख्या 8 थी वर्ष 1980 में प्रदेश में उपलब्ध कुल अकृषीय संस्थानों (20.81 लाख) के 51.5 प्रतिशत संस्थान ग्रामीण क्षेत्र में तथा 48.5 प्रतिशत संस्थान नगरीय क्षेत्र में कार्यरत थे। प्रदेश में कुल अकृषीय संस्थानों के 77.6 प्रतिशत संस्थान स्वकार्य उद्यम थे। वर्ष 1980 के कुल अकृषीय संस्थानों में कार्यरत कुल 54.70 लाख व्यक्तियों में से 49.4 प्रतिशत व्यक्ति भाड़े पर कार्य करने वाले रहे। नगरीय क्षेत्र के इन संस्थानों में भाड़े पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या कुल कार्यरत व्यक्तियों की 56.1 प्रतिशत थी।

3.9—वर्ष 1978-79 के पश्चात् प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन के उतार चढ़ाव को औद्योगिक उत्पादन (विनिर्माण) सूचकांक से भी आंका जा सकता है। प्रदेश का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (1970-71=100.0) वर्ष 1978-79 में 178.8 था। आगामी वर्ष 1979-80 में पड़े सूखे के कारण कृषिगत कच्चेमाल की आपूर्ति में कमी तथा उद्योगों को मिलने वाली विद्युत में कटौतियों के परिणाम—स्वरूप यह सूचकांक लगभग 16.8 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 1979-80 में 148.8 रहा। वर्ष 1980-81 में गत वर्ष की अपेक्षा यद्यपि कृषि उत्पादन में सुधार हुआ किन्तु औद्योगिक कार्यों हेतु विद्युत आपूर्ति में सुधार के स्थान पर लगभग 1.2 प्रतिशत की गिरावट हो गई जिसके कारण ही कदाचित 'सूती कपड़ा' और 'यातायात एवं उपकरण' जैसे प्रमुख उद्योगों के उत्पादन में क्रमशः 9.2 प्रतिशत तथा 21.1 प्रतिशत की वृद्धि तथा 'ऊनी रेशमी एवं कृत्रिम कपड़ा', 'जूट सन व मेस्ता', 'लकड़ी व लकड़ी के उत्पाद', 'रबर प्लास्टिक आदि के उत्पाद', 'अघातक खनिज', 'मशीनरी' एवं 'बिजली की मशीनरी' जैसे अपेक्षाकृत कम महत्व पूर्ण उद्योगों के उत्पादन में 0.3 प्रतिशत से 32.0 प्रतिशत की वृद्धि के उपरान्त भी 'खाद्य पदार्थ', 'पेय तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद', 'रसायन', जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों के उत्पादन में क्रमशः 6.2 प्रतिशत, 11.4 प्रतिशत, 3.6 प्रतिशत की कमी के साथ-साथ 'कपड़े का उत्पाद', 'कागज मुद्रण एवं प्रकाशन', 'चमड़ा एवं फर उत्पाद', 'मूलधातु एवं मिश्रित धातु', जैसे उद्योगों के उत्पादन में 20.2 प्रतिशत से 1.1 प्रतिशत के मध्य गिरावट आने के कारण वर्ष 1980-81 में प्रदेश में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (151.2) गत वर्ष के सूचकांक से मात्र 1.6 प्रतिशत ही अधिक रहा। वर्ष 1980-81 के औद्योगिक उत्पादन की वर्ष 1978-79 से तुलना करने पर ज्ञात होता है कि 'जूट सन मेस्ता', लकड़ी एवं लकड़ी के उत्पाद, 'रबर प्लास्टिक आदि के उत्पाद' जैसे कतिपय उद्योगों के अतिरिक्त सभी उद्योगों के उत्पादन में 38.7 प्रतिशत से 6.1 प्रतिशत के मध्य गिरावट आने के कारण वर्ष 1980-81 का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 151.2 वर्ष 1978-79 के व्यापक सूचकांक से लगभग 15.4 प्रतिशत कम रहा। वर्ष 1981-82 के प्रथम त्रैमास अप्रैल-जून 1981 में प्रदेश में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो 131.6 था, गत वर्ष के सम्बन्धी त्रैमास के सूचकांक से 12.2 प्रतिशत अधिक रहा।

प्रदेश के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक से सम्बन्धित कुछ वर्षों के आंकड़े निम्न तालिका 3.4 में प्रदर्शित किये गये

तालिका 3.4

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (1970-71=100.0)

उद्योग	1978-79	1979-80	1980-81	1979-80	1978-79
				की तुलना	की तुलना
	†	†	††	में 1980-	में 1980-
				81 में प्रति-	81 में प्रति
				शत वृद्धि/	शत वृद्धि/
				ह्रास	ह्रास
1	2	3	4	5	6
1—खाद्य पदार्थ	162.0	122.8	115.2	(-) 6.2	(-) 28.9
2—पेय, तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद	208.8	154.6	136.9	(-) 11.4	(-) 34.4
3—सूती कपड़ा	90.8	74.9	81.8	(+) 9.2	(-) 9.9

1	2	3	4	5	6
4—ऊनी, रेशमी एवं कृत्रिम कपड़ा ..	116.4	72.4	72.6	(+) 0.3	(-) 37.6
5—जूट, सन एवं मैस्ता ..	164.1	187.2	204.1	(+) 9.0	(+) 24.4
6—कपड़े का उत्पाद ..	71.8	75.3	60.1	(-) 20.2	(-) 16.3
7—लकड़ी एवं लकड़ी के उत्पाद ..	108.7	101.7	134.2	(+) 32.0	(+) 23.5
8—कागज, मुद्रण एवं प्रकाशन ..	306.5	282.2	264.4	(-) 6.3	(-) 13.7
9—चमड़ा एवं फर उत्पाद ..	147.2	155.8	133.9	(-) 14.1	(-) 9.0
10—रबर, प्लास्टिक आदि के उत्पाद ..	414.1	429.9	502.3	(+) 16.8	(+) 21.3
11—रसायन ..	128.2	107.8	103.9	(-) 3.6	(-) 19.0
12—अधात्विक खनिज ..	170.6	155.0	160.2	(+) 3.4	(-) 6.1
13—मूल धातु एवं मिश्रित धातु उद्योग ..	206.4	167.7	165.8	(-) 1.1	(-) 19.7
14—धातु की बनी वस्तुएँ ..	124.4	119.0	100.2	(-) 15.8	(-) 19.5
15—मशीन ..	382.3	280.1	281.9	(+) 0.6	(-) 26.3
16—विजली की मशीनरी ..	343.1	321.9	389.3	(+) 20.9	(+) 13.5
17—यातायात उपकरण एवं पुर्जे ..	201.8	184.4	223.3	(+) 21.1	(+) 10.7
18—विविध ..	171.5	204.0	197.7	(-) 3.1	(+) 15.3
व्यापक सूचकांक ..	178.8	148.8	151.2	(+) 1.6	(-) 15.4

† आंशिक संशोधित

†† अनन्तम

स्रोत—अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उ० प्र० ।

3. 10—प्रदेश के औद्योगिक विकास में खनिजों का महत्वपूर्ण स्थान है। नीचे तालिका 3.5 में प्रदेश में खनिजों के उत्पादन से सम्बन्धित दर्शाये गये आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1979 में विविध प्रकार के 34.14 लाख मी० टन खनिजों का उत्पादन हुआ परन्तु वर्ष 1979 की अपेक्षा वर्ष 1980 में सिलिका सैंड, लाइम स्टोन, तथा मैग्नेसाइट जैसे महत्वपूर्ण उत्पादित खनिजों की मात्रा में क्रमशः 19.9 प्रतिशत, 27.5 प्रतिशत तथा 34.3 प्रतिशत की कमी हो गई। परिणाम स्वरूप कोयले, फास्फोराइट व डोलोमाइट के उत्पादन में क्रमशः 1.9 प्रतिशत, 14.0 प्रतिशत तथा 22.5 प्रतिशत की वृद्धि के उपरान्त भी वर्ष 1980 में उत्पादित 29.82 लाख मी० टन खनिज उत्पादन गत वर्ष की तुलना में 12.7 प्रतिशत कम रहे। यद्यपि वर्ष 1980 में उत्पादित खनिजों की मात्रा में ह्रास हुआ किन्तु मूल्य की दृष्टि से वर्ष 1980 में उत्पादित 2225 लाख रुपये के खनिज गत वर्ष की अपेक्षा 17.7 प्रतिशत अधिक रहे जिसका मुख्य कारण प्रमुख रूप से उत्पादित कोयले, फास्फोराइट व डोलोमाइट के कुल मूल्यों में क्रमशः 35.0 प्रतिशत, 10.5 प्रतिशत, तथा 7.7 प्रतिशत की वृद्धि होना था।

तालिका 3.5

उत्तर प्रदेश में खनिज उत्पादन

खनिज पदार्थ	उत्पादन				वर्ष 1979 की तुलना में 1980 में प्रतिशत वृद्धि	
	मात्रा (000 मी० ट०)		मूल्य (लाख रु०)		मात्रा	मूल्य
	वर्ष 1979	वर्ष 1980	वर्ष 1979	वर्ष 1980		
1	2	3	4	5	6	7
(क) धात्विक						
1—वाक्साइट ..	4	0	1	0	(-) 97.8	(-) 83.9
2—डायस्पोर ..	1	2	4	4	100.0	0.0
(ख) अधात्विक						
1—डोलोमाइट ..	40	49	13	14	22.5	7.7
2—जिप्सम ..	2	1	1	1	(-) 50.0	0.0

1	2	3	4	5	6	7
3-लाइमस्टोन	1425	1033	348	271	(-) 27.5	(-) 22.1
4-मैग्नेसाइट ..	105	69	116	84	(-) 34.3	(-) 27.6
5-ग्रेनाइट ..	4	5	2	3	25.0	50.0
6-फास्फोराइट ..	57	65	86	95	14.0	10.5
7-ग्रेनाइटोसाइट ..	10	11	4	4	10.0	0.0
8-सिलिका सैंड	236	189	44	37	(-) 19.9	(-) 15.9
9-स्टीटाइट ..	9	8	7	5	(-) 11.1	(-) 28.6
10-कोयला ..	1521	1550	1264	1707	1.9	35.0
समस्त ..	3414	2982	1890	2225	(-) 12.7	17.7

नोट:—वर्ष 1979 के आंकड़े संशोधित तथा वर्ष 1980 के आंकड़े अस्थायी हैं।

स्रोत—इण्डियन ब्यूरो ऑफ माइंस, भारत सरकार।

3. 11—खनिजों के महत्व को ध्यान में रखते हुये प्रदेश में उपलब्ध खनिज सम्पदा के सर्वेक्षण, अन्वेषण तथा सिद्धीकरण हेतु प्रदेश में वर्ष 1955 में "भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय" स्थापित किया गया और खानों के विकास, खनिजों के व्यावसायिक उत्पादन एवं निष्पादन तथा खनिजों पर आधारित उद्योगों की स्थापना में तीव्र गति लाने हेतु वर्ष 1974 में "उत्तर प्रदेश खनिज विकास निगम" की स्थापना की गई। प्रदेश में टंगस्टन, ग्रेफाइट, सोना-एवं कीमती पत्थरों के उत्खनन कार्य में तीव्रता लाने के साथ-साथ रसायनिक, स्टील, ग्लास, सिरामिक तथा फास्फेट खाद उद्योगों के लिये आवश्यक खनिजों के उत्पादन पर बल दिया जा रहा है। अतः छठी योजनावधि में 'भूतत्व एवं खनिकर्म' कार्यक्रमों हेतु 1810 लाख रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है, जिसमें से वर्ष 1980-81 में 210 लाख रुपये का व्यय किया गया और वर्ष 1981-82 में 531 लाख रुपये का सम्भावित व्यय वर्ष 1980-81 वास्तविक व्यय से लगभग 152.9 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 1981-82 में खनिज भंडारों की खोज हेतु 33 नवीन सर्वेक्षणों के साथ-साथ अल्मोड़ा तथा पीड़ी गढ़वाल जनपदों में टंगस्टन तथा सोने के भंडारों का विस्तृत सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ किया गया। राज्य खनिज विकास निगम द्वारा भी मंसूरी में लम्बीघर लाइम स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट तथा देहरादून जनपद में कैलशियम कार्बाइड प्रोजेक्ट स्थापित करने का कार्य प्रगति पर रहा। वर्ष 1979-80 में सार्वजनिक क्षेत्र में लगे कुल 17.27 लाख कर्म-करों में खान एवं उत्खनन कार्य में लगे कर्मकरों का अंश केवल 0.2 प्रतिशत था। वर्ष 1979-80 की कुल राज्य आय में इस उद्योग से अर्जित आय का अंश 0.2 प्रतिशत रहा।

3. 12—कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्रों की प्रगति के साथ-साथ मानव जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने में विद्युत का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अतः प्रदेश में विद्युत उत्पादन को यथा सम्भव तीव्रतर गति से बढ़ाने का प्रयास किया गया। प्रदेश में विद्युत उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता कुल उत्पादन तथा उपभोग के आंकड़े तालिका 3.6 में दिए गये हैं।

तालिका 3.6
उत्तर प्रदेश में विद्युत का विकास

वर्ष	अधिष्ठापित क्षमता (में 0 वाट)	कुल उत्पादन (लाख कि० वा० घंटे)	कुल उपभोग (लाख कि० वा० घंटे)
1	2	3	4
1978-79	3076	76880
1979-80	3340	76107
1980-81	3612	78090

स्रोत—केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण एवं उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद्।

तालिकागत आंकड़ों से ज्ञात होता है कि पांचवीं योजना के अन्तिम वर्ष 1978-79 में प्रदेश में विद्युत् उत्पादन की कुल अधिष्ठापित क्षमता 3076 मेगावाट थी, जो लगभग 8.6 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1979-80 में 3340 मेगावाट हो गई तथा पुनः 8.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 1980-81 में 3612 मेगावाट के स्तर पर पहुंच गयी। वर्ष 1980-81 में प्रदेश में उपलब्ध कुल अधिष्ठापित क्षमता राष्ट्र की कुल अधिष्ठापित क्षमता की लगभग 11 प्रतिशत रही। वर्ष 1978-79 में प्रदेश में विद्युत् का कुल उत्पादन 101395 लाख कि० वा० घंटे हुआ था, जो वर्ष 1979-80 में सूखे के कारण घटकर 101334 लाख कि० वा० घंटे रह गया। 1980-81 में विद्युत् उत्पादन में सुधार हुआ और वह गत वर्ष की तुलना में 0.6 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1980-81 में 101905 लाख कि० वा० घंटे हो गया। उत्पादन के साथ-साथ वर्ष 1979-80 में प्रदेश में कुल विद्युत् उपभोग (76107 लाख कि० वाट घंटे) गत वर्ष की अपेक्षा 1.0 प्रतिशत कम रहा। वर्ष 1980-81 में प्रदेश में उपभुक्त 78090 लाख कि० वा० घंटे विद्युत् गत वर्ष की अपेक्षा 2.6 प्रतिशत तथा वर्ष 1978-79 में उपभुक्त विद्युत् की अपेक्षा 1.6 प्रतिशत अधिक रही।

3.13—पांचवीं योजना के अन्तिम वर्ष (1978-79) में प्रदेश में प्रति व्यक्ति विद्युत् उपभोग लगभग 89 कि० वा० घंटे था, जो वर्ष 1979-80 में विद्युत् उत्पादन में गिरावट के कारण घटकर 87 कि० वा० घंटे रह गया। प्रदेश में प्रति व्यक्ति विद्युत् उपभोग में 2.2 प्रतिशत की गिरावट के समक्ष अखिल भारतीय स्तर पर यह गिरावट केवल 0.7 प्रतिशत की रही। वर्ष 1979-80 में प्रति व्यक्ति विद्युत् उपभोग की दृष्टि से यह प्रदेश आसाम (36), हिमाचल प्रदेश (57), जम्मू एवं काश्मीर (73) तथा बिहार (81) के अतिरिक्त सभी राज्यों से पीछे था। प्रदेश में प्रति व्यक्ति विद्युत् उपभोग 87 कि० वाट घंटे पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र तथा अखिल भारतीय औसत का क्रमशः 27.7 प्रतिशत, 36 प्रतिशत, 38.5 प्रतिशत तथा 66.3 प्रतिशत ही रहा।

3.14—जैसा कि निम्न तालिका 3.7 से विदित है कि वर्ष 1978-79, 1979-80 तथा 1980-81 में प्रदेश में 90 प्रतिशत से भी अधिक विद्युत् का उपभोग घरेलू, औद्योगिक तथा सिंचाई एवं जल निकासी कार्यों के लिये हुआ।

तालिका 3.7

उत्तर प्रदेश में उपभुक्त विद्युत् का मदवार प्रतिशत वितरण

मद	1978-79	1979-80	1980-81
1	2	3	4
1—घरेलू कार्य	9.9	10.6	10.2
2—औद्योगिक कार्य	51.7	47.9	46.2
3—सिंचाई एवं जल निकासी	31.4	33.5	35.5
4—अन्य	7.0	8.0	8.1
योग ..	100.0 (76880)	100.0 (76107)	100.0 (78090)

नोट :—कोष्ठ में कुल विद्युत् उपभोग लाख कि० वाट घंटों में है।

स्रोत—केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण एवं उ० प्र० राज्य विद्युत् परिषद्।

यह भी देखा गया है कि यद्यपि औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत् के उपभोग में गिरावट आई और कुल उपभुक्त विद्युत् में इसका अंश वर्ष 1978-79 के 51.7 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 1980-81 में 46.2 प्रतिशत रह गया फिर भी विद्युत् का सबसे अधिक उपभोग इसी क्षेत्र में हुआ। दूसरी ओर प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था में कृषि की महत्ता को देखते हुए सिंचाई कार्यों के लिये विद्युत् आपूर्ति को प्राथमिकता दी गई और सिंचाई एवं जल निकासी कार्यों हेतु उपभुक्त विद्युत् की मात्रा वर्ष 1978-79 में 24146 लाख कि० वा० घंटे से बढ़ते हुए वर्ष 1980-81 में 27726 लाख कि० वा० घंटे हो गई और कुल विद्युत् उपभोग में इसका अंश वर्ष 1978-79 के 31.4 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1980-81 में 35.5 प्रतिशत हो गया। परन्तु वर्ष 1979-80 के विपरीत 1980-81 में घरेलू कार्यों में प्रयुक्त विद्युत् में कुछ गिरावट आई परिणामतः कुल विद्युत् उपभोग में घरेलू कार्यों हेतु प्रयुक्त विद्युत् का अंश जो 1979-80 के 10.6 प्रतिशत था वह घटकर वर्ष 1980-81 में 10.2 प्रतिशत रह गया।

3. 15—प्रदेश में 82 प्रतिशत जन समुदाय, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है उसे विद्युत सुविधा सुलभ कराने की दृष्टि से ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम का सूत्रपात किया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामों/हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण तथा नलकूपों का ऊर्जीकरण किया जाता है। प्रदेश में विद्युतीकृत ग्रामों/हरिजन बस्तियों तथा ऊर्जीकृत नलकूपों की संख्या निम्न तालिका 3. 8 में दी गई है।

तालिका 3.8

उत्तर प्रदेश में विद्युतीकृत ग्राम/हरिजन बस्तियां तथा ऊर्जीकृत नलकूप

वर्ष	विद्युतीकृत		आबाद ग्रामों में विद्युतीकृत ग्रामों का शतांश	ऊर्जीकृत नलकूप (हजार)	
	ग्राम (हजार)	हरिजन बस्ती (संख्या)			
1	2	3	4	5	
1978-79	..	36.3	12,453	32.2	308.0
1979-80	..	38.6	14,014	34.3	344.1
1980-81	..	42.4	16,277	37.6	383.9

स्रोत—केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्।

उपरोक्त तालिका से विदित है कि वर्ष 1978-79 तक प्रदेश क 32.2 प्रतिशत आबाद ग्रामों (36298) को विद्युतीकृत किया जा चुका था। यद्यपि प्रदेश में विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या बढ़ते हुए वर्ष 1980-81 में 42372 हो गई थी फिर भी वर्ष 1980-81 तक इस प्रदेश में कुल आबाद ग्रामों के केवल 37.6 प्रतिशत ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा सका जबकि वर्ष 1979-80 तक हरियाणा, केरल और पंजाब में शत प्रतिशत ग्राम तथा अखिल भारतीय स्तर पर 43.4 प्रतिशत ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका था। वर्ष 1981-82 में सितम्बर 1981 तक 338 अतिरिक्त ग्रामों का विद्युतीकरण किये जाने के उपरान्त प्रदेश में विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या बढ़कर 42710 हो गई है। 1980-81 के अन्त तक विद्युतीकृत 16277 हरिजन बस्तियां वर्ष 1978-79 की तुलना में 30.7 प्रतिशत तथा गत वर्ष की अपेक्षा 16.1 प्रतिशत अधिक थीं। वर्ष 1981-82 में सितम्बर 1981 तक विद्युतीकृत हरिजन बस्तियों की संख्या 16775 हो गई थी। सिंचाई साधनों के रूप में निजी नलकूपों का महत्व उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। जिस कारण अधिक से अधिक संख्या में इन्हें ऊर्जीकृत करने के प्रयास किये गये। वर्ष 1978-79 में प्रदेश में 308.0 हजार निजी नलकूप ऊर्जीकृत थे। वर्ष 1980-81 तक प्रदेश में ऊर्जीकृत नलकूपों की संख्या बढ़कर 383.9 हजार हो गई जो वर्ष 1978-79 की तुलना में 24.6 प्रतिशत तथा गत वर्ष की तुलना में 11.6 प्रतिशत अधिक रही। प्रदेश में निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण के तीव्र प्रयासों का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि जहां वर्ष 1978-79 में कुल निजी नलकूपों के 45.2 प्रतिशत नलकूप ऊर्जीकृत थे, वर्ष 1980-81 में यह शतांश बढ़कर 47.5 हो गया था।

3. 16—'उत्खनन' 'विनिर्माण' तथा 'विद्युत गैस एवं जल सम्पत्ति' खण्डों की (1970-71 के भाव पर) आय में वर्ष 1979-80 में पूर्व वर्ष की अपेक्षा 10.5 प्रतिशत की गिरावट हो गई थी परन्तु वर्ष 1980-81 में इन स्रोतों से अनुमानित आय में वर्ष 1979-80 की तुलना में 10.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 1980-81 में वर्ष 1979-80 की तुलना में कुल राज्य आय में लगभग 22.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि उपर्युक्त स्रोतों से अर्जित आय में केवल 10.1 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई जिस कारण वर्ष 1979-80 की कुल राज्य आय में इन स्रोतों से अर्जित आय का अंश 12.4 प्रतिशत से घटकर वर्ष 1980-81 में केवल 11.1 प्रतिशत रह गया।

अध्याय 4

सड़क परिवहन एवं संचार

4.0—सड़क, परिवहन एवं संचार सुविधाओं का आर्थिक विकास के प्रतिफलों को जन-समुदाय तक पहुंचाने में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। इसी तथ्य को दृष्टि में रखते हुए प्रदेश में इन सुविधाओं के नियोजित विकास हेतु छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) अवधि में कुल परिव्यय का 8.6 प्रतिशत अंश (535 करोड़ रुपये) निर्धारित किया गया। वर्ष 1980-81 में परिवहन एवं संचार सेवाओं पर कुल वार्षिक योजना व्यय का 10.3 प्रतिशत अंश व्यय किया गया तथा वर्ष 1981-82 में यह व्यय 9.7 प्रतिशत होने का अनुमान है।

4.1—सड़कों निर्माण काल में तो रोजगार के अवसर सुलभ कराती ही है, साथ ही निर्माणोपरान्त वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, विपणन तथा उपभोग में सामंजस्य स्थापित कर आर्थिक विकास को गतिमान करने के साथ-साथ राज्य सरकार की राजस्व प्राप्ति में अभिवृद्धि करने में भी सहायक होती है। प्रदेश में सड़कों के विस्तार के अनवरत प्रयासों के परिणामस्वरूप पांचवीं योजना के अंतिम वर्ष (1978-79) में प्रदेश में पक्की सड़कों की कुल लम्बाई 56.7 हजार कि०मी० हो गई थी, जो कि प्रदेश के प्रति 100 वर्ग कि०मी० क्षेत्र पर लगभग 19 कि०मी० तथा प्रति लाख जनसंख्या पर लगभग 56 कि०मी० थी। प्रदेश में अधिक से अधिक ग्रामों को पक्की सड़कों से जोड़ने के प्रयास के फलस्वरूप प्रदेश के कुल 14.8 प्रतिशत ग्राम पक्की सड़कों से जोड़े जा चुके थे। पक्की सड़कों से दूरी के अनुसार प्रदेश के कुल ग्रामों का वितरण तालिका 4.1 में दर्शाया गया है:—

तालिका 4.1

“ ग्रामों का पक्की सड़कों से दूरी के अनुसार प्रतिशत वितरण 31 मार्च, 1979

(अनन्तिम)

आर्थिक क्षेत्र	ग्राम में	1 कि०मी० से कम	1-3 कि०मी०	3-5 कि०मी०	5 कि०मी० या अधिक
1	2	3	4	5	6
1—पर्वतीय क्षेत्र	12.7	6.4	14.2	14.1	52.6
2—पश्चिमी क्षेत्र	16.8	8.9	24.6	19.6	30.1
3—केन्द्रीय क्षेत्र	11.9	7.7	23.4	19.8	37.2
4—पूर्वी क्षेत्र	15.1	11.6	24.5	18.4	30.4
5—बुन्देलखण्ड क्षेत्र	16.0	3.3	15.8	17.8	47.1
उत्तर प्रदेश	14.8	9.3	22.7	18.3	34.9

स्रोत—जनपद में कुछ चुने हुए मदों की सुविधा से दूरी के अनुसार ग्रामों की संख्या, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश।

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि पश्चिमी क्षेत्र के सर्वाधिक 16.8 प्रतिशत ग्राम पक्की सड़कों से जुड़े थे। पूर्वी एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में भी ऐसे ग्रामों का शतांश क्रमशः 15.1 व 16.0 प्रदेश के 14.8 से अधिक रहा, जबकि पर्वतीय क्षेत्र के केवल 12.7 प्रतिशत ग्राम तथा केन्द्रीय क्षेत्र के न्यूनतम 11.9 प्रतिशत ग्राम ही पक्की सड़कों पर स्थित थे। पक्की सड़कों से एक कि०मी० से कम दूरी वाले ग्रामों की संख्या को सम्मिलित करते हुए यह ज्ञात होता है कि पूर्वी क्षेत्र में ऐसे ग्रामों का प्रतिशत अंश सर्वाधिक रहा जबकि पश्चिमी क्षेत्र द्वितीय स्थान पर रहा। 5 कि०मी० या उससे अधिक दूरी पर स्थित ग्रामों का सर्वाधिक अंश (52.6 प्रतिशत) पर्वतीय क्षेत्र में रहा। इस दृष्टि से बुन्देलखण्ड क्षेत्र का दूसरा (47.1 प्रतिशत) तथा केन्द्रीय क्षेत्र (37.2 प्रतिशत) का तृतीय स्थान रहा। पश्चिमी तथा पूर्वी क्षेत्रों में लगभग 30 प्रतिशत ग्राम पक्की सड़कों से 5 कि०मी० से अधिक दूरी पर स्थित थे।

4.2—वर्ष 1979-80 में 3.1 हजार कि०मी० सड़कों के विस्तार, के परिणामस्वरूप वर्ष के अन्त में प्रदेश में उपलब्ध कुल पक्की सड़कों लगभग 59.8 हजार कि०मी० हो गईं। प्रति लाख जनसंख्या पर एवं प्रति 100 वर्ग कि०मी० क्षेत्र पर इन सड़कों की क्षेत्रवार लम्बाई तालिका 4.2 में दी हुई है।

तालिका 4.2

31 मार्च, 1980 की आर्थिक क्षेत्रवार कुल पक्की सड़कों का वितरण

आर्थिक क्षेत्र	कुल पक्की सड़कों की लम्बाई (कि०मी०)	प्रति लाख जनसंख्या पर कुल पक्की सड़कों की लम्बाई (कि०मी०)	प्रति 100 वर्ग कि०मी० क्षेत्रफल पर पक्की सड़कों की लम्बाई (कि०मी०)
1	2	3	4
1—पर्वतीय क्षेत्र	11,593	125.37†	11.34†
2—पश्चिमी क्षेत्र	16,491	44.08	20.07
3—केन्द्रीय क्षेत्र	9,232	50.04	20.13
4—पूर्वी क्षेत्र	18,151	47.43	21.15
5—बुन्देलखण्ड क्षेत्र	4,300	83.54	14.60
उत्तर प्रदेश	59,767	57.52	20.30

†पर्वतीय क्षेत्र की स्थलाकृति के कारण इस क्षेत्र की उपलब्ध वास्तविक सड़कों को आधा करके संगणित किया गया है।

स्रोत—सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।

तालिका 4.2 से विदित है कि वर्ष 1979-80 में पर्वतीय एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में प्रति लाख जनसंख्या पर क्रमशः 125.37 कि०मी० तथा 83.54 कि०मी० सड़कें थीं, जो राज्य के औसत 57.52 कि०मी० की अपेक्षा कहीं अधिक रही जबकि केन्द्रीय, पूर्वी व पश्चिमी क्षेत्रों में प्रति लाख जनसंख्या पर क्रमशः 50.04 कि०मी०, 47.43 कि०मी० तथा 44.08 कि०मी० सड़कें थीं। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह पाया गया कि पर्वतीय एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र, जिनका प्रति लाख जनसंख्या पर सड़कों की लम्बाई में क्रमशः प्रथम व द्वितीय स्थान था, प्रति 100 वर्ग कि०मी० क्षेत्र पर क्रमशः 11.34 कि०मी० तथा 14.60 कि०मी० ही सड़कें थीं और इस दृष्टि से ये क्षेत्र क्रमशः पांचवें एवं चौथे स्थान पर रहे।

4.3—वर्ष 1980-81 में प्रदेश में 2746 कि०मी० नवीन सड़कों का निर्माण, 1004 कि०मी० सड़कों का पुनर्निर्माण तथा 52 सेतुओं का निर्माण किया गया जिस हेतु 89.73 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। परिणामस्वरूप वर्ष 1980-81 के अन्त में प्रदेश में पक्की सड़कों की कुल लम्बाई 62.5 हजार कि०मी० हो जाने की आशा है। इस प्रकार ग्रामों को प्रमुख सड़कों से सम्बद्ध करने के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत 1500 या उससे अधिक जनसंख्या वाले 520 ग्राम तथा 1000 से 1499 जनसंख्या वाले 78 ग्रामों को पक्की सड़कों से जोड़ना संभव हो सका। वर्ष 1981-82 में 1580 कि०मी० नवीन मार्गों के निर्माण, 1080 कि०मी० मार्गों के पुनर्निर्माण तथा 62 सेतुओं के निर्मित किये जाने की संभावना है। अतः आशा है कि 1981-82 के अन्त में प्रदेश में 1500 या उससे अधिक जनसंख्या वाले 58.3 प्रतिशत ग्राम तथा 1000 से 1499 जनसंख्या वाले 26.1 प्रतिशत ग्राम पक्की सड़कों से जुड़ जावेंगे।

4.4—प्रदेश में सड़कों के विस्तार होने के साथ-साथ विभिन्न प्रकार की मोटर गाड़ियों की संख्या में भी वृद्धि दृष्टिगोचर हुई। प्रदेश के मार्गों पर चलने वाली गाड़ियों से सम्बन्धित आंकड़े नीचे तालिका 4.3 में दर्शाये गये हैं।

तालिका 4.3

प्रदेश के सड़क मार्गों पर चलने वाली मोटर गाड़ियों की संख्या

मोटर गाड़ियां	1978-79	1979-80	1980-81	1978-79 1979-80	
	(हजार)	(हजार)	(हजार)	की तुलना में	की तुलना में
1	2	3	4	5	6
1—मोटर साइकिल	191.7	227.7	251.8	31.4	10.6
2—कार	44.1	46.8	46.1	4.5 (-)	1.5
3—बस	12.0	12.0	22.5	87.5	87.5
4—टैक्सी	5.5	6.4	7.5	36.4	17.2
5—ट्रक	27.2	28.6	32.3	18.8	12.9
6—ट्रैक्टर	70.1	83.8	89.7	28.0	7.0
7—अन्य	23.2	25.7	25.7	10.8	0.0
समस्त	373.8	431.0	475.6	27.2	10.3

स्रोत—परिवहन मायुक्त, उ० प्र०

तालिका 4.3 से ज्ञात होता है कि वर्ष 1980-81 में प्रदेश में चालू कुल 475.6 हजार गाड़ियां थीं। जो वर्ष 1978-79 (373.8 हजार) की तुलना में 27.2 प्रतिशत तथा गत वर्ष 1979-80 की अपेक्षा 10.3 प्रतिशत अधिक थीं। वर्ष 1980-81 में सार्वजनिक आवागमन सेवाओं में 22.5 हजार बसें तथा 7.5 हजार टैक्सियां लगी थीं जिनकी संख्या गत वर्ष 1979-80 की तुलना में 87.5 प्रतिशत व 17.2 प्रतिशत अधिक रही। माल यातायात हेतु वर्ष 1980-81 में ट्रकों में भी काफी वृद्धि हुई। जिनकी संख्या वर्ष 1980-81 में 32.3 हजार थी जो वर्ष 1978-79 व 1979-80 की अपेक्षा क्रमशः 18.8 प्रतिशत तथा 12.9 प्रतिशत अधिक थी। मोटर साइकिल अपेक्षा कृत अधिक सुविधाजनक गाड़ी होने के कारण उसकी लोकप्रियता बढ़ रही है और यही कारण है इनकी संख्या में वर्ष 1980-81 में वर्ष 1978-79 की अपेक्षा 31.4 प्रतिशत वृद्धि हुई। इसी प्रकार वर्ष 1980-81 में 89.7 हजार ट्रैक्टर गत वर्ष की तुलना में 7.0 प्रतिशत अधिक थे परन्तु कारों की संख्या में वर्ष 1980-81 में कुछ कमी (1.5 प्रतिशत) हो गई।

4.5—आवागमन एवं यातायात सुविधाओं के प्रसार का सही अनुमान निम्न तालिका 4.4 से लगाया जा सकता है जिसमें प्रति लाख जनसंख्या पर कतिपय मोटर गाड़ियों की संख्या दर्शायी गयी है।

तालिका 4.4

प्रति लाख जन संख्या पर प्रदेश के भागों पर चलने वाली गाड़ियां।

क्रम- संख्या	मोटर गाड़ी	1978-79	1979-80	1980-81
1	2	3	4	5
1	मोटर साइकिल	188	219	227
2	कार	43	45	42
3	बस	12	12	20
4	टैक्सी	5	6	7
5	ट्रक	27	28	29
6	ट्रैक्टर	81	95	99

स्रोत—परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश

उपरोक्त तालिका 4.4 से ज्ञात होता है कि वर्ष 1978-79 में प्रदेश की प्रति लाख जनसंख्या पर 188 मोटर साइकिलें बढ़ते हुए वर्ष 1980-81 में 227 हो गईं। इस प्रकार उपर्युक्त दो वर्षों (1979-81) में प्रति लाख जनसंख्या पर इनकी संख्या में हुई 39 गाड़ियों की वृद्धि (20.7 प्रतिशत) अन्य की अपेक्षा सर्वाधिक रही। इसके विपरीत प्रति लाख जनसंख्या पर कारों की संख्या वर्ष 1980-81 में वर्ष 1979-80 की अपेक्षा 6.7 प्रतिशत तथा वर्ष 1978-79 की अपेक्षा 2.3 प्रतिशत कम रही। सार्वजनिक आवागमन सुविधाओं में प्रयुक्त होने वाली प्रति लाख जनसंख्या पर बसें एवं टैक्सियों की संख्या वर्ष 1978-79 में क्रमशः 12 व 5 से बढ़कर वर्ष 1980-81 में क्रमशः 20 व 7 हो गई। इन्हीं वर्षों में प्रति लाख जनसंख्या पर ट्रकों की संख्या में 2 तथा ट्रैक्टरों की संख्या में 18 की वृद्धि दृष्टिगोचर हुई।

4.6—प्रदेश में यातायात सुविधाओं की पूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कार्यरत है। प्रदेशवासियों को सस्ती एवं सुगम यातायात सेवा सुलभ कराने हेतु इस निगम द्वारा अपने कार्य कलापों का निरन्तर विस्तार किया जा रहा है। इस निगम द्वारा प्रदत्त यातायात सेवाओं के प्रसार सम्बन्धी आंकड़े तालिका 4.5 में दर्शाये गये हैं।

तालिका 4.5

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा प्रदत्त यातायात सेवा का प्रसार

मव	1978-79	1979-80	1980-81
1	2	3	4
1—औसत परिचालित बसें (संख्या)	4,115	4,356	4,391
2—परिचालित मार्ग की औसत लम्बाई (कि०मी०)	132	148	148
3—परिचालित मार्ग (संख्या)	1,652	1,782	1,945
4—औसत दैनिक यात्री (हजार)	1,082	1,227	1,263
5—प्रति यात्री दैनिक औसत आय (₹0, 0.00)	1.71	1.84	2.00

स्रोत—उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम।

उक्त तालिका से ज्ञात होता है कि प्रदेशवासियों को आवागमन की सुविधा सुलभ कराने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की वर्ष 1980-81 में 4391 बसें सेवारत थीं जो वर्ष 1978-79 (4115 बसें) तथा वर्ष 1979-80 (4356 बसें) की तुलना में क्रमशः 6.7 प्रतिशत और 0.8 प्रतिशत अधिक रही। निगम द्वारा कुछ नये मार्गों पर भी बस सेवायें चालू कर दी गईं। यह देखा गया कि वर्ष 1980-81 में परिचालित मार्गों की संख्या 1945 वर्ष 1978-79 और पूर्व वर्ष की अपेक्षा क्रमशः 17.7 प्रतिशत और 9.1 प्रतिशत अधिक रही। यातायात सेवाओं के विस्तार एवं उनमें अभिवृद्धि होने के फलस्वरूप वर्ष 1980-81 के प्रतिदिन औसत लाभान्वित 1263 हजार यात्री गत वर्ष की अपेक्षा 2.9 प्रतिशत तथा वर्ष 1978-79 की तुलना में 16.7 प्रतिशत अधिक रहे।

4.7--सड़कों के विस्तार तथा आवागमन एवं माल यातायात सेवाओं हेतु वाहनों की संख्या में वृद्धि से जनता के लिये आवागमन की सुविधा में वृद्धि के साथ-साथ "माल कर एवं यात्री कर" "तथा वाहनों पर कर" के रूप में राज्य सरकार के राजस्व में भी वृद्धि हुई जैसा कि तालिका 4.6 से भी विदित है।

तालिका 4.6

उत्तर प्रदेश में परिवहन राजस्व एवं कुल राज्य करों में इनका शतांश

(लाख रुपयों में)

वर्ष	मालकर एवं यात्री पर कर	वाहनों पर कर	कुल परिवहन कर	कुल राज्य कर में परिवहन कर का शतांश	
1	2	3	4	5	
1978-79	..	2728	2160	4888	9.6
		(55.8)	(44.2)	(100.0)	
1979-80	..	3661	2440	6101	10.8
		(60.0)	(40.0)	(100.0)	
1980-81	..	4105	2609	6714	10.4
		(61.1)	(38.9)	(100.0)	
1981-82 (पु)	..	5314	2808	8122	10.8
		(65.4)	(34.6)	(100.0)	

पु—पुनरीक्षित अनुमान,

नोट—कोष्ठक में दर्शाये गये आंकड़े कुल परिवहन राजस्व का मदवार प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत—वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश।

वर्ष 1980-81 में राज्य सरकार को परिवहन राजस्व के रूप में 67.14 करोड़ रुपये की आय हुई थी जो वर्ष 1978-79 की तुलना में लगभग 37 प्रतिशत तथा गत वर्ष की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत अधिक रही। वर्ष 1981-82 के लिये 81.22 करोड़ रुपये के अनुमानित परिवहन राजस्व वर्ष 1980-81 की अपेक्षा लगभग 21 प्रतिशत अधिक रहने की आशा है। वर्ष 1981-82 में अनुमानित परिवहन राजस्व कुल राज्य करों के लगभग 10.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है। उक्त आंकड़ों से यह भी ज्ञात होता है कि माल एवं यात्री कर का कुल परिवहन राजस्व में अंश वर्ष 1978-79 में 55.8 प्रतिशत से बढ़ते हुए वर्ष 1981-82 में 65.4 प्रतिशत हो गया।

4.8—जहाँ तक संचार साधनों का सम्बन्ध है, डाक घरों का प्रमुख स्थान है। वर्ष 1978-79 में प्रदेश में कुल 16457 डाकघर थे जो वर्ष 1973-74 की अपेक्षा लगभग 12.9 प्रतिशत अधिक रहे। प्रदेश में डाकघरों की संख्या में वृद्धि का क्रम जारी रहा और वर्ष 1980-81 में इनकी संख्या 17367 हो गई जो गत वर्ष की तुलना में 0.6 प्रतिशत तथा वर्ष 1978-79 की अपेक्षा 5.5 प्रतिशत अधिक थी। डाकघर सेवा के वास्तविक प्रसार के अभिज्ञान हेतु प्रति डाकघर सेवित जनसंख्या के आंकड़े तालिका 4.7 में दर्शाये गये हैं।

तालिका 4.7
उत्तर प्रदेश में डाक घरों का प्रसार

वर्ष	डाकघरों की संख्या	प्रति डाकघर सेवित जन-संख्या
1	2	3
1973-74	14579	6389
1974-75	14598	6500
1975-76	14791	6533
1976-77	15275	6442
1977-78	15768	6355
1978-79	16457	6201
1979-80	17255	6021
1980-81(अ)	17367	6088

(अ)—अनन्तिस

स्रोत—डाक महाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

तालिकागत आंकड़ों से विदित होता है कि वर्ष 1975-76 तक प्रति डाकघर सेवित जनसंख्या में वृद्धि का क्रम जारी रहा किन्तु उसके पश्चात् यह गिरता रहा । वर्ष 1980-81 में प्रति डाकघर सेवित जनसंख्या 6088 रही ।

4.9—संचार सेवाओं के साथ-साथ डाक घर देश/प्रदेश की विभिन्न विकास योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय बचत के रूप में वित्त संसाधन एकत्र कर प्रदेश के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं । पांचवीं योजना के अन्तिम वर्ष (1978-79) में प्रदेश में डाकघरों द्वारा राष्ट्रीय बचत के रूप में कुल 435.23 करोड़ रुपये जमा किये गये, जो कि वर्ष 1979-80 में 6.5 प्रतिशत वृद्धि के साथ 463.35 करोड़ रुपये हो गये । वर्ष 1980-81 में इस धनराशि में गत वर्ष की तुलना में पुनः लगभग 20.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह बढ़कर 559.06 करोड़ रुपये हो गयी । परिणामतः वर्ष 1980-81 में शुद्ध जमा धनराशि 162.85 करोड़ रुपये गत वर्ष की तुलना में लगभग 10.0 प्रतिशत तथा वर्ष 1978-79 की तुलना में 21.4 प्रतिशत अधिक थी । कुल बचत की अपेक्षा शुद्ध बचत में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि होने के कारण कुल बचत में शुद्ध बचत का अंश जो कि वर्ष 1978-79 में 30.8 था, बढ़कर वर्ष 1979-80 में 32.0 हो गया परन्तु वर्ष 1980-81 में कुल जमा धनराशि की तुलना में अधिक धनराशि निकाली गई थी जिस कारण वर्ष 1980-81 की कुल बचत में शुद्ध बचत का अंश घट कर 29.1 रह गया ।

4.10—टेलीफोन त्वरित संचार साधन है । अतः प्रदेश में इसका महत्व बढ़ता ही जा रहा है । वर्ष 1973-74 में प्रदेश में कुल 90419 टेलीफोन कनेक्शन थे, जिनमें पांचवीं योजना अन्तिम में 44.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा वर्ष 1978-79 में इनकी संख्या बढ़कर 130490 हो गई । आगामी वर्ष में इनकी संख्या में पुनः 5.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई और इनकी कुल संख्या वर्ष 1979-80 के अन्त में 137447 थी । प्रदेश में उरलब्ध टेलीफोन सेवा में वृद्धि का वास्तविक अनुमान तालिका 4.8 जिसमें प्रति लाख जनसंख्या पर टेलीफोन कनेक्शन के आंकड़े दर्शाये गये हैं, से लगाया जा सकता है ।

तालिका 4.8
उत्तर प्रदेश में टेलीफोन सुविधाओं में अभिवृद्धि

वर्ष	टेलीफोन कनेक्शन (कार्यरत) (संख्या)	प्रति लाख जनसंख्या पर कार्यरत टेलीफोन कनेक्शन (संख्या)
1	2	3
1973-74	90419	97
1974-75	102098	108
1975-76	109539	114
1976-77	119334	122
1977-78	125733	126
1978-79	130490	128
1979-80	137447	132

स्रोत—महा प्रबंधक दूरसंचार, उत्तर प्रदेश ।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि प्रति लाख जनसंख्या पर वर्ष 1973-74 में 97 टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध थे, जिनकी संख्या बढ़कर वर्ष 1978-79 में 128 तथा वर्ष 1979-80 में 132 हो गई। इस प्रकार पंचम पंचवर्षीय योजनावधि में प्रति लाख जनसंख्या पर टेलीफोन कनेक्शन की संख्या में लगभग 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई और वर्ष 1979-80 में गत वर्ष की तुलना में टेलीफोन कनेक्शन 3.1 प्रतिशत अधिक रहे। प्रति लाख जनसंख्या पर टेलीफोन की संख्या में लगातार वृद्धि इस बात का द्योतक है कि टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या जनसंख्या में वृद्धि की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ी है।

4.11—टेलीविजन का मनोरंजन एवं संचार साधन के रूप में महत्त्व तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, साथ ही व्यापार जगत के लिये विज्ञापन का सफलतम साधन होने के कारण ये प्रदेश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में परोक्ष रूप से सहायक सिद्ध हो रहे हैं। यों तो प्रदेश में यह सुविधा वर्ष 1970 में ही उपलब्ध हो गई थी किन्तु 1974 के उपरान्त से प्रदेश में टेलीविजनों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई। वर्ष 1980 (31 दिसम्बर को) में इनकी संख्या लगभग 160.0 हजार थी, जो कि पूर्वगामी वर्ष (1979) की तुलना में 24.2 प्रतिशत तथा 1974 की अपेक्षा 2461.5 प्रतिशत अधिक रही। यह भी देखा गया कि वर्ष 1980 में प्रदेश की प्रति लाख जनसंख्या पर उपलब्ध 154 टेलीविजन गत वर्ष की अपेक्षा 28 तथा वर्ष 1974 में उपलब्ध 7 टेलीविजन की तुलना में 22 गुने रहे।

4.12—परिवहन एवं संचार खण्ड से अर्जित आय का कुल राज्य आय में योगदान वर्ष 1970-71 में लगभग 3.9 प्रतिशत था, जो बढ़कर 1973-74 में 4.4 प्रतिशत हो गया, किन्तु 1978-79 की कुल राज्य आय में यह अंश 4.3 प्रतिशत रह गया। वर्ष 1980-81 की कुल राज्य आय (1970-71 के भाव पर) में इसके योगदान में पुनः वृद्धि हुई और वह 4.6 प्रतिशत हो गया।

अध्याय 5

सामाजिक सेवाये

5.0—प्रदेश के आर्थिक विकास के साथ-साथ शासन द्वारा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सूचना एवं प्रचार, श्रम-कल्याण, समाज के निर्बल वर्ग के व्यक्तियों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने आदि सम्बन्धी विभिन्न सामाजिक सेवाये भी उपलब्ध कराई जा रही हैं ताकि प्रदेशवासियों की कार्यकुशलता व कार्यक्षमता में निरन्तर अभिवृद्धि होने के फलस्वरूप प्रदेश का सन्तुलित आर्थिक विकास सम्भव हो सके। छठी पंचवर्षीय योजना अवधि (1980-85) में 6200 करोड़ रुपये के स्वीकृत कुल परिव्यय का लगभग 11.1 प्रतिशत अंश उक्त सेवाओं पर व्यय किया जाना प्रस्तावित है। छठी योजना के प्रथम वर्ष 1980-81 में उक्त सेवाओं पर सम्भावित व्यय राज्य की वार्षिक योजना के कुल व्यय का लगभग 11.4 प्रतिशत रहा और वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकृत कुल परिव्यय का लगभग 11.7 प्रतिशत अंश इन सेवाओं के लिये आवंटित किया गया है। स्पष्टतः राज्य सरकार द्वारा सामाजिक सेवाओं के प्रसार पर उत्तरोत्तर बल दिया जा रहा है।

शिक्षा

5.1—मानव के सर्वांगीण विकास एवं उसके आर्थिक उत्थान में शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान के नीति निर्धारक सिद्धान्तों में 14 वर्ष तक की आयु के सभी बालक बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा सुलभ कराने पर बल दिया गया है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु देश एवं प्रदेश में विशेषकर प्राथमिक शिक्षा सुविधाओं के तीव्र प्रसार के अनवरत प्रयास किये जा रहे हैं। पांचवीं योजनाकाल के अन्त तक प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 69244 थी, जो लगभग 2.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 1980-81 में 70931 हो गई। यह वर्ष 1979-80 के 70292 विद्यालयों की तुलना में 0.9 प्रतिशत अधिक थी। इन प्राथमिक शिक्षण संस्थाओं में हुई वृद्धि के साथ ही इनमें कार्यरत अध्यापकों की संख्या में भी वृद्धि हुई। वर्ष 1980-81 में इन संस्थाओं में 244712 अध्यापक कार्यरत थे जिनकी संख्या वर्ष 1978-79 (241298) और वर्ष 1979-80 (243985) की तुलना में क्रमशः लगभग 1.4 प्रतिशत तथा 0.3 प्रतिशत अधिक थी। प्राथमिक शिक्षा संस्थाओं तथा अध्यापकों की संख्या में वृद्धि के विपरीत वर्ष 1980-81 में प्राथमिक शिक्षा संस्थाओं में अध्ययनरत 94.37 लाख विद्यार्थी वर्ष 1978-79 के 118.75 लाख विद्यार्थियों की तुलना में 20.5 प्रतिशत कम थे, किन्तु वर्ष 1979-80 (93.11 लाख) की अपेक्षा वर्ष 1980-81 में छात्रों की संख्या में 1.4 प्रतिशत की वृद्धि दृष्टगोचर हुई। परिणामतः प्रति विद्यालय छात्र संख्या जो वर्ष 1978-79 में 171 थी वह वर्ष 1979-80 में 132 तथा वर्ष 1980-81 में 133 ही रह गयी थी। अध्यापकों की संख्या में वृद्धि होने के फलस्वरूप अध्यापक छात्र अनुपात वर्ष 1978-79 के 1:49 की अपेक्षा वर्ष 1980-81 में 1:39 हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों तथा निर्बल वर्ग के छात्रों की संख्या में अपेक्षित वृद्धि करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर के छात्रों के प्रोत्साहन हेतु बालिकाओं तथा निर्बल वर्ग के बालकों को भी पाठ्य पुस्तकों के वितरणार्थ प्रोत्साहन अनुदान स्वीकृत किये गये तथा वर्ष 1978-79 से प्रति वर्ष निर्बल वर्ग के 40000 बच्चों को पोषाक वितरण के आदेश भी प्रसारित किये जाते रहे। त्वास एवं अवरोध को दूर करने हेतु अब कक्षा 1, 2 व 3 को अलग-अलग न रखकर समन्वित शिक्षा क्रम के अन्तर्गत संचालित किया जा रहा है।

5.2—प्राथमिक शिक्षा के साथ-साथ सीनियर बेसिक तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा सुविधाओं के प्रसार के प्रयास भी जारी हैं। पांचवीं योजना काल के अन्त में प्रदेश में सीनियर बेसिक स्कूल तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या क्रमशः 11428 तथा 4671 थी जिसके पश्चात् वर्ष 1980-81 तक इनकी संख्या क्रमशः 17.3 प्रतिशत और 11.5 प्रतिशत बढ़कर 13407 व 5210 हो गयी, और यह गत वर्ष की तुलना में क्रमशः 2.1 प्रतिशत और 5.2 प्रतिशत अधिक रही। वर्ष 1978-79 में पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या 1653 हजार थी किन्तु वर्ष 1979-80 में यह 16 प्रतिशत से कम होकर 1389 हजार ही रह गई। वर्ष 1980-81 में इन विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या में सुधार हुआ और गत वर्ष की अपेक्षा लगभग 2.2 प्रतिशत की वृद्धि होने के फलस्वरूप इनकी संख्या 1420 हजार हो गई। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की संख्या वर्ष 1980-81 में 3364 हजार थी जो पांचवीं योजना काल के अन्तिम वर्ष (1978-79) तथा गत वर्ष की तुलना में क्रमशः 7.5 प्रतिशत और 3.4 प्रतिशत अधिक रही। यह भी देखा गया कि वर्ष 1980-81 में प्रदेश के पूर्व माध्यमिक विद्यालयों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक-छात्र अनुपात, क्रमशः 1:21 और 1:30 रहा।

5.3—प्रदेश के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में वर्ष 1980-81 में शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति की स्थिति की जानकारी निम्न तालिका 5.1 से हो सकती है।

तालिका 5.1

प्रदेश में वर्ष 1980-81 में उपलब्ध शिक्षण-सुविधाओं का क्षेत्रवार स्थिति

शिक्षा स्तर	पर्वतीय क्षेत्र	पश्चिमी क्षेत्र	केंद्रीय क्षेत्र	पूर्वी क्षेत्र	बुन्देलखण्ड क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
प्रति विद्यालय छात्र संख्या						
उच्चतर माध्यमिक	367	670	784	660	730	646
सीनियर बेसिक	54	118	105	116	76	106
जूनियर बेसिक	71	135	136	153	107	133

प्रति अध्यापक छात्र संख्या

उच्चतर माध्यमिक . . .	22	31	32	30	32	30
सीनियर बेसिक . . .	13	24	21	20	20	21
जूनियर बेसिक . . .	30	38	40	41	37	39

स्रोत—शिक्षा निदेशालय

उपरोक्त तालिका के अनुसार जहाँ केन्द्रीय तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्रों में क्रमशः 784 तथा 730 छात्रों पर एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय था, वहीं पर्वतीय क्षेत्र में लगभग उतनी ही छात्र संख्या पर ऐसी दो संस्थायें थीं। इसी प्रकार प्रति सीनियर व जूनियर बेसिक स्कूल में न्यूनतम छात्र संख्या पर्वतीय क्षेत्र में ही थी। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में भी प्रति सीनियर/जूनियर बेसिक स्कूल छात्र संख्या स-पूर्ण प्रदेश के औसत से कम रही। इसी प्रकार उच्चतर माध्यमिक, सीनियर बेसिक तथा जूनियर बेसिक स्तर पर प्रदेश में प्रति अध्यापक छात्रों की औसत संख्या क्रमशः 30, 21 एवं 39 थी। पर्वतीय क्षेत्र में प्रति अध्यापक छात्र संख्या स-पूर्ण प्रदेश की तुलना में कम रही और अन्य सभी क्षेत्रों में प्रति अध्यापक छात्रों की औसत संख्या राज्य के औसत के लगभग समतुल्य रही।

5. 4—स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षा हेतु गत वर्ष की भांति वर्ष 1980-81 में भी (विश्वविद्यालय मानी गयी गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय सहारनपुर के अतिरिक्त) 19 विश्वविद्यालय कार्यरत रहे किन्तु डिग्री कालेजों की संख्या जो वर्ष 1978-79 में 368 थी, उनकी संख्या बढ़ कर वर्ष 1980-81 में 384 हो गई। यद्यपि डिग्री कालेजों की संख्या में वर्ष 1978-79 व 1980-81 की अवधि में 4.3 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई परन्तु इन संस्थाओं में वर्ष 1980-81 में कार्यरत 19403 अध्यापक वर्ष 1978-79 के 16923 अध्यापकों की अपेक्षा 14.7 प्रतिशत अधिक थे। इन शिक्षा संस्थाओं तथा अध्यापकों की संख्या में वृद्धि के साथ ही उनमें विद्यार्थियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई। वर्ष 1980-81 में इन संस्थाओं में 451 हजार विद्यार्थी थे जिनकी संख्या वर्ष 1978-79 के 412 हजार तथा वर्ष 1979-80 के 433 हजार विद्यार्थियों की तुलना में लगभग 9.5 प्रतिशत तथा 4.2 प्रतिशत अधिक रही।

5. 5—शिक्षण सुविधाओं के प्रसार के फलस्वरूप प्रदेश में साक्षरता का स्तर, जो वर्ष 1971 में 21.7 प्रतिशत था, बढ़ कर वर्ष 1981 में 27.4 प्रतिशत हो गया। इसके विपरीत अखिल भारतीय स्तर पर वर्ष 1971-81 की अवधि में साक्षरता प्रतिशत 29.4 से बढ़कर 36.2 हुआ। अतः यद्यपि साक्षरता के क्षेत्र में वृद्धि प्रदेश में अपेक्षाकृत कुछ अधिक ही रही फिर भी इस दृष्टि से यह प्रदेश अखिल भारतीय स्तर (36.2 प्रतिशत) से काफी पीछे तो है ही राजस्थान (24.0 प्रतिशत) एवं बिहार (26.0 प्रतिशत) को छोड़कर अन्य सभी राज्यों का अनुगामी रहा।

5. 6—प्रदेश के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में साक्षरता स्तर का विवरण नीचे तालिका 5.2 में दिया गया है।

तालिका 5.2

1971-81 के दशक में साक्षरता का प्रसार

क्रम- संख्या	आर्थिक क्षेत्र	1971	1981*	साक्षरता प्रतिशत में वृद्धि
1	2	3	4	5
1	पर्वतीय क्षेत्र	31.0	39.4	8.4
2	पश्चिमी क्षेत्र	22.3	28.2	5.9
3	केन्द्रीय क्षेत्र	22.9	28.5	5.6
4	पूर्वी क्षेत्र	19.4	24.6	5.2
5	बुन्देलखण्ड क्षेत्र उत्तर प्रदेश	22.5 21.7	28.7 27.4	6.2 5.7

*ग्रस्थाई

स्रोत—भारतीय जनगणना 1971 व 1981।

उपरोक्त आंकड़ों से विदित है कि शिक्षा की दृष्टि से अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा पूर्वी क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। वर्ष 1971 की ही भांति वर्ष 1981 में भी पूर्वी क्षेत्र में साक्षरता का स्तर सबसे नीचे रहा और अन्य सभी आर्थिक क्षेत्रों में साक्षरता का स्तर प्रदेश के औसत साक्षरता स्तर 27.4 प्रतिशत से अधिक रहा। पर्वतीय क्षेत्र 39.4 प्रतिशत साक्षरता स्तर के साथ सभी आर्थिक क्षेत्रों में अग्रणी रहा। 1971-81 के दशक में जहाँ केन्द्रीय क्षेत्र के साक्षरता

प्रतिशत में प्रदेश के लगभग समतुल्य 5.6 की वृद्धि हुई वहीं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में यह वृद्धि 6.2 की रही और साक्षरता की दृष्टि से बुन्देलखण्ड क्षेत्र जो वर्ष 1971 में तृतीय स्थान पर था, 28.7 प्रतिशत साक्षरता स्तर के साथ वर्ष 1981 में द्वितीय स्थान पर आ गया। इसके अतिरिक्त वर्ष 1981 में केन्द्रीय, पश्चिमी तथा पूर्वी क्षेत्रों में साक्षरता का स्तर क्रमशः 28.5 प्रतिशत, 28.2 प्रतिशत तथा 24.6 प्रतिशत रहा और ये क्षेत्र क्रमशः तृतीय, चतुर्थ तथा पाँचवें स्थान पर रहे।

5.7—प्रदेश में काफी अधिक संख्या में (लगभग 72.6 प्रतिशत) व्यक्ति निरक्षरों की श्रेणी में आते हैं। अतः प्रदेश में साक्षरता के तीव्र प्रसार हेतु अन्य उपायों के साथ-साथ वय-वर्ग 6-11 वर्ष के बच्चों की अनौपचारिक शिक्षा हेतु 5600 तथा वय-वर्ग 11-14 वर्ष के बच्चों की अनौपचारिक शिक्षा हेतु 1600 केन्द्र स्थापित किये गये हैं जहाँ ग्रंथ कालिक शिक्षा दिये जाने का प्रबन्ध किया गया है। साथ ही साथ प्रदेश से निरक्षरता उन्मूलन की दिशा में प्रौढ़ शिक्षा कार्य-क्रम की ओर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। छठी योजनावधि (1980-85) में 15-35 वर्ष आयु वर्ग के 1.17 करोड़ व्यक्तियों को साक्षर बनाने हेतु 3.81 लाख प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 में 32 जनपदों में 300-300 केन्द्रों वाली 32 परियोजनाएँ प्रारम्भ की गयीं। इनके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा भी 300-300 केन्द्रों वाली दो परियोजनाएँ दो मँदानी जनपदों में तथा 100 केन्द्र वाली एक परियोजना एक पर्वतीय जनपद में प्रारम्भ की गईं।

5.8—प्रदेश में तीन स्तरीय तकनीकी शिक्षा पद्धति चालू है। वर्ष 1980-81 में स्नातक स्तर की आठ संस्थाएँ, डिप्लोमा स्तर की 47 तथा प्रमाण-पत्र स्तर की 67 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएँ कार्यरत रहीं। इन संस्थाओं की प्रवेश क्षमता क्रमशः 1120, 8130 तथा 26800 है। यद्यपि प्राविधिक शिक्षा का उद्देश्य रोजगार सृजित करने वाले सार्वजनिक संस्थानों की आवश्यक जनशक्ति की सम्पूर्ति रहा है किन्तु अब अभियन्तण स्नातकों एवं डिप्लोमा धारकों को स्वतः रोजगार तथा उद्यम की ओर प्रेरित करने हेतु प्राविधिक शिक्षा कार्य क्रम के अन्तर्गत उत्पादन युक्त प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना तथा उत्पादन विकास और प्रबन्ध प्रशिक्षण की योजनाएँ भी सम्मिलित की गई हैं।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

5.9—एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति त्वरित लाभ पहुँचाने की क्षमता के कारण अधिक लोकप्रिय है, अतः जन आकांक्षाओं के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा भी एलोपैथिक चिकित्सा सेवाओं के प्रसार तथा उसके स्तर को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों सहित एलोपैथिक चिकित्सालय एवं शोधालय वर्ष 1980 के अन्त में 3187 थे जो वर्ष 1978 तथा वर्ष 1979 की तुलना में क्रमशः लगभग 6.9 प्रतिशत तथा 1.7 प्रतिशत अधिक थे। वर्ष 1978 व 1980 की अवधि में चिकित्सालयों/शोधालयों की संख्या में वृद्धि जनसंख्या में वृद्धि के ही अनुरूप रही। चिकित्सालय/शोधालयों की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ उनमें उपलब्ध चिकित्सकों तथा शैय्याओं में भी वृद्धि हुई। वर्ष 1979 के अन्त में उपलब्ध 6592 चिकित्सक थे जो वर्ष 1978 की तुलना में लगभग 7.8 प्रतिशत अधिक थे। परिणामतः प्रति दस लाख जनसंख्या पर उपलब्ध चिकित्सकों की संख्या वर्ष 1978 में 60 से बढ़कर वर्ष 1979 में 63 हो गयी। प्रदेश में एलोपैथिक चिकित्सालयों एवं शोधालयों में शैय्याओं की संख्या में भी वर्ष 1979 में पूर्व वर्ष की अपेक्षा 3.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यदि शैय्याओं की उपलब्धता का आर्थिक क्षेत्रवार अध्ययन किया जाय तो ज्ञात होगा कि वर्ष 1979 में प्रदेश की कुल प्रक्षिप्त जनसंख्या के पर्वतीय तथा केन्द्रीय क्षेत्र में क्रमशः 4.4 प्रतिशत तथा 17.8 प्रतिशत अंश पर क्रमशः 11.1 प्रतिशत तथा 23.2 प्रतिशत शैय्याएँ उपलब्ध थीं, बुन्देलखण्ड क्षेत्र में प्रदेश की कुल 4.9 प्रतिशत जनसंख्या पर 4.9 प्रतिशत शैय्याएँ उपलब्ध थीं जबकि पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्र में क्रमशः 36.9 प्रतिशत तथा 36.0 प्रतिशत जनसंख्या पर क्रमशः 30.4 प्रतिशत तथा 30.4 प्रतिशत शैय्याएँ उपलब्ध थीं। स्पष्टतः प्रदेश में जनसंख्या के अनुपात में शैय्याओं की उपलब्धता पर्वतीय एवं केन्द्रीय क्षेत्र में अधिक तथा पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्र में कम रही। चिकित्सा सुविधा के सम्बन्ध में देखा गया कि वर्ष 1980 में 32115 हजार रोगी चिकित्सित हुये जिनकी संख्या गत वर्ष (1979) की तुलना में लगभग 1.5 प्रतिशत तथा वर्ष 1978 की तुलना में लगभग 3.0 प्रतिशत अधिक थी।

5.10—वर्ष 1981-82 में फाइलेरिया एवं मलेरिया, जैसे संचारी रोगों की रोकथाम हेतु फाइलेरिया नियंत्रण इकाईयों तथा फाइलेरिया क्लिनिक की स्थापना, मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम का 11 जनपदों में प्रसार, कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कुष्ठ नियंत्रण केन्द्र एवं कुष्ठ नियंत्रण इकाईयों की स्थापना, अंधेपन की रोक-थाम हेतु सभी जनपदीय अस्पतालों में नेत्र अनुभाग उपलब्ध कराने तथा 6 सचल नेत्र चिकित्सा इकाईयों को प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है।

5.11—ग्रामीण जनता के स्वास्थ्य स्तर को ऊँचा उठाने तथा उन्हें चिकित्सा सुविधा मुलभ कराने हेतु वर्ष 1981-82 में 10 नवीन अस्पतालों की स्थापना, 23 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के उन्नयन, 100 गौण (सबसीडियरी) हेल्थ सेन्ट्रों की स्थापना तथा विशिष्ट सेवा सुविधा प्रदान करने हेतु जिला अस्पतालों में 14 ई0 एन0 टी0 अनुभाग एवं तहसील स्तरीय अस्पतालों में 9 दन्त रूजालय खोलने का प्रस्ताव है।

5.12—एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के साथ-साथ आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति को भी राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। वर्ष 1980-81 के अन्त में प्रदेश में आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति के 1269 राजकीय चिकित्सालय एवं शोधालय थे, जो वर्ष 1978-79 की तुलना में 10.4 प्रतिशत तथा वर्ष 1979-80 की तुलना में लगभग 5.3 प्रतिशत अधिक रहे। साथ ही वर्ष 1980-81 में इन शोधालय/चिकित्सालयों में उपलब्ध क्रमशः 3888 शैय्याएँ तथा 1287 डाक्टर भी वर्ष 1978-79 की तुलना में क्रमशः 15.2 प्रतिशत

तथा 10.6 प्रतिशत अधिक तथा गत वर्ष की अपेक्षा क्रमशः 7.3 प्रतिशत तथा 5.1 प्रतिशत अधिक रहे। इन सुविधाओं के प्रसार के फलस्वरूप वर्ष 1980-81 में इस पद्धति द्वारा 110.88 लाख रोगियों का उपचार हुआ जिनकी संख्या वर्ष 1978-79 की तुलना में 11.0 प्रतिशत एवं वर्ष 1979-80 में उपचारित रोगियों की तुलना में 3.8 प्रतिशत अधिक रही। योग एवं पंचकर्म जैसे आयुर्वेदिक विशिष्ट चिकित्सा सेवा से जनता को लाभान्वित करने हेतु वर्ष 1979-80 में राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ में एक केंद्र स्थापित किया गया तथा वर्ष 1981-82 में ऐसे ही एक और केंद्र की स्थापना तथा 57 आयुर्वेदिक शोधालय खोलने एवं एक क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का भी लक्ष्य है।

5.13—होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा सुलभ कराने हेतु पांचवीं योजना के अन्त (1978-79) में प्रदेश में 260 चिकित्सालय/शोधालय, 158 शैथ्यायें तथा 272 चिकित्सक उपलब्ध थे। वर्ष 1979-80 के अन्त तक इन चिकित्सालय/शोधालयों की संख्या बढ़कर 295 तथा चिकित्सकों की संख्या 307 हो गई। वर्ष 1981-82 में 85 नये होम्योपैथिक शोधालय स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

पेयजल सम्पत्ति

5.14—स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ पेयजल भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। पेयजल की समस्या हल करने की ओर भी सरकार का निरन्तर प्रयास जारी है। इन प्रयासों के फलस्वरूप पांचवीं योजना के अन्त तक प्रदेश में 388 नगरों तथा 8587 ग्रामों को नल द्वारा स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी थी। 1979-81 की अवधि में 46 अतिरिक्त नगरों तथा 3015 ग्रामों को यह सुविधा उपलब्ध कराने के फलस्वरूप वर्ष 1980-81 के अन्त तक प्रदेश में कुल 644 नगरों में से लगभग दो तिहाई नगर (434) तथा केवल 10 प्रतिशत ग्रामों (11602) को ही नल द्वारा स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध करायी जा सकी। स्वच्छ पेयजल सुलभ कराने की दिशा में अवशिष्ट कार्य का अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वर्ष 1980-81 तक प्रदेश के 35506 अभावग्रस्त ग्रामों में से केवल 22.3 प्रतिशत (7912) ग्रामों को ही यह सुविधा सुलभ कराई जा सकी। जल सम्पत्ति एवं जलोत्सारण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1981-82 में जन निगम द्वारा 20 अतिरिक्त नगरों तथा 2700 ग्रामों को स्वच्छ पेय जल की सुविधा सुलभ कराने का लक्ष्य है। जिस हेतु ₹0 56.70 करोड़ का प्राविधान किया गया है। ग्राम्य विकास विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की हरिजन तथा पिछड़े वर्ग की बस्तियों को मैदानी क्षेत्र में कुओं/हैण्डपम्प तथा पर्वतीय क्षेत्र में डिग्गियों के निर्माण द्वारा पेयजल सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। वर्ष 1981-82 में 200 लाख ₹0 के परिव्यय से मैदानी क्षेत्र में 1552 कुओं, 2000 हैण्ड पम्प तथा पर्वतीय क्षेत्र में 500 डिग्गियों के निर्माण के लक्ष्य की पूर्ति का कार्य प्रगति पर रहा।

5.15—जलोत्सारण कार्यक्रम के अन्तर्गत मार्च 1980 तक प्रदेश के 42 नगरों में आंशिक जलोत्सारण की सुविधा सुलभ कराई जा चुकी थी। वर्ष 1980-81 में 3 नये नगरों में जलोत्सारण व्यवस्था उपलब्ध कराई गई तथा पंचमहानगरियों एवं 3 नगरों में जलोत्सारण व्यवस्था के पुनर्गठन का कार्य प्रगति पर रहा। वर्ष 1981-82 में भी 3 नये नगरों में जलोत्सारण सुविधा सुलभ कराने का प्रयास किया गया।

5.16—आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने के साथ-साथ जनसंख्या की वृद्धि दर पर नियंत्रण रखने एवं परिवार आकार को छोटा रखने हेतु जनसाधारण को अनुर्वरीकरण एवं लूप निवेशन की सुविधायें सुलभ कराई गईं। वर्ष 1980-81 में 11977 पुरुषों तथा 66461 महिलाओं द्वारा अनुर्वरीकरण सेवाओं का लाभ उठाया गया। इस प्रकार वर्ष 1980-81 में कुल 78,438 अनुर्वरीकृत व्यक्ति वर्ष 1978-79 के 29,255 तथा वर्ष 1979-80 के 56,530 अनुर्वरीकृत व्यक्तियों की तुलना में क्रमशः 168.1 प्रतिशत और 38.8 प्रतिशत अधिक रहे।

5.17—लगभग 25 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सामाजिक एवं आर्थिक उन्नयन हेतु अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम स्थापित किया गया है। इस निगम द्वारा 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर माजिन मनी ऋण तथा अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त वर्ष 1978-79 से स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत विभिन्न विकास विभागों द्वारा इस वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु वित्तीय व्यवस्था करते हुए भौतिक लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं। वर्ष 1981-82 में कुल आयोजनागत परिव्यय का 11.1 प्रतिशत अंश स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान हेतु निर्धारित किया गया तथा 171 करोड़ रुपये की धनराशि सहकारिता तथा बैंक ऋण के रूप में प्राविधानित की गई और वर्ष 1981-82 में 4.5 लाख परिवारों को यथा सम्भव लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।

5.18—विशेषकर समाज के निर्बल वर्ग के लोगों को कुपोषण एवं असंतुलित आहार के दुष्प्रभाव से बचाने हेतु न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को पुष्टाहार योजना के अन्तर्गत प्रोटीन युक्त भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई।

निःसन्देह ये सभी कार्यक्रम प्रदेश में उपलब्ध जन-शक्ति की कार्यक्षमता व कार्य कृशता बढ़ाने में परोक्ष रूप से सहायक होकर प्रदेश एवं प्रदेशवासियों के आर्थिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं।

अध्याय 6

श्रम शक्ति एवं सेवायोजन

6. 0—उत्पादन प्रक्रिया में श्रम एक अपरिहार्य निवेश (इनपुट) है। अतः प्रदेश एवं प्रदेशवासियों की आर्थिक समृद्धि प्रदेश में उपलब्ध श्रम-शक्ति के अधिकतम एवं विवेकपूर्ण उपयोग पर निर्भर है। इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि कर्मकरों को उनकी रुचि एवं योग्यता के अनुरूप रोजगार सुलभ कराने के साथ-साथ श्रमिकों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण की ऐसी समुचित व्यवस्था हो जिससे प्रदेश में उद्योगों के लिये पर्याप्त मात्रा में कुशल एवं दक्ष श्रमिकों की पूर्ति सुनिश्चित की जा सके। प्रदेश में श्रम विभाग के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय इस दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। इस निदेशालय की सेवायोजन शाखा रोजगार इच्छुक व्यक्तियों को चयन हेतु सेवायोजकों के पास भेजती है। इस प्रकार यह कार्यालय रोजगार इच्छुक व्यक्तियों को रोजगार ढूढ़ने में सहायता प्रदान करने के साथ-साथ सेवायोजकों को उपयुक्त कर्मचारी सुलभ करता है। साथ ही निदेशालय द्वारा अपनी देख-रेख में संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा औद्योगिक एवं प्राविधिक संस्थानों के माध्यम से जन-शक्ति के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जाती है।

6. 1—1981 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में 32303 हजार मुख्य कर्मकर तथा 2965 हजार सीमान्त कर्मकर पाये गये। इस प्रकार प्रदेश में वर्ष 1981 में कुल 35268 हजार कर्मकर वर्ष 1971 के 27334 हजार कर्मकरों की तुलना में 29.0 प्रतिशत अधिक रहे। 1971-81 के दशक में प्रदेश की जनसंख्या में हुई 25.52 प्रतिशत की वृद्धि के समक्ष इस अवधि में कर्मकरों की संख्या में 29.0 प्रतिशत की वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप प्रदेश की कुल जनसंख्या में कर्मकरों का शतांश वर्ष 1971 में 30.9 से बढ़ कर वर्ष 1981 में 31.8 हो गया। कुल जनसंख्या में कर्मकरों के शतांश सम्बन्धी आंकड़े तालिका 6.1 में दर्शाये गये हैं।

तालिका 6.1

उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कर्मकरों का शतांश

मद	1971 कर्मकरों का शतांश	1981 (अस्थायी) में कर्मकरों का शतांश		
		मुख्य कर्मकर	सीमान्त कर्मकर	कुल कर्मकर
1	2	3	4	5
पुरुष	52.2	49.6	1.9	51.5
स्त्री	6.7	6.0	3.5	9.5
ग्रामीण	31.5	29.6	3.0	32.6
नगरीय	27.7	27.2	1.1	28.3
उत्तर प्रदेश	30.9	29.1	2.7	31.8

(स्रोत—भारतीय जनगणना 1971, 1981)

उपर्युक्त तालिका से ज्ञात होता है कि यद्यपि वर्ष 1981 में पुरुष, स्त्री, ग्रामीण, नगरीय तथा प्रदेश की कुल जनसंख्या में मुख्य कर्मकरों का शतांश वर्ष 1971 की तुलना में कम रहा किन्तु वर्ष 1981 में मुख्य कर्मकरों के साथ-साथ सीमान्त कर्मकरों की श्रेणी में रखे गये कर्मकरों को भी सम्मिलित करने पर पता चलता है कि वर्ष 1981 में कुल पुरुषों के 51.5 प्रतिशत पुरुष कर्मकर वर्ष 1971 के 52.2 प्रतिशत पुरुष कर्मकरों की तुलना में कम रहे। जबकि अन्य सभी वर्गों में कर्मकरों का प्रतिशत अंश वर्ष 1981 में वर्ष 1971 की अपेक्षा अधिक रहा। इन आंकड़ों से यह भी विदित होता है कि प्रदेश में स्त्री जनसंख्या में स्त्री कर्मकरों का प्रतिशत अंश, जो वर्ष 1971 में 6.7 था बढ़कर वर्ष 1981 में 9.5 हो गया। 1971-81 के दशक में स्त्री जनसंख्या में स्त्री कर्मकरों के अंश में अन्य वर्गों की जनसंख्या में कर्मकरों के अंश की अपेक्षा अधिक वृद्धि हुई। स्त्री जनसंख्या में स्त्री कर्मकरों के अंश में हुई वृद्धि के कारण ही पुरुष जनसंख्या में पुरुष कर्मकरों के शतांश में गिरावट के उपरान्त भी प्रदेश की कुल जनसंख्या में कुल कर्मकरों के शतांश में वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त वर्ष 1971 की ही भांति वर्ष 1981 में भी ग्रामीण जनसंख्या में कर्मकरों का शतांश 32.6 नगरीय जनसंख्या में कर्मकरों के शतांश 28.3 से अधिक रहा।

6. 2—वर्ष 1971 की जनगणनानुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में श्रम-शक्ति (15-59 वर्ष की आयु वर्ग) का अंश 51.4 प्रतिशत था। यद्यपि समस्त स्त्री वर्ग में महिला श्रम-शक्ति का अंश 51.9 प्रतिशत, पुरुष जनसंख्या में पुरुष श्रम-शक्ति (50.9 प्रतिशत) की तुलना में अधिक था, किन्तु स्त्री श्रम शक्ति का केवल 10.7 प्रतिशत भाग ही कर्मकरों की श्रेणी में था। इसी कारण पुरुष श्रम शक्ति के 86.9 प्रतिशत कर्मकर होने के उपरान्त भी प्रदेश की कुल श्रम-शक्ति का केवल 50.9 प्रतिशत अंश ही कर्मकरों की श्रेणी में पाया गया। वर्ष 1981 की जनगणना सम्बन्धी विभिन्न आयु वर्गानुसार आंकड़े अभी अनुपलब्ध हैं, ऐसी स्थिति में वर्ष 1981 की जनसंख्या में श्रम-शक्ति तथा श्रम-शक्ति में कर्मकरों के अंश पर प्रकाश डालना सम्भव नहीं है।

6.3—उपलब्ध श्रमिकों को रोजगार सुलभ कराने में सार्वजनिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वर्ष 1978-79 के अन्त में प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र में सेवायोजित व्यक्तियों की संख्या लगभग 16.95 लाख थी। आगामी वर्ष (1979-80) में मऊनाथ भंजन में कटाई मिल के कर्मचारियों की बहाली तथा भूमि संरक्षण, वन सेवाओं, टेक्सटाइल वस्त्र, सीमेन्ट तथा चूना उत्पादन, वायुयान के अंगों का निर्माण, सड़क निर्माण, भवन निर्माण, सग्रहण सेवाओं तथा अन्य सामुदायिक सेवाओं के विस्तार हेतु की गई नवनियुक्तियों के परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र में सेवारत व्यक्तियों की संख्या वर्ष 1979-80 के अन्त में बढ़कर लगभग 17.38 लाख हो गई। सार्वजनिक क्षेत्र में सेवा के अवसर प्रदान करने में सामुदायिक, सामाजिक एवं अन्य व्यक्तिगत सेवाओं का स्थान सर्वोपरि है और गत वर्ष की भांति वर्ष 1979-80 में भी सार्वजनिक क्षेत्र में सेवारत कुल व्यक्तियों में से आधे से भी अधिक व्यक्ति (52.1 प्रतिशत इन्हीं सेवाओं में कार्यरत थे। उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1979-80 में "यातायात, भण्डार एवं संचार" "उत्पादन" तथा "निर्माण उद्योगों" में लगे कर्मचारी सार्वजनिक क्षेत्र में लगे कुल कर्मचारियों के क्रमशः 18.7 प्रतिशत, 8.3 प्रतिशत तथा 8.2 प्रतिशत थे।

6.4 सार्वजनिक क्षेत्र में लगे व्यक्तियों की संस्थान वर्गानुसार सूचना तालिका 6.2 में दर्शायी गयी है।

तालिका 6.2

संस्थान वर्गानुसार सार्वजनिक क्षेत्र में लगे व्यक्ति

संस्थान वर्ग	संख्या लाख में		गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	वर्ष 1979-80 के कुल कर्मचारियों का प्रतिशत वितरण
	1978-79	1979-80*		
1	2	3	4	5
1—केन्द्रीय सरकार	4.30	4.36	1.4	25.1
2—राज्य सरकार	6.36	6.57	3.3	37.8
3—अर्द्ध सरकारी संस्थानों:—				
(1) केन्द्रीय	1.37	1.45	5.8	8.3
(2) राज्य	1.80	1.85	2.8	10.7
4—स्थानीय निकाय	3.12	3.15	1.0	18.1
समस्त	16.95	17.38	2.5	100.0

*अनन्तिम

स्रोत:—प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश।

उपरोक्त तालिका के अनुसार वर्ष 1979-80 में गत वर्ष की अपेक्षा राज्य सरकार के कर्मचारियों की संख्या में 3.3 प्रतिशत, केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार की अर्द्ध सरकारी संस्थाओं में सेवारत व्यक्तियों की संख्या में क्रमशः 5.8 प्रतिशत तथा 2.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो कि प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र में लगे कुल व्यक्तियों की संख्या में हुई 2.5 प्रतिशत वृद्धि की अपेक्षा अधिक रही। जबकि यह वृद्धि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा स्थानीय निकायों में सेवायोजित व्यक्तियों की संख्या में क्रमशः केवल 1.4 प्रतिशत व 1.0 प्रतिशत ही रही। यह भी देखा गया कि वर्ष 1979-80 में सार्वजनिक क्षेत्र में लगे कुल व्यक्तियों के 25.1 प्रतिशत व्यक्ति केन्द्र सरकार, 37.8 प्रतिशत व्यक्ति राज्य सरकार, 19.0 प्रतिशत व्यक्ति अर्द्ध सरकारी संस्थाओं तथा शेष 18.1 प्रतिशत व्यक्ति स्थानीय निकायों में सेवारत रहे।

6.5—वर्ष 1980-81 में निजी क्षेत्र में कुल सेवायोजित 5.63 लाख व्यक्तियों में से 86.3 प्रतिशत व्यक्ति बृहद संस्थानों (एकट संस्थानों) तथा शेष 13.7 प्रतिशत व्यक्ति लघु संस्थानों (नान एकट संस्थानों) में कार्यरत थे। वर्ष 1980-81 में निजी क्षेत्र के बृहद संस्थानों में सेवायोजित व्यक्तियों की संख्या में गत वर्ष (1979-80) की अपेक्षा लगभग 1.6 प्रतिशत तथा लघु संस्थानों में सेवायोजित व्यक्तियों की संख्या में 3.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र में सेवायोजित व्यक्तियों की संख्या में 3.2 प्रतिशत की वृद्धि के विपरीत निजी क्षेत्र में वर्ष 1980-81 में सेवायोजित कुल 5.63 लाख व्यक्ति गत वर्ष के 5.53 लाख व्यक्तियों की तुलना में केवल 1.8 प्रतिशत अधिक रहे।

6.6—उपलब्ध श्रम-शक्ति को रोजगार सुलभ कराने में विभिन्न प्रकार के उद्योगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तालिका 6.3 में प्रदेश के संगठित क्षेत्र के उद्योगों में सेवायोजन सम्बन्धी आंकड़े दर्शाये गये हैं।

तालिका 6.3

प्रदेश के उद्योगों (संगठित क्षेत्र) में सेवायोजन

वर्ष	उद्योगों में लगे श्रमिक (हजार)	सूचकांक (1973-74 =100)	प्रति लाख जन संख्या पर श्रमिक संख्या
1	2	3	4
1973-74	357	100.0	383
1974-75	406	113.7	428
1975-76	487	136.4	504
1976-77	491	137.5	499
1977-78	534	149.6	533
1978-79*	538	150.7	527

*अनन्तिम।

स्रोत—वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण, उत्तर प्रदेश।

उपरोक्त आंकड़ों से ज्ञात होता है कि प्रदेश में संगठित क्षेत्र के उद्योगों में वर्ष 1978-79 में सेवा-योजित 538 हजार श्रमिक वर्ष 1973-74 की तुलना में 50.7 प्रतिशत तथा गत वर्ष की अपेक्षा 0.7 प्रतिशत अधिक रहे। इस प्रकार पंचम पंच वर्षीय योजना अवधि में इन उद्योगों के कर्मचारियों में 50 प्रतिशत वृद्धि हुई। प्रदेश में प्रति लाख जनसंख्या पर औद्योगिक श्रमिकों की संख्या वर्ष 1973-74 की 383 से बढ़कर वर्ष 1978-79 में 527 हो गई।

6.7—जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, रोजगार इच्छुक अभ्यर्थियों को उपयुक्त सेवायोजन के अवसर खोजने तथा सेवायोजकों को कुशल एवं दक्ष कर्मचारी उपलब्ध कराने में प्रदेश में सेवायोजन कार्यालय अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। यद्यपि वर्ष 1980 में इन कार्यालयों द्वारा पंजीकृत 791.9 हजार रोजगार इच्छुक अभ्यर्थी तथा इन कार्यालयों के माध्यम से 37.1 हजार सेवायोजित व्यक्ति गत वर्ष की तुलना में क्रमशः 11.7 प्रतिशत तथा लगभग 24.2 प्रतिशत कम रहे, किन्तु वर्ष 1981 में जनवरी से सितम्बर 1981 की अवधि में पंजीकृत 621.7 हजार अभ्यर्थी तथा इन कार्यालयों के माध्यम से 32.5 हजार सेवायोजित व्यक्ति गत वर्ष की सम्वादी अवधि में पंजीकृत अभ्यर्थियों की तुलना में 6.5 प्रतिशत तथा सेवायोजित व्यक्ति 11.2 प्रतिशत अधिक रहे।

6.8—सेवायोजन कार्यालय की सजीव पंजिका के अनुसार वर्ष 1980 के अन्त में प्रदेश के सेवा-योजन कार्यालयों के रिकार्ड पर 13.64 लाख रोजगार इच्छुक अभ्यर्थी उपलब्ध थे। ऐसे व्यक्तियों का व्याव-सायिक वर्गीकरण तालिका 6.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 6.4

उत्तर प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों की सजीव पंजिका पर उपलब्ध अभ्यर्थियों का उद्यमवार वर्गीकरण।

उद्यम वर्ग	वर्ष 1980 के अन्त में उपलब्ध अभ्यर्थी (लाख)	कुल अभ्यर्थियों का प्रतिशत वितरण
1	2	3
1—व्यवसायिक तकनीकी तथा सम्बन्धित व्यवसायों के अभ्यर्थी	0.74	5.4
2—प्रशासकीय अनुपालकीय तथा प्रबन्धकीय	0.00	0.0
3—लिपिक तथा सम्बन्धित	0.45	3.3
4—विक्रय	0.01	0.1
5—सेवा	0.53	3.9
6—कृषि, मत्स्य, शिकार तथा उनसे सम्बन्धित	0.04	0.3
7—उत्पादन एवं सम्बन्धित, परिवहन उपकरण चालक तथा श्रमिक	1.13	8.3
8—अन्य (अवर्गीकृत)	10.74	78.7
समस्त	13.64	100.0

स्रोत:—प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश।

उपरोक्त आंकड़ों से प्रतीत होता है कि सजीव पंजिका पर उपलब्ध समस्त अभ्यर्थियों में से 78.7 प्रतिशत अभ्यर्थी ऐसे थे, जिनका व्यवसायिक वर्गीकरण अनुपलब्ध है। कदाचित्त यह अभ्यर्थी, किसी भी प्रकार के व्यवसाय में रोजगार प्राप्त करने को तत्पर रहे हों। यह भी देखा गया कि उत्पादन एवं सम्बन्धित, परिवहन उपकरण चालक तथा श्रमिक और "व्यावसायिक, तकनीकी, तथा सम्बन्धित" व्यवसाय वर्गों में रोजगार के इच्छुक क्रमशः 1.13 लाख तथा 0.74 लाख अभ्यर्थी कुल अभ्यर्थियों के क्रमशः 8.3 प्रतिशत तथा 5.4 प्रतिशत रहे। "लिपिक" एवं "सेवा" वर्ग के अभ्यर्थी भी कुल अभ्यर्थियों के क्रमशः 3.3 प्रतिशत व 3.9 प्रतिशत रहे। यद्यपि प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों की सजीव पंजिका पर रोजगार इच्छुक 13.64 लाख अभ्यर्थी उपलब्ध थे फिर भी वर्ष 1980 में इन कार्यालयों द्वारा प्रदेश के विभिन्न प्रतिष्ठानों को सर्वेयर, वोटनिस्ट, केमिस्ट, फारमेसिस्ट, आशु लिपिक (हिन्दी/अंग्रेजी), फायर फाइटिंग आपरेटर, मोल्डर्स, कटर एण्ड पालिशर, वीवर, कार्पेंट वीवर, वर्कशाप इन्स्ट्रक्टर (यांत्रिक), आर्मेचर वाइण्डर तथा अनुभवी हिन्दी/अंग्रेजी कम्पोजीटर जैसे प्रशिक्षित कर्मकर उपलब्ध कराना सम्भव नहीं हो सका।

6.9—राष्ट्रीय सेवायोजन संस्था की वर्किंग ग्रुप कमेटी की संस्तुतियों के अनुसार वर्ष 1963 में सेवायोजन निदेशालय में एक विशेष सेवायोजन कार्यालय स्थापित किया गया जो स्नातक, इंजीनियर, आर्कीटेक्ट, मेट्रोलोजिस्ट, स्नातक पशु चिकित्सक, तकनीकी क्षेत्र में स्नातक, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, कास्ट एकाउन्टेन्ट, एक्चुरीज, केन्द्रीय/राज्य सरकारों के भूतपूर्व राजपत्रित अधिकारी, लेफ्टिनेन्ट या उससे उच्च पद वाले भूतपूर्व सैनिकों का पंजीयन करके उन्हें उपयुक्त सेवायोजन के अवसर प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। प्रदेश में वर्ष 1979 एवं वर्ष 1980 में क्रमशः 2058 तथा 1879 अभ्यर्थियों का पंजीयन किया गया तथा कार्यालय द्वारा क्रमशः 62 व 67 अभ्यर्थियों को सेवायोजित कराया गया।

6.10 - सभी रोजगार चाहने वालों को सर्वतनिक रोजगार सुलभ कराना सम्भव नहीं है। अतः बेरोजगारी की समस्या को यथा सम्भव नियंत्रित करने के उद्देश्य से शासन द्वारा सेवा योजन निदेशालय में सितम्बर, 1978 में स्वतः नियोजन कक्ष की स्थापना की गई। सेवायोजन कार्यालयों द्वारा स्वतः नियोजन के सम्बन्ध में विभिन्न विभागों, सरकारी निगमों, एजेंसियों तथा वित्तीय संस्थाओं और बैंकों से विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत दी जाने वाली सहायता/सुविधाओं के सम्बन्ध में स्वतः नियोजन हेतु इच्छुक पंजीकृत अभ्यर्थियों को व्यापक जानकारी उपलब्ध कराकर उन्हें स्वनियोजन हेतु प्रेरित किया जा रहा है। वर्ष 1980 में स्वतः नियोजन हेतु अधिकाधिक लोगों को प्रेरित करने के उद्देश्यों से 3613 स्वतः नियोजन हेतु सम्पर्क स्थापित किये गये तथा स्वतः नियोजन हेतु क्रमशः 8991 सामूहिक वार्तायें तथा 373 गोष्ठी/बैठकें आयोजित की गयीं जो कि गत वर्ष के क्रमशः 1269 सम्पर्क, 6149 वार्तायें तथा 291 गोष्ठीयों की अपेक्षा काफी अधिक रही। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप वर्ष 1980 में 2368 स्वनियोजित व्यक्तियों गत वर्ष के स्वनियोजित व्यक्तियों (646) की तुलना में तीन गुने से भी अधिक रहे। इसके साथ ही वर्ष के अन्त तक स्वतः नियोजन पंजिका पर उपलब्ध 11476 अभ्यर्थी गत वर्ष की अपेक्षा 93 प्रतिशत अधिक रहे। स्पष्टतः प्रदेश में इन कार्यालयों के माध्यम से व्यक्तियों को स्वतः नियोजन हेतु प्रेरित करने में काफी सहायता मिल रही है, जो कि प्रदेश में व्याप्त बेरोजगारी एवं अर्द्ध बेरोजगारी को शीघ्र नियंत्रित करने में सहायक सिद्ध होगी।

अध्याय 7

प्रदेश की आर्थिक प्रत्याशयें

7.0—प्रदेश की अर्थ व्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित होने के फलस्वरूप कृषि एवं सम्बन्धी आर्थिक कार्यकलापों को यथा सम्भव विकसित करने के प्रयास किये जा रहे हैं। यद्यपि अति वृष्टि एवं अनावृष्टि के दुष्परिणामों के कारण प्रदेश का कृषि उत्पादन लगभग प्रत्येक वर्ष प्रतिकूल रूप में प्रभावित होता है जिससे प्रदेश के अधिक विकास की गति में अवरोध उत्पन्न होता है। फिर भी सिंचित क्षेत्र और द्विफसली क्षेत्र में वृद्धि करने तथा उन्नत कृषि विधियों का प्रयोग करके कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के निरन्तर प्रयास किये जाते रहे हैं। वर्ष 1981-82 में सकल सिंचित क्षेत्रफल गत वर्ष की अपेक्षा 9 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 151 लाख हेक्टेयर होने पर सकल बोये गये क्षेत्रफल में सकल सिंचित क्षेत्रफल का अंश गत वर्ष के 55.9 प्रतिशत से बढ़कर 60.4 प्रतिशत होने की संभावना है। वर्ष 1981-82 में फसल सघनता 140.2 प्रतिशत तक होने की आशा है जो गत वर्ष (139.1) की अपेक्षा 0.8 प्रतिशत अधिक होगी। वर्ष 1981-82 में 13.44 लाख मी० टन रासायनिक उर्वरकों का सम्भावित वितरण गत वर्ष की अपेक्षा लगभग 17 प्रतिशत अधिक रहेगा जिसके फलस्वरूप प्रति हेक्टेयर उर्वरकों का उपयोग 54.6 कि० ग्रा० के स्तर तक पहुँचने की आशा है। इस प्रकार समग्र रूप से वर्ष 1981-82 में प्रदेश में कुल खाद्यान्न, गन्ना, तिलहन और आलू के निर्धारित उत्पादन लक्ष्य, क्रमशः 269 लाख मी० टन, 700 लाख मी० टन, 17 लाख मी० टन और 45 लाख मी० टन की पूर्ति करना संभव हो सकेगा।

7.1— प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र में चीनी, वनस्पति, सीमेंट तथा सूती वस्त्र प्रमुख उद्योग हैं। वर्ष 1979-80 में प्रदेश के औद्योगिक उत्पादन में, विद्युत् आपूर्ति में कमी होने के कारण, गत वर्ष की अपेक्षा लगभग 18 प्रतिशत का ह्रास हुआ था किन्तु वर्ष 1980-81 में औद्योगिक उत्पादन की स्थिति में कुछ सुधार अवश्य हुआ। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1981-82 की प्रथम छमाही (अप्रैल-सितम्बर, 1981) में वनस्पति उत्पादन 78112 मी० टन गत वर्ष की सम्वादी अवधि के उत्पादन की तुलना में 37.6 प्रतिशत अधिक रहा। अप्रैल-सितम्बर, 1980 की अवधि में उत्पादित 24.65 हजार मी० टन चीनी के विपरीत अप्रैल-सितम्बर, 1981 की अवधि में चीनी का उत्पादन 57.95 हजार मी० टन हुआ, किन्तु सीमेंट के उत्पादन में कुछ कमी हुई। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अनुसार वर्ष 1981-82 के प्रथम त्रैमास (अप्रैल-जून, 1981) में प्रदेश के औद्योगिक उत्पादन का व्यापक सूचकांक (1970-71 = 100) 131.6 गत वर्ष के सम्वादी त्रैमास के सूचकांक की तुलना में 12.2 प्रतिशत अधिक रहा। सन्दर्भित वर्ष में प्रदेश के औद्योगिक उत्पादन में काफी प्रगति होने की आशा है।

7.2 आर्थिक विकास एवं जन साधारण के जीवन स्तर के समुन्नतीकरण में विद्युत् के महत्व को ध्यान में रखते हुये प्रदेश में विद्युत् उत्पादन क्षमता में अभिवृद्धि के अनवरत प्रयास जारी है। वर्ष 1980-81 में प्रदेश में कुल अधिष्ठापित क्षमता 3612 मेगावाट थी, जो भारत की कुल अधिष्ठापित क्षमता की लगभग 11 प्रतिशत रही। वर्ष 1981-82 में विद्युत् कार्यक्रमों पर होने वाले कुल सम्भावित व्यय का 62.9 प्रतिशत अंश विद्युत् उत्पादन हेतु सुलभ कराया गया जिस कारण वर्ष 1981-82 में ग्रानपारा एक्सटन्शन II तथा III द्वारा प्रदेश के विद्युत् अधिष्ठापन क्षमता में 200 मेगावाट की वृद्धि होने की संभावना है। विद्युत् उत्पादन क्षमता में वृद्धि के साथ-साथ वर्ष 1980-81 में प्रदेश में उत्पादित 101905 लाख कि० वा० घंटे विद्युत् गत वर्ष की तुलना में 0.6 प्रतिशत अधिक रही। वर्ष 1981-82 में अप्रैल-सितम्बर, 1981 की अवधि में प्रदेश में उत्पादित लगभग 61796 लाख कि० वा० घंटे विद्युत् गत वर्ष की सम्वादी अवधि में उत्पादित विद्युत् (50890 लाख कि० वा० घंटे) की अपेक्षा 21.4 प्रतिशत अधिक रही। विद्युत् आपूर्ति में सुधार होने से प्रदेश में कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन हेतु उपलब्ध कराई जाने वाली विद्युत् की मात्रा में वृद्धि संभावित है और तदनुसार प्रदेश में कृषि एवं औद्योगिक कार्यकलापों एवं उत्पादन में अभिवृद्धि होने की संभावना है।

7.3-- जनसाधारण, विशेषकर समाज के निर्बल वर्ग के व्यक्तियों के लिये राष्ट्रीय मानकों के अनुसार न्यूनतम स्तर का सामाजिक उपभोग सुलभ कराने हेतु न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का सूत्रपात किया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 6-14 वर्ष के शत-प्रतिशत बच्चों के लिये प्रारम्भिक शिक्षा, प्रत्येक ग्राम में ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वच्छता, इम्प्यूनाइजेशन, साधारण बीमारियों के निदान की व्यवस्था, सभी अवशेष समस्याग्रस्त ग्रामों में पेयजल की व्यवस्था, 1000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों को ग्रामीण सड़कों से जोड़ना, कम से कम 50 प्रतिशत ग्रामों का विद्युतीकरण, भूमिहीन ग्रामीण परिवारों को आवास निर्माण हेतु वित्तीय सहायता, 0-6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा धात्री माताओं के लिये पुष्टाहार की व्यवस्था तथा पर्यावरण सुधार सम्मिलित है। छठी योजना (1980-85) में 6200 करोड़ रुपये के कुल स्वीकृत परिव्यय में से 826 करोड़ रुपये (13.3 प्रतिशत भाग) उपर्युक्त कार्यक्रम हेतु निर्धारित किया गया है। वर्ष 1980-81 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पर 113.67 करोड़ रुपये जो कुल योजना व्यय का 11.7 प्रतिशत रहा, व्यय हुआ। वर्ष 1981-82 में इन कार्यक्रमों पर होने वाला 129.90 करोड़ रुपये का सम्भावित व्यय गत वर्ष की अपेक्षा लगभग 14.3 प्रतिशत अधिक रहा।

परिशिष्ट-1
उत्तर प्रदेश के आर्थिक क्षेत्र

आर्थिक क्षेत्र	संभलित जिले		
1-पर्वतीय क्षेत्र	* 1-अल्मोड़ा * 4-गढ़वाल * 7-देहरादून	* 2-पिथौरागढ़ * 5-चमोली * 8-उत्तरकाशी ।	3-देहरादून 6-नैनीताल
2-पश्चिमी क्षेत्र	1-सहारनपुर 4-गाजियाबाद * 7-मथुरा * 10-एटा * 13-बदायूं * 16-पीलीभीत * 19-इटावा	2-मुजफ्फरनगर * 5-बुलन्दशहर 8-आगरा 11-बरेली * 14-मुरादाबाद * 17-रामपुर	3-मेरठ 6-अलीगढ़ * 9-मैनपुरी 12-बिजनौर * 15-शाहजहाँपुर * 18-फर्रुखाबाद
3-केन्द्रीय क्षेत्र	1-कानपुर * 4-उन्नाव * 7-हरदोई	* 2-फतेहपुर * 5-रायबरेली 8-खीरी	3-लखनऊ * 6-सीतापुर * 9-बाराबंकी
4-पूर्वी क्षेत्र	1-इलाहाबाद * 4-जौनपुर / गोरखपुर * 10-आजमगढ़ * 13-बहराइच	2-वाराणसी * 5-गाजीपुर * 8-देवरिया * 11-कैजाबाद * 14-सुल्तानपुर	3-मिर्जापुर * 6-बलिया * 9-बस्ती * 12-गोण्डा * 15-प्रतापगढ़
5-बुन्देलखंड क्षेत्र	* 1-बांदा * 4-मिर्जापुर	* 2-हमीरपुर * 5-ललितपुर	* 3-जालौन

*ये सभी जनपद राज्य सरकार द्वारा पिछड़े जनपद घोषित किये गये हैं ।

Sub. Man. Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No. D-990
Date.....22.2.84

NIEPA DC



000990

पी 0 एच 0 यू 0 पी 0 - ए 0 पी 0 34 सा अर्थ एवं संख्या-11-12-82-(2812)-1983-1,400 (मैग 0) ।